an>

Title: Further discussion on the flood and drought situation in the country raised by Shri Yogi Adityanath on the 30th July, 2014 (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON: The House shall, now, take up discussion under Rule 193 – Shri Ravneet Singh

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही अहम विषय सूखे के ऊपर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने इस चर्चा की शुरूआत की थी। देश के 58 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं। देश की आमदनी का 14 प्रतिशत खेती से आता है, जो कि वैसे बहुत कम है, लेकिन इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से जो सूखे जैसे हालात बने हैं, वे बहुत दुखदायी हैं। हालांकि केन्द्र सरकार जुलाई-अगस्त के महीने में होने वाली बारिश से काफी उम्मीदें लगाई हुई है, पर हकीकत यह है कि आज भी देश में औसत बारिश 25 प्रतिशत कम है। बरसात की कमी ने फसलों की बिजाई पर सीधा असर डाला है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस खरीफ सीजन में सिर्फ 32.80 प्रतिशत क्षेत्र में ही फसलों की बिजाई हो सकी है। पूरे देश में इस साल सिर्फ 345.60 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही बिजाई हो सकी है, जबकि पिछले साल 627.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई हो चुकी थी। राज्यों की बात करें, तो महाराष्ट्र में टोटल बिजाई 134.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती थी, जबकि आज तक केवल 8.43 लाख हेक्टेयर ही हुई है। इसी तरह गुजरात में 86.8 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है, जिसमें से केवल 12.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ही इस बार बिजाई हो सकी है। ऐसे ही राजस्थान में 156 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, लेकिन आज केवल 15 लाख हेक्टेयर पर ही बिजाई हुई है। ऐसे ही हालात कर्नाटक के हैं, मध्य प्रदेश के हैं जहां अब 10 प्रतिशत ही बिजाई हुई है।

ऐसे ही हालात उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के भी बने हुए हैं, जहां खेती की पैदावार पर असर पड़ा है। इस वजह से दालों समते रसोई की सभी चीजें काफी महंगी हुई हैं। जैसे पहले प्याज ने रुलाया था, अब टमाटर रुला रहा है। दिल्ली में टमाटर 80 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर बिक रहा है। हालांकि मानसून आज भी देश में 25 प्रतिशत कम है। लेकिन कइयों ने अनुमान लगाया है कि 2012 की तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर खेती-बाड़ी की विकास दर पर एक प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। पिछले हफ्ते पूरे देश में औसतन 24 प्रतिशत ज्यादा बरसात हुई है, जो कि इस मानूसन सीजन में सबसे ज्यादा है। उससे पिछले हफ्ते देश में औसतन बारिश 15 प्रतिशत कम हुई थी। आने वाले दिनों में भी बरसात में जो औसतन कमी है, उसके पूरा होने की बात कही जा रही है। किसान का सवाल मानसून के औसत के हिसाब से बरसात होने का नहीं है, उनका सवाल है कि क्या फसलों की बिजाई के समय सही समय पर, सही मात्रा में बारिश हुई और इसका जवाब है, नहीं।

देश में इस साल एक जून से 23 जुलाई तक 45 प्रतिशत ऐसे जिले हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है और 16 प्रतिशत जिलों में बारिश नाममात्र ही हुई है। देश में देरी से बरसात आने के कारण धान और दालों की बिजाई में काफी दिक्कत आई है। इन फसलों को जीवित रखने के लिए किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

अगर हम डैम्स की बात करें तो 17 जुलाई, 2014 तक देश के 85 बड़े डैम्स जिनमें पानी 40 बीसीएम था, जबकि ठीक एक साल पहले 65.73 बीसीएम था। एक अनुमान के अनुसार पिछले दस साल की एवरेज स्टोरेज जो थी, उससे भी कम इस साल कम है। इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है।

मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब की बात जरूर करूंगा। वहां स्थिति और भी गम्भीर है। देश में कुल धान का 40 प्रतिशत हिस्सा पंजाब से आता है। यहां पर धान की बिजाई 10 जून को शुरू हो गई थी। धान की फसल के लिए पहले 20 दिन बहुत अहम् होते हैं। सही मात्रा में फसल को पानी देकर उसे जीवित रखा जाना जरूरी है। पंजाब में 1 जून से 23 जुलाई के बीच राज्य के 22 जिलों में से 11 जिलों में नाममात्र की बरसात हुई है और आठ जिलों में औसत से कम बरसात हुई है। इसलिए यह कहना कि पंजाब में सूखे जैसे हालात बने हैं, बिल्कुल ठीक होगा।

पंजाब में बहुत जरूरी है कि जून और जुलाई माह में बारिश हो। इस बार ऐसा न होने से राज्य में 65 प्रतिशत से ज्यादा जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, उन्हें धान की फसल बचाने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ा और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पंजाब सरकार ने उनकी फसल के लिए किसानों को आठ घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन वहां हालात यह हैं कि चार घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए किसानों को जेनरेटर चलाने के लिए...(व्यवधान) मैं तो किसान की बात कर रहा हूं, कुछ मांगने की बात कर रहा हूं। इसलिए डीजल जेनरेटर चलाने के लिए किसानों को लाखों रुपए खर्च करने पड़े हैं, सिर्फ सरकार की गलती की वजह से। क्योंकि समय पर न तो इन्होंने अनुमान लगाया कि कितनी बिजली हमें बाहर से खरीदनी पड़ेगी और न यह अनुमान लगाया कि कितना कोयला चाहिए। आज इसी वजह से रोपड़ और बठिंडा के थर्मल प्लांट बंद पड़े हैं। हमारे यहां भाखड़ा नंगल डैम है, जहां से काफी मात्रा में पानी पंजाब को जाता है, लेकिन वहां पानी कम होने के कारण, हमारे यहां नहरों में भी पानी नहीं है। इसीलिए कई जिलों में नहरों का पानी भी नहीं मिल रहा है।

आज पंजाब सरकार ने 2330 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग केन्द्र सरकार से की है और हरियाणा ने 800 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। यहां पर कृषि मंत्री जी बैठे हैं। इन्होंने इससे इनकार किया है, जबकि पंजाब के मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 2330 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है और इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई हैं तथा वे गए हैं। लेकिन यहां केन्द्रीय मंत्री जी का जवाब आया कि हमें पंजाब की ओर से पैसे की मांग नहीं की गई है। ऐसे ही 800 करोड़ रुपए हरियाणा ने मांगे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसी ही स्थिति 1972 के बाद वर्ष 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय देश में बनी थी। मुझे याद है कि ऐसी ही सरकार अकाली दल-बीजेपी की वहां थी और बादल साहब ने खुद पैकेज मांगा और उस समय की यूपीए चेयरमैन और हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने 800 करोड़ रुपया यहां से उस समय पंजाब को और 400 करोड़ रुपया हरियाणा को दिया। यह रिपोर्ट आपके सामने है। ...(व्यवधान) पर आज जब पंजाब में इनकी सरकार ने मांगा तो आपने उन्हें मना कर दिया।

महोदय, उस सरकार ने किसानों का 2008 में 72,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को उससे लाभ हुआ और जो छोटे किसान, एक-दो एकड़ के खुदकुशी कर रहे थे, उन्हें लाभ हुआ। यह 72,000 करोड़ रुपये माफी की विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। लेकिन आज हम बात करें तो अलग-अलग राज्यों के किसानों के नुकसान का पता लगाने के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। उस बारे में आज तक आपने कोई कमेटी नहीं बनाई। उस टाइम इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन हुआ था जो सारी स्टेट के किसानों के नुकसान का अनुमान लगा रही थी जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके।

पंजाब में पांच नदियां हैं। मैं कोई पाइंट स्कोर करने की बात नहीं कर रहा हूं। मालवा क्षेत्र रेगिस्तान बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में ही है कि बादल साहब ने 85,000 ट्यूबवैल्स जो वहां पर खराब हो चुके हैं उनके लिए आपसे 700 करोड़ रुपये की मांग की है। वहां पर पानी 400 फुट नीचे चला गया है और वह भी पीने के योग्य नहीं है। उससे कैंसर, हैपीटाइटस-बी, पीलिया होने का खतरा है। साथ ही 5 लाख से 6 लाख रुपया 400 फुट बोरिंग पर खर्च आता है जोकि दो-चार एकड़ वाला किसान खर्च नहीं कर सकता है और वह उसके लिए कर्जा लेता है। इस तरह से वह कर्जे के नीचे दब चुका है।

अगर हमें पंजाब की खेती बचानी है तो जैसे गेहूं-धान पर एमएसपी है तो मक्का, बाजरा और दालों पर एमएसपी क्यों नहीं करते हैं, जिससे किसान कम पानी से होने वाली उपज की ओर जाए। हम क्रॉप डायवर्सिफिकेशन की बात करते हैं लेकिन ग्राउंड पर ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। हमारी पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी दुनिया भर में मानी हुई है। आपको उसे आवश्यकता के हिसाब से पैसा देना चाहिए। पिछले बीस सालों में अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसा नया बीज नहीं तैयार किया गया जो कम पानी से ज्यादा पैदावार दे। प्राइवेट एजेंसीज इसमें काम करना चाहती हैं, जो हमें अच्छे बीज उपलब्ध कराएं, उन्हें हम जरूर ले कर आएं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें यह कदम उठाने जरूरी हैं। मक्का, बाजरा और दालों की एमएसपी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जैसे हमारी सरकार ने वर्ष 2009 में यही हालात थे तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो केंद्र की स्कीम जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन है, इनका उपयोग किया था। आप भी ऐसे प्लान तैयार करें। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि किसानों को ज्यादा पैदावार करने वाले बीज उपलब्ध कराएं। क्राप इंश्योरेंस को निचले स्तर तक के लोगों को उपलब्ध कराएं। जब हमें पता था कि यह स्थिति आने वाली है, बजट के अंदर पूरी तरह से डिनायल मूड में रहे हैं। यह बात नहीं मानी और किसानों की मदद के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। करोड़ों रुपयों के फल और सब्जियां हर साल खराब हो रही हैं। स्टैच्यू लगाने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमने बहुत पैसे रखे हैं, लेकिन किसान जो कि हमारी रीढ़ हैं, उनके वेयर हाउसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, उनके लोजिस्टिक के लिए हमने कोई भी फंड एलोकेट नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश में कम से कम छह जगह यह बोला कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी जिससे किसान को फसलों की लागत से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। आज पचास परसेंट तो क्या केवल पचास रुपए धान की फसल के बढ़ाए हैं जो कि केवल तीन परसेंट है और महंगाई की दर नौ परसेंट है। अगर सेविंग एकाउंट के बयाज की बात करें तो उसमें भी चार परसेंट मिलता है, तो यह केवल तीन परसेंट है।

मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार के मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आने वाले आंकड़े किसानों के लिए काम नहीं आए। उन्होंने फसलों को बचाने के लिए जो पैसा खर्च करना था जो कर्ज लेना था, वह ले लिया है लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। देश का किसान आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है। समय की जरूरत है कि केंद्र सरकार बारिश के आंकड़ों में न जाते हुए पंजाब हरियाणा के किसानों को धान पर कम से कम पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दे। साथ ही दूसरे राज्यों में भी किसानों को जो उचित मुआवजा दिया जा सकता है, वह जरूर देना चाहिए जिससे हमारा किसान खुशहाल रहे और हमारा किसान आत्महत्या करने से बच सके। अगर किसान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। आपका ज्यादा ध्यान ट्रेडर्स पर है, बिजनेसमैन पर है किसान के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। जैसे यूपीए सरकार ने किसानों पर ध्यान दिया था, उसी तरह आप भी किसानों पर ध्यान दें।

आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*SHRI M.CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM) : Hon. Chairman Sir. I thank and salute Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* for giving me this opportunity to speak in this august House. I thank the voters of my Chidambaram constituency for electing me to Lok Sabha. People of our country are affected by natural disasters like heavy rains, tsunami, cyclones, floods, earthquakes and drought like situation. There is a loss to the precious lives and property. For example; 1967- Cyclone in Tamil Nadu; 2000- Gujarat earthquake; 2004- Tsunami disaster; 2011-Thane cyclone and periodical floods are hard to forget. During 2004 tsunami, more than 10000 people died in Chennai, Cuddalore, Nagappattinam, Puduchchery and adjoining areas. Property worth many lakhs of rupees were destroyed. Tamil Nadu looked like a grave yard. A leader who claim to be the one and only leader of Tamils admitted himself in the hospital during tsunami disaster. But despite cyclone threat, within 3 hours of the disaster, Hon. Chief Minister Amma visited the tsunami affected areas and provided immediate assistance to the needy people. Hon'ble Amma even ignored the advice of high level government officers who said that it would be dangerous to go to Tsunami affected areas as the disaster threat was still pertinent. Hon. Amma protected fishermen by providing fishing boats and nets. The then US President Bill Clinton had visited the Tsunami affected areas and was lots of praise for the rehabilitation measures undertaken the State Government on war-footing basis, under the leadership of Hon. Chief Minister *Puratchithalaivi* Amma.

On 30.12.2011, Thane cyclone had struck the coastal areas of Tamil Nadu at a speed of 125 mph. The people were affected. The then State Government of Tamil Nadu demanded a grant of an aid of Rs.5000 Crore from the Union Government. The high level team sent by the Union Government had also recommended for release of the grant. But the then UPA Government, in which DMK was an ally, only provided Rs.500 Crore as against the required aid of Rs.5000 crore. The Union Government had disappointed the people of Tamil Nadu. The State Government led by Hon. Amma managed with the State funds in providing rehabilitation to the Thane cyclone affected people.

Hon. Amma is the savior of the people of Tamil Nadu. People of coastal areas of the State are affected by cyclones and sea erosion. There should be brick walls along the seashore areas of the coastal districts to prevent sea erosion and effect of fierce giant waves. Union Government should allocate adequate funds.

During the Indo-China war and Indo-Pakistan war in 1965, Hon. Amma, who was at a tender age of 16, donated her hard earned jewellery worth lakhs to the Soldiers Welfare Fund. Hon. Amma handed over them to the then Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. Hon.Amma was not into politics at that point in time. I say this because to explain the patriotism and confidence Hon'ble Amma possess for the people of this great country. We should be united as Indians and we should express our concern for the fellow Indians as well. The National Disaster Management Authority should be strengthened with allocation of adequate funds and whenever natural disasters take place, immediate relief and rehabilitation measures should be undertaken on war-footing basis. There was a drought like situation in Tamil Nadu during 2012. Paddy and others crops were destroyed due to drought. The Tamil Nadu Government had declared all districts excluding Chennai as drought affected and provided a relief grant of up to Rs.15,000/- per acre of agricultural land. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma is the only Chief Minister in this country who had provided relief grant for drought affected people. Excess river water drains into sea. This can only be prevented by interlinking of rivers. Through this, we can manage floods and also help the drought affected states of the country. Desalination plant is functional in Tamil Nadu. Adequate funds should be allotted for implementing this scheme throughout the country. Union Government should come forward to implement this scheme in various parts of the country.

In my Chidambaram constituency in Ariyalur, Jayamkondam a lignite corporation should be set up to provide employment to the people. Farmers had given their lands with a hope that their livelihood would be protected. This scheme has not materialized and no compensation was provided to the farmers who gave their lands. Their lives are at stake. Union Government should set up a lignite corporation in this area and generate employment to the people of my constituency.

Tamil Nadu is the most affected State due to floods, cyclones, heavy rains and sometimes drought. Union Government led by Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi should allocate adequate funds to Tamil Nadu for developing infrastructure and to tackle natural disasters. International Tsunami Warning Centre was set up in the year 1963. There are 26 member countries in this organization. India should also become a member of organization so as to protect the people from Tsunami like natural disasters. Sea erosion should be controlled. The fierce giant waves should be tackled by provision of requisite floating equipments and gadgets. Chidambaram, Buvanagiri and Ariyalur are the coastal districts in my constituency. Fishermen and people are frequently affected by giant sea waves. Brick walls should be constructed along the coastal areas to protect the people of my constituency. I also urge that the Union Government should allocate adequate funds for the State of Tamil Nadu so that the welfare measures undertaken by Hon. Amma could be continued. Tamil Nadu should become a role model for the country. I request to allocate additional funds for Tamil Nadu.

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): Thank you, Mr. Chairman, for giving me the opportunity to speak in this august House on the debate "Flood and Drought".

India is having a varied situation in different parts. Sometimes, in the same year, and simultaneously, we face 'drought' in one part, and 'flood' in another part. So, it is very difficult to control this situation. Water not only gives us life, but also it takes away life from us as well. It is only the amount that matters: the abundance or the absence. This year we are having the problem of drought. We received lesser amount of rainfall this year -- 56 per cent deficit in Central India, and 20 per cent deficit in West Bengal. The eastern part is in a better situation and we are not severely affected this year. However, in West Bengal, the cultivation of jute is under threat. During the months of April-May, the situation worsened. Therefore, I would request the Minister to take necessary steps so that the farmers can at least get some benefit.

Recently, there was an MoU between the Central Groundwater Board and the Indian Institute of Remote Sensing to survey the situation of water Table status of lands. And that is restricted to northern India. I would request the Minister that the MoU between these two organizations should be extended to cover the entire country so that the benefits could be extended to the farming community of the country as a whole.

This year, the drought situation is alarming. It is expected that El Nino effect may hit us soon. So, we are facing a lot of problems. If we categorize these problems, crop management stands out to be an important area. In crop management, what is urgently required is the introduction of crop diversification. We are traditionally growing rice, wheat, etc., but it is time to adopt different types of crops so that the loss being suffered by the farmers could be minimized. Among the legume crops, *arhar, til, castor, soyabean*, are some of the crops that can be grown with less amount of water.

Another important factor is the water management. Day by day, we are facing water scarcity. This is a major problem which we will face in the years to come. For this, better management practice of water is required. We need to grow those crops which require less amount of water. We need those crops which have deep roots so that they can tap water from the deeper region of the soil. The research must be directed to those areas where less water consuming crops can be grown satisfactorily to cater to the needs of the farming community of this country.

Now, I come to the institutional support which is extremely required in the form of credit facilities. These credit facilities can be extended to the farming communities. Sometimes, huge amount of investment is required in the allied sectors and obviously the crop insurance is one among them. These are some of the major areas that need to be addressed and should be taken into consideration by the Ministry.

There is one institute situated at Hyderabad. Its name is Central Research Institute for Dryland Agriculture (CRIDA). It is situated only at Hyderabad. It has no other branch in other parts of this country. I urge upon the Minister to look into the matter and set up different branches, offices and research institutes under this premier institute in different parts of this country where similar kind of atmospheric and climatic factors prevail. For example, there are some districts like Purulia and Bankura which are dryland and where there is water scarcity. The Government can set up a centre of CRIDA so that the farmers of that area can utilize the expertise generated from these centres.

Now, I come to another important aspect that is about micro irrigation system. What we are using right now is the flood irrigation system, pitcher irrigation system. But the micro irrigation system is one of the major ways to mitigate the problem. If we introduce this micro-irrigation at large scale, then we can make use of water efficiently and we can save water for our future generations.

The Damodar Valley Corporation is another important project of the Government of India where dredging has not been done for the last 66 years. Just after Independence, the dam was constructed, the project was launched and still dredging was not adopted to make recovery. If this siltation is not taking place, then the capacity of the reservoir becomes more but due to repeated siltation, the problem aggravates. Due to this, floods are occurring in many parts of West Bengal and adjacent States frequently. I urge upon the Minister to look into the matter so that at least the dredging by DVC takes place.

In my constituency, there are rivers namely Ichamati and Churni. Every year, the people of this area are affected by floods. If the Government is taking necessary steps to dredge the river, then the people of the area will be benefitted more.

With these few words and with the expectation that the Ministry will look into the matter, I am concluding my speech.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to you for permitting me to speak. India is strongly affected by two major hydro-meteorological disasters, namely, drought and flood. Drought is a perennial feature. About 16 per cent of India's total area is

drought prone and approximately, 50 million people are annually affected by droughts. India is vulnerable to drought in about 68 to 70 per cent of the total sown area.

As per the report of the National Disaster Management Authority, 2012, in India about 49.81 million hectares, that is, about 15.2 per cent of total geographical area, is flood prone and on an average 10 to 12 million hectare is actually affected every year causing a range of miseries. Simultaneously, occurrence of flood in one part and drought in another part of the country is quite common.

As you know, *The Times of India,* the day before yesterday made an observation that the deficit compared to the national average of monsoon, is 24 per cent at national level. But in some States like Haryana and the UT of Chandigarh, the deficit is 53 per cent; in Punjab, it is 58 and so on. Like this, in around 15 important States, the deficit is more than 45 per cent. This is the position of the country as on today.

Secondly, I am not quoting the minutes of the meeting of the Crop Weather Watch Group held on 11 th July, 2014. It is said that out of 617 districts, 67 districts, that is, 11 per cent received excess rainfall; 112 districts, that is, 18 per cent received normal, 224 districts, that is, 36 per cent received deficient, 210 districts, that is, 34 per cent received scanty rainfall and four districts, that is, one per cent received no rain during the above period. This is the position.

In that report, as per the latest information available on sowing of crops, around 24.3 per cent of the normal area under *kharif* crops has been sown up to 11.7.2014. And area sown under all *kharif* crops taken together has been reported to be 256.61 lakh hectares at all-India level as compared to 502.17 lakh hectares in corresponding period of last year. This is the comparison. The Government has given this report. As per *The Deccan Herald,* 85,000 people were affected in Odisha flood as per the news of 30th July, 2014. Odisha flood affected two lakh people and 431 people are missing. This is the report of the PTI. Odisha flood kills 33 people on an average every year. In this context, I would like to draw your kind attention to my State Odisha.

Amongst all the natural disasters afflicting the State, floods are the most frequent and devastating. About 80 per cent of the annual rainfall in the State is concentrated over a short monsoon period of three months. While the coastal plains are very flat, the slopes in the inland are precipitous. This leads to heavy siltation, flash floods and poor discharge of flood waters into the sea, and thus embankments are breached with alarming frequency.

Damages due to floods are caused mainly by the Mahanadi, the Brahmani and the Baitarani, which have a common delta where floodwaters intermingle; and, when in spate simultaneously, wreak considerable havoc. The problem is further accentuated when flood synchronises with high tide. The silt deposited constantly by these rivers in the delta area rises the bed levels and the rivers often overflow their banks or break through new channels causing heavy damages. Flood and drainage congestion also affect lower reaches along the Subarnarekha River. Hon. Chairman, Sir, Subarnarekha belongs to your Constituency. Rivers Rushikulya, Vansadhara and Budhabalang also cause floods. Nearly 80 per cent of the rainfall in the State occurs within three months, which also coincides with the main cropping season.

The normal rainfall in the State, calculated on the basis of the average of 50 years of annual rainfall, from 1901 to 1950 was 1503 mm with 73 rainy days. The rainfall pattern, however, started showing a declining trend over the last 50 years. The declining and fluctuating decennial variation can be clearly seen if one goes through the report in detail.

The impact of the drought is mainly felt in agriculture, resulting in loss of production. Besides crop loss, droughts also create problems of irrigation, drinking water, loss of employment, scarcity of essential commodities, migration of farm labourers, increasing rural indebtedness, land and asset alienation, etc. People who get worst affected are small and marginal farmers, and agricultural labourers.

Odisha was hit by the worst of cyclones Phailin which made landfall in the southern part of the State on October 12, 2013. Cyclone Phailin coupled with another spell of high floods occurred simultaneously affecting severely the lives and properties of people of that region. Although the Government of Odisha - through adequate preparedness, proper planning and execution - could restrict the loss of lives, there was severe damage to both public assets and private properties. The Government also ensured delivery of timely assistance to affected people.

Our hon. Chief Minister, my leader Navin Patnaik, wrote a letter to the then UPA Government seeking assistance of Rs.5832.5 crore. The then Home Minister assured, while he was visiting Bhubaneswar on a government programme, to provide Rs.1,000 crore. However, unfortunately only Rs.460.3 crore was sanctioned. Sir, the hon. Minister is sitting here. She knows the quantum of devastation caused in 2013. I would request the hon. Minister through you, Sir, to ensure that adequate fund are released to the Government of Odisha so that we can have our due.

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : सभापति जी, नियम 193 के अंतर्गत बाढ़ और सूखे से देश में जो हालात हैं, उस पर चर्चा में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज देश में सब तरफ बाढ़ की बातें बताई जा रही हैं लेकिन मेरे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन में पूरा सूखा है। दो साल पहले भी बहुत बड़ा सूखा पड़ा। किसान बेहाल हैं। दो साल पहले भी महाराष्ट्र में सूखा था, उस वक्त भी सरकार की तरफ से बहुत सारे किसानों को मदद दी गई, चारा छावनियाँ लगाई गईं, पानी के टैंकर लगाए गए। उसके बावजूद इस साल भी वही हालात मराठवाड़ा रीजन में हैं। सूखे के कारण अभी दोबारा बुआई की गई, दोबारा बीज बोया गया लेकिन दोबारा बुआई करने के बाद भी फसल नहीं पैदा हुई। किसानों पर यह बहुत बड़ी आपत्ति आ चुकी है। मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि किसान आज जिस हालात से गुज़र रहे हैं, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी की है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि आप उन किसानों के लिए अच्छे से अच्छा पैकेज देकर उनको उस हालात से बाहर निकालें।

महोदय, जब बाढ़ आती है तो गाँव बहकर जाने जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन जब सूखा होता है तो पीने का पानी भी किसानों और जानवरों को नहीं मिलता है। ऐसी हालात वहाँ की हैं । वहाँ कुछ नये डैम के लिए स्वीकृति है लेकिन वहाँ गवर्मेंट उसको मान्यता नहीं देती और मान्यता नहीं होने के कारण वे डैम नहीं होते। मैं सरकार से यह निवेदन करूँगा कि वहाँ के भंडारण अगर बन जाएँ तो वहाँ के जानवरों और किसानों के लिए पीने के पानी का मसला भी हल हो जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ के किसानों की ज़मीनों को भी अच्छा पानी मिलेगा और वहाँ का सूखा दूर होने में मदद होगी। इसके साथ ही मैं सरकार से गुज़ारिश करूँगा कि पिछली बार जो अनियमित बारिश हुई और जो ओले पड़े मार्च महीने में, उस वक्त भी किसानों को मुआवज़ा देने की कोशिश की गई। बड़े-बड़े किसानों को तो मुआवज़ा मिल गया, लेकिन जो हालात से मजबूर है, जिसको सही

वक्त पर मिलना चाहिए, उन किसानों को मुआवज़ा नहीं मिला। उसमें भी वहाँ के जो काम करने वाले गवर्नमैंट के नीचे लैवल के कर्मचारी हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों से लेनदेन करते हुए, कुछ पैसे लेकर वहाँ के जो ज़रूरी किसान हैं, उनको बाजू में रखा और जो इनको पैसे देता है, उन किसानों को वहाँ पर फायदा दिया गया। मैं 377 के तहत यहाँ पर मुद्दा उठा चुका हूँ और उसके बारे में मैंने सरकार से अपील की है कि उसकी तहकीकात करे, जिन किसानों को मुआवज़ा नहीं मिला, उनको मुआवज़ा देने की कोशिश करे। वैसे हालात अभी न हों। अभी दोबारा बुआई होने के बाद भी अगर किसानों को कुछ आस नहीं है, धान नहीं आता है तो अभी दूसरी बार की जो भी बुआई हुई है उसमें भी अगर किसान परेशान हैं तो उसको कुछ अच्छा पैकेज देना चाहिए। उसके हालात को देखते हुए, उसकी मजबूरी को देखते हुए उसकी मदद करना सरकार का काम है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, आज के हालात में किसानों को जो खाद का बैग दिया जाता था, जो 400-500 रुपये में खाद का बैग दिया जाता था, आज वह खाद का बैग 1200-1300 रुपये में दिया जाता है। लेकिन उसके साथ किसानों को जो माल का भाव मिलना चाहिए, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। आज कपास का भाव जो मिलना चाहिए, आज सरकार 4000 रुपये से लेती है जबकि वह 10000 रुपये से भी ले तो उसको फायदा नहीं मिलता है। सोयाबीन की हालत वही है। जो 3000 रुपये से सरकार सोयाबीन लेती है, पिछली बार 3000 से लिया, इस बार 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मेरी सरकार से विनती है कि आप उसका जो भी बाज़ार भाव या मूल्य ठहराते हैं, उस वक्त उन किसानों के क्या हालात हैं, वह देखने के बाद उनका सर्वे करके ठहराना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई न कोई बैठ जाता है। वह सरकार को बता देता है कि इस तरह का भाव होना चाहिए, आपकी सरकार फाइनल कर देती है। मेरी आपसे विनती है और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी विनती करूँगा कि किसानों के हालात देखते हुए आज हम बोलते हैं कि भारत देश किसानों के ऊपर चल रहा है। 70 फीसदी लोग किसानों के भरोसे चलते हैं, लेकिन यह सब होने के बावजूद भी किसानों का ख्याल नहीं किया जाता, उनकी तरफ दुर्लक्ष किया जाता है। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि किसानों का जो भी धान है, उसका भाव अच्छी तरह से मिलना चाहिए और किसानों के जो हालात है, वह सुधारने के लिए हमें अच्छे कदम उठाने चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपने दो शब्द पूर्ण करता हूँ।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Discussion under Rule 193 on the flood and drought situation in the country, which is of prime importance.

India is vulnerable to a variety of natural and man-made disasters. Strong and effective emergency management has been a felt need in all corners of the world. Effective policies play a vital role in mitigating the impact of disaster and reducing the likely losses of life and property.

Poverty, vulnerability and disasters are linked. Often it is the poorest that are the worst affected and suffer the most. Their poverty makes them more vulnerable. Their capacity to cope with disasters and recover from their effects is constrained by their lack of resources. But if those people are sufficiently prepared and have the capacity to cope and recover quickly, droughts, floods and even earthquakes need not be a disaster.

In rural areas, Panchayati Raj institutions are democratically decentralised bodies that can display tremendous potential in disaster management as they are closer to the scene and have a better knowledge of local resources and weaknesses. However, their role has been limited mostly to the response phase of any disaster. I would request the Government to totally involve Panchayati Raj institutions in disaster management.

Sir, disaster management can be classified into two types; natural calamities and man-made calamities. Natural calamities are cyclones, earthquakes, floods, tsunamis, landslides, avalanches (fall of snow slides), volcanic eruptions, drought etc. Man-made calamities are road and rail accidents, air and sea accidents, industrial accidents, nuclear disasters, biological disasters (they come from bio-waste if it is not properly treated), epidemic outbreaks, chemical disasters (they mostly occur in industries) - Bhopal gas leakage tragedy is one of the best examples of this - Oil fires, coal fires, forest fires, oil spills etc.

Landslides are common in the lower Himalayas. Rising deforestation further aggravates the severity of landslides. Parts of the Western Ghats also suffer from low intensity landslides. Avalanches are common in Kashmir, Himachal Pradesh and Sikkim.

Floods are the most common natural disaster in India. Floods kill thousands and displace millions. Excess, erratic or untimely monsoon rainfall may also wash away or otherwise ruin crops. Almost all of India is flood-prone and extreme precipitation events such as flash floods and torrential rains have become increasingly common in central India over the past several decades coinciding with the rising temperatures.

Early warning system saves lives. Severe monsoon rain causes floods. When this is forecasted timely, early warnings may be delivered and people can be evacuated in such situations so that loss of life and property can be reduced to the best extent possible. If early warning system is best utilized, everyone will be prepared to face any eventuality. In such a way, Tsunami Warning System is also developed after the devastation it caused during 2004. These early warning systems are really worked out throughout the world.

Uttarakhand tragedy is the best example of natural calamity. In June 2013 a multi-day cloud burst in Uttarakhand caused devastating floods and landslides in the country's worst natural disaster. As per official records of Uttarakhand Government, more than 5700 people were presumed dead and among them, 934 were local residents. Destruction of bridges and roads left about one lakh pilgrims and tourists trapped in the valleys of Char Dham pilgrimage. The Indian Air Force, the Indian Army and para-military troops were put in relief operations of the flood ravaged areas.

From 14 to 17 June, 2013, Uttarakhand and the adjoining areas received heavy rainfall which was about 375 per cent more than the benchmark rainfall during a normal monsoon. This caused melting of Chorabari Glacier at a height of 3800 metres and eruption of the Mandakini River which led to heavy floods. Residents and tourists in Kedarnath left with no time to move to safer areas which resulted in loss of thousands of lives and properties. The Government was charged with being too slow in rescuing and relocating the people.

As much as 90 per cent of the other smaller tributaries could be affected the same way. My suggestions in order to prevent these types of tragedies are – grow more trees on the hills to maintain the ecological balance of the region and save the hills from pollution and the rivers from contamination. Less number of vehicles should be allowed thoroughfare on the hill areas to avoid pollution and to maintain ecological balance. A limited number of projects should be sanctioned for infrastructures like roads, buildings and other constructions. It should be allowed by the competent authority only after a scientific study on hill environment. No construction should be allowed near river banks. There should be accurate weather forecasts. Proper medical facilities should be ensured at tourist locations. Disaster management groups should be established. Usage of plastic by the tourists should be regulated. Proper cleanliness should be ensured at tourist destinations. Suitable steps should be taken to maintain serenity of the place. Traffic regulations should be imposed to avoid traffic jams.

Now I would like to speak about the man-made disaster which occurred in my State, Andhra Pradesh. A gas pipeline of GAIL leaked at Nagaram village of East Godavari District, which is another man-made calamity and because of this pipeline leak, Nagaram village caught fire killing 22 people and leaving 20 people severely burnt on Friday, the 28th June 2014. It happened in my native District.

The blast occurred in the pipeline carrying gas to Lanco Power Station. The pipeline was maintained by GAIL India. The fire broke out between 5.30 a.m. and 5.45 a.m. on the pipeline running through Nagaram village. The gas leak seemed to have been taking place for the last four days prior to the blast. Since the gas was odourless, its leakage was undetected until a tea stall owner by name Vasu, lit a stove early morning to prepare tea for a family. His stall was barely 200 metres away from the place where the gas leaked, leading to a blast followed by large balls of fire.

HON. CHAIRPERSON : Now, nothing would go on record. Shrimati K. Kavitha to speak.

(Interruptions) â€¦[*]

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Sir, I thank you for this opportunity.

While this august House is discussing the flood and drought situation of the country, I would like to bring to the attention of the House a very important issue. Natural flood/drought is one aspect and the other face of the same coin would be man-inflicted flood. We had such a situation in the erstwhile Andhra Pradesh when Telangana and Andhra Pradesh were together.

In 2009, we had a man-inflicted flood in Kurnool which had swept away many villages and we had a very serious situation. This was caused because one river basin water was diverted to other. The Krishna river water was diverted to Penna river basin and since the Central Water Commission does not have proper control of all the water projects that are being constructed in various States, I believe, this situation had arisen. We were thinking that only God and nature can, in fact, give droughts and floods but after looking at the situation we understand now that the Central Water Commission also is capable of doing that. I would like to draw the attention of the hon. Minister who is present here to two issues.

My first point is with regard to the Polavaram project. Now that this project has been given a national status, we would like to bring it to the notice of the hon. Minister that while preparing the DPR, the flood level of Godavari was calculated only at 30 lakh cusecs but now after fresh records and the latest data the flood level is at 50 lakh cusecs; but that is not noted and permissions have been given. Tomorrow if, because of global warming, because of various other situations arising, something goes wrong, then Godavari will be flooded and if the flood level goes up to 50 lakh cusecs, then God forbid it will be a very serious incident and in that event even a big city like Rajamundry could be wiped off the face of this earth. This is a very serious issue and I believe that the hon. Minister will pay attention to it and also have a re-look into the permissions of the Polavaram project. Since the Government has accorded it the national status, the responsibility of any life lost because of this negligence will directly fall on the Central Government. That is one aspect.

Sir, while giving permission to projects like this, none of the States is consulted. The States of Andhra Pradesh, Telengana, Odisha and Chattisgarh are the four States which would be directly affected by this project, but none of the Chief Ministers of these four States was called and consulted. No meetings are being held. No proper study has been made. This will ultimately lead to a man inflicted flood which is really not a good practice.

The other issue that I wanted to bring to the notice of the hon. Minister of Water Resources is about the redistribution of the water of the river Krishna among the four States. The time of the Tribunal has been increased by another two years. I will hope and pray that the Central Government would use the latest technology available. It could be the GIS or the SONAR technology because the upper riparian States are storing water in small projects which do not have permission and they are changing the natural course of the river and storing water because of political obligations. But if a proper study is not done lower riparian States are going to suffer, not only suffer but if at all any unwanted monsoon or serious rainfall takes place, it will ultimately result in flood. So, I hope and pray that the Central Water Commission and the Ministry of Water Resources will pay serious attention to the Krishna Water Distribution and also use the latest technology possible and do justice to all the States.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, thank you for giving me this opportunity. When we are discussing our strategies and policies for management

of flood and drought situation in our country, we should take into account the fact that our country is having diverse climatic condition, just as we are having a diverse culture.

Sir, as predicted, this year's monsoon has been weak and there has been a decline in the accumulated rainfall for the country as a whole as compared to the last year. The decline is 43 per cent. It is an alarming situation. Out of 617 districts, 434 districts have received deficient rainfall.

The Central Water Commission's data shows that 85 reservoirs in our country are having 66 per cent less storage as compared to last year and the storage is 10 per cent less than the normal storage capacity. This will have serious implications for agriculture. The area sown under Kharif crop cultivation has come down from 500 to 256 lakh hectares. This shows that there is almost a 50 per cent decline of area sown under Kharif crop cultivation. There is a danger of sharp fall in agricultural production; there is a danger to our food security and there is also a danger of further worsening of the inflation in our country. Inflation is already on the rise and I do not want to go into the details of inflationary situation in our country.

Sir, in this situation the Government should intervene with a series of policy instruments. Unfortunately, the Government is reluctant to initiate necessary policies to help farmers and to sustain agriculture.

I would like to make some suggestions in this regard. The Government should enhance agricultural extension services and make seeds, fertilisers, and other things available at affordable prices. The most important thing is, they should ensure cheap agricultural credit and institutional credit to farmers. According to the records of the National Crime Bureau, a farmer commits suicide in every 31 minutes. This has been continuing for the last one decade. This situation is going to be further grim with weak monsoon and less rainfall.

So, I would like to urge upon the Government to immediately declare a moratorium on agricultural loans and, as a contingency plan, the Government should announce interest free loans to farmers. I do not know whether the Government will do it or not. But I would like to urge upon the Agriculture Minister, who is a good Minister and a very good friend of mine, to take these aspects into account.

The National Farmers Commission headed by the famous agricultural scientist, Dr. M.S. Swaminathan had recommended that agricultural loan should be made available to farmers at not more than four per cent rate of interest. The Government has not yet accepted that recommendation of the National Commission on Farmers. Instead, the Government is moving in the wrong direction. I am saying this because the Ministry of Consumer Affairs has recently issued a guideline forbidding the States to give bonus over and above the Minimum Support Price. I would like to urge upon the Government to withdraw that guideline and not to prevent the States from giving bonus over and above the MSP.

Finally, coming to my own State, Kerala, Kerala is having a peculiar geographical pattern and landscape and because of this, we experience sudden floods immediately followed by severe drought situation. This is an extraordinary situation. Because of its landscape, there is heavy rainfall, water flows fast down into the sea and within three to four days, there will be shortage of drinking water and within weeks, there will be a drought situation. When the Central team arrives Kerala to assess the damage caused by floods, they will not see any damage caused by floods because, by that time, drought might have started. This sort of a situation is prevailing there.

Secondly, Kerala is one of the few States which receives both South-West monsoon and North-East monsoon. This aspect also should be taken into account. The North-East monsoon starts from the month of October onwards.

Thirdly, Kerala is a State which is having one of the longest coastline in our country. Sir, there the groundwater level is increasingly depleting. That aspect is also there and we experience frequent landslides especially during monsoon. This is peculiar to Kerala. I would like to request the hon. Minister to have a relook into the guidelines and criteria for the central assistance given as compensation to natural calamities.

Finally, there is a long pending demand that there should be a unit of National Disaster Management in Kerala. Since Kerala is very sensitive to natural calamities and we are lacking trained personnel and mechanism to address natural calamities, I would again like to make this demand, please take steps to set up a unit of National Disaster Management in Kerala.

With these words, I would like to conclude.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me a chance to participate in the discussion on the flood and drought situation in our country. India has been the victim of various natural disasters in the recent past causing extensive damage to life and property. The east coast in general and the coast of Andhra Pradesh in particular, has suffered various natural disasters due to three cyclones, namely Phailin, Nilam and Laila. It happened in a very short span of time causing endless destruction of live stocks, properties, and human lives. Not much has been done either by the Central Government or by the State Government to help the affected people. Though the El Nino condition is easing out in the country, there is a drought like situation in various parts of the country.

I would like to bring to your notice that as on 29th July there is a 25 per cent deficiency in the average rainfall of the country. The highest deficiency is in Punjab with 63 per cent. There is 46 per cent deficiency of rain in Telangana, our brother State; and 32 per cent deficiency of rain in my State of Andhra Pradesh.

Two-thirds of our people are dependent on agriculture. I would like to bring to your notice that only ten per cent of the people who are suffering due to flood and drought are getting some sort of relief from the Government. This is one of the reasons as to why the farmers are getting into the debt trap. Moreover, only 25 per cent of the people get access to institutional credit. There are various insurance schemes which are available to the farmers. But less than 15 per cent of the land, which is cultivated, is covered by various insurance schemes.

Out of 198 million hectares of gross sown area in the country, only 25.69 million hectares of land is covered by the insurance schemes. There

are a lot of complaints regarding the settlement process of the insurance claims. There is a very serious complaint that it is cumbersome and tedious. Most of the people do not get the claims in time.

Just to explain the intensity of the drought situation, I would like to give an example of my constituency, Rajampet, which is part of Andhra Pradesh and which is in the drought-prone area of Rayalaseema. The ground water level, which was 300 or 500 feet below, has currently reached the level of 1,200 feet. Though this is not potable, people are forced to drink this water.

We are talking of price rise of potatoes and tomatoes, but today in my constituency we are talking of price rise of water. Each pot of water costs Rs. 5 in my constituency. In the major municipalities like Punganur and Madanapalli, we are getting water only once in fifteen days. This is really pathetic.

All Governments are talking of creation of employment. I would like to bring to your notice that lakhs of people from my constituency are going to nearby cities as labourers. Even people owning five to ten acres of land are going to other areas as labourers. This is a pathetic condition to which our people of Rayalaseema are subjected to. The condition has gone from bad to worse by the time.

Through you, Mr. Chairman, I would request the Government of India to appoint a high powered committee to study the effectiveness of various relief and rehabilitation programmes in the country so that each and every one who is affected can be helped.

Through you, Mr. Chairman, I would request the Finance Commission to consider transfer of higher resources to States that are regularly affected by the cyclone, flood and drought.

I thank you once again for giving me this chance.

HON. CHAIRPERSON : Shri Nandkumar Singh Chouhan – not present.

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): Hon. Chairman Sir, I rise to speak on the important issue of 'Drought and Floods' under Rule 193.

Sir, several areas in Punjab are in the grip of severe drought. Standing crops have dried up. Punjab contributes 40% of the paddy crop in the central pool. As the rains have played truant, the paddy crop has been badly affected in Punjab. The farmers have found themselves at the receiving end.

Sir, agriculture is the mainstay of Punjab. It is the backbone of Punjab. During times of crisis, the farmers in Punjab even mortgage the jewellery of their wives to save their standing crops. So, the drought has wreaked havoc in Punjab. The AI Nino factor has resulted in a weak monsoon.

Sir, on the other hand, there is an apprehension that if monsoon picks up later, it may result in torrential rains in the countryside and on the hills. This will result in the flooding of rivers in Punjab. The swollen rivers will breach their embankments. We have seen this in the past. Large areas are inundated. People are marooned. Standing crops are destroyed. Cattle are washed away. Sir, the farmers must be adequately compensated. If paddy crop of the farmers is destroyed in one acre, it entails a loss of around Rs.one lakh to the farmers. Hence, the Government must grant a compensation amount of at least Rs.50,000/- per acre to the affected farmers.

The Central Government must provide relief and succour to the farmers affected by floods or drought. Adequate funds should be made

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

available to the State Government so that the farmers are compensated in time. The State Governments must also be granted the financial power to draw the amount in case there is a breach in the embankment or if roads are washed away. It should be left to the wisdom of State Government how it chooses to utilize this fund for the affected people.

Sir, my constituency Ferozepur shares a 150 kms long border with Pakistan. On one side flows river Ravi whereas river Sutlej flows on the other side. This area is frequently ravaged by floods. It results in washing away of school buildings and roads. Drinking water becomes a casualty. A special fund is needed for the affected people of my constituency Ferozepur.

Chairman Sir, in the Malwa region of Punjab, the groundwater level has dropped further. Nowadays, boring work has to be done till a depth of 400 to 500 feet to get water. About 85,000 tube-wells have gone dry in this area. Our Hon. Chief Minister Sardar Badal has urged the Central Government to immediately release adequate funds so that the affected farmers are compensated at the earliest. Sir, these are small and marginal farmers who need to be taken care of. Sir, the districts of Muktsar, Ferozepur, Fazilka, Faridkot etc. have also suffered due to hailstorms etc.. So, funds should be release for this purpose also. Chairman Sir, the canal-water system in Punjab is a legacy of British times.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, at that time, only 50% of the area in Punjab was under agriculture. However, nowadays, 95% land in Punjab is cultivable. So, the canal system needs to be revamped keeping in view this fact. More water should be released for irrigation to the farmers. Sir, in the progress of farming and farmers lies the progress of the country.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I have a long list of speakers to speak on this discussion under Rule 193. Those who want to lay their speeches, they can lay the same on the Table of the House. It will be treated as part of the proceedings.

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा) : सभापति महोदय, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ने लगा है। अलनीनो इफैक्ट से प्रशांत महासागर में पानी का तापमान बढ़ा, उसके कारण भारत में भी उसका प्रभाव हमें इस वर्ष देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसका पूर्वानुमान बता दिया था कि कहीं सूखा पड़ेगा और कहीं बहुत अधिक वर्षा होगी। जहां सूखा पड़ेगा, वहां उसका प्रभाव समाज और किसान पर पड़ेगा। जहां अधिक बारिश होती है, उसका प्रभाव और नुकसान भी सर्वाधिक किसान को ही उठाना पड़ता है। आज पूरे भारत वर्ष में कुछ इलाकों में बहुत अधिक सूखा है, बारिश का अभाव है और कुछ जगह पर अधिक वर्षा हुई है।

सभापति महोदय, मेरे मध्य प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं जहां पर कम वर्षा हुई है और कम वर्षा के कारण वहां के सारे किसान आज परेशान हैं। मध्य प्रदेश का दतिया, धार, सागर, विदिशा, रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर, गुना, सीधी, शाजापुर, आगर, मालवा, देवास, अशोक नगर, नीमच, सतना, दमोह, छत्तरपुर, श्योपुर, रतलाम, मंदसोर, ढिंढोरी, ग्वालियर, पन्ना, शहडोल और उमरिया कम वर्षा से प्रभावित जिले हैं। यहां सूखे का प्रभाव है। इस कारण यहां के किसानों की फसलें खराब हो गयी हैं। कई जगह बोये हुए सोयाबीन का बीज तक नहीं निकल पाया। यह स्थिति सूखे के कारण बनी है। वहीं पर मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां तूफानी बारिश हुई, आंधी के साथ बारिश हुई जिसमें बेतूल, बुरहानपुर, हरदा और खंडवा जिलों में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी। वहां ताप्ती नदी के साथ-साथ जिले की सारी नदियां उफान पर थीं। तूफानी बारिश, हवाओं के साथ जो बारिश हुई, वह मैंने बुरहानपुर जिले में कभी नहीं देखी। वहां पर 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बुरहानपुर जिले में केले की फसल तबाह हो गयी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला बुरहानपुर जिले में पैदा होता है। एक केले के पेड़ को फलदार पेड़ बनाने तक 69 रुपये का खर्च आता है। ये भारत सरकार के हार्टिकल्चर डिपार्टमैंट के आंकड़े हैं। आज वहां केले की फसल का नुकसान हुआ है, उसका अनुमान हम यहां बैठकर नहीं लगा सकते। मैं तीन दिन तक पूरे बुरहानपुर जिले में घूमा हूं और एक-एक खेत तक गया हूं। हर किसान की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा है, अतिवृष्टि के कारण, तेज हवा के साथ जो बारिश हुई, इसके कारण अरबों रुपए के केले के फसल का नुकसान बुरहानपुर जिले में हुआ। किसान का जो भी नुकसान होता है, चाहे वह सोयाबीन का हो या केले का हो, उस नुकसान से बचने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना तो लागू की गयी, लेकिन उस राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ हमारे किसानों को नहीं मिल पाता है। इसे व्यावहारिक बनाने की बहुत अधिक जरूरत है। यह राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, एग्रीकलचर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से किया जाता है। इसको व्यक्तिगत दृष्टिकोण में न रखते हुए, क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रखकर यह योजना बनायी गयी। " न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। " यह हालत किसानों की हो जाती है। व्यापक दृष्टिकोण रखकर जो बीमे का आकलन किया जाता है, उसके कारण केला उत्पादक किसानों से हर साल बीमे की प्रीमियम कंपलसरी कटती है। सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, एक केले के पेड़ को फलदार बनाने में 69 रुपये का खर्च आता है तथा दो सौ से ढाई सौ रुपए का एक पेड़ का फल बनता है। बीमा कंपनी लगातार केले के फसल का बीमा काट रही है। जो भी लोन उठाता है या कर्ज उठाएगा, चाहे वह राष्ट्रीयकृत बैंक से उठाये या कौपरेटिव बैंक से उठाये, यह नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की बीमा का किस्त कटाना कंपलसरी हो गया है। प्रीमियम कटने के बाद केला उत्पादक किसानों को आज तक एक रुपये का भी इंश्योरेंस नहीं मिला है। यह किसी भी फसल के किसानों को नहीं मिला है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस फसल बीमा योजना को व्यावहारिक बनाया जाए। यह जब व्यावहारिक बनेगी, तब बनेगी, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से मेरे यहाँ जो केले की फसल बर्बाद हुई है, उन केला उत्पादक किसानों को जिन्दा रहने के लिए केन्द्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा है। मध्य प्रदेश की सरकार तो मदद कर रही है। जब-जब प्राकृतिक आपदा आयी है, तो चाहे वे सोयाबीन उत्पादक किसान हों, गेहूं उत्पादक किसान हों या अन्य किसान हों, उन्हें आरबीसी के तहत सहायता दी गयी है। लेकिन वह सहायता बहुत कम मात्रा में होती है और केले जैसी फसल के लिए आरबीसी के तहत प्रदेश सरकार जो देती है, वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान होती है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि इस बार हमारे यहाँ के केला उत्पादक किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर सहायता का हाथ आगे बढ़ाएं और मेरे यहाँ के केला उत्पादक किसानों को आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए दोनों सरकारें सहयोग करें, मैं यह अनुरोध करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, हमारे बुरहानपुर जिले में बारिश के कारण लगभग एक हजार मवेशी 24 घंटे की तेज वर्षा में निमोनिया के कारण मर गये। खुले में तेज बारिश उनके ऊपर बरसी और कुछ मवेशी बाढ़ के कारण बह गये। ऐसी परिस्थिति में वे छोटे-छोटे मवेशी पालने वाले लोग या वे छोटे-छोटे किसान जिनके मवेशी इस बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण मर चुके हैं, उनको भी सहायता दी जाए। मध्य प्रदेश में केला पैदा करने वाले किसानों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार भी आगे आए।

* **SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) :** This year again the state of Karnataka has experienced the worst drought. It is the fourth year in a row. The June month recorded the lowest rainfall in the past few decades. The state got only 47% rainfall in June this year. The improper rain has affected agriculture activity, availability of drinking water and hydel power generation.

During monsoon, sowing takes place on an average 74 lakh hectares in the state. By June 30, the average sowing area should have been 25.36 lakh hectares, but is only 18.92 lakh hectares.

Karnataka state government had declared 125 taluks out of 176 taluks (revenue sub-divisions) as drought hit talukas. The drought-hit areas received less than average rainfall with a continuous dry spell for the last 2 to 3 months.

Therefore, I urge upon the Union Government to come forward to rescue farmers of the drought affected areas and release adequate funds to take up drought relief measures like providing drinking water, fodder for cattle and other livestock and food grain supply.

* **DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR) :** I put my views on a dialectical situation, that is flood and drought prevailing in parts of our country. In this regard, I would like to say that my state Odisha is affected by these natural disasters almost every year. You will be coming across the news that the western parts of Odisha especially the KBK regions have been affected by drought and the eastern parts, that is the coastal belt of the Odisha has been ravaged by flood severely putting the people in distress. I am sorry to say that after almost 66 years of country's independence we are facing the problem due to lack of water as well as flood of water. That means we are lacking at management of water appropriately. You must know once the river Whang Ho of China was known as the sorrow of the country because of its role in playing havoc and destruction along the river flowing areas, but today the same river is considered as a privilege because of the able management of the water of the said river by the use of

technology. So, where are we now? And for how many years we will be telling that we are unable to mitigate the problems of drought or flood? Can't we tame the river to manage its water during flood or can't we interlink the river to divert the surplus water to the rivers or channels flowing in areas affected by drought?

According to the guidelines for management of floods, I would like say that in last five years, the govt. especially the Ministry of Water Resources has not formulated any guidelines or actionable plan for management of floods. This has categorically breached the proposed process as was issued by Disaster Management Authority of India in 2008 to mitigate the flood in the country.

The work of flood forecasting and warning in the country is not at all satisfactory. I would like to mention that there are 4728 reserviors and barrages in the country, but they are not being properly monitored or taken care of in order to reduce the damage caused by flood or to control the severity of flood. A task force was set up in 2004 by the Government of India to manage flood and erosion along river Ganga and Brahmaputra at the estimated cost of Rs.4982 crores, but almost every year I am coming across the flood ravaged situation emerging in the areas these rivers are flowing. It is a matter of concern whether the funds sanctioned for the purpose is not being implemented properly or there is loophole in our system with a mindset not to control disaster caused by flood.

In respect of state of Odisha, I would like to shed views that out of 205 large dams in Odisha, there was no emergency plan for the large dams for which Emergency Action Plan was under preparation.

It is not all advisable that we should go for providing relief or assistance only after the occurrence of flood or drought, rather we always should take the preemptive measures to confront such disaster with a view to control the magnitude of devastation. My state Odisha especially my constituency Jagatsinghpur through which the biggest river of the state, i.e. Mahanadi is flowing, flood in river Mahanadi in Odisha is a recurrent phenomenon. Heavy rains during monsoon period as well as un-seasonal cyclonic rains cause flood in river Mahanadi subsequently making breaches in embankment along both sides of river. Almost every year, the low lying areas along the river Mahanadi in my Parliamentary Constituency namely Tirtol, Rahama, Kujang, Singitali, Chaumauhani, Lughagarha, Balidiha, etc. face the fury of flood because of breaches in embankment. It is a matter of concern that the breaches in embankment cause more casualities as well as loss of property, since it occur suddenly thereby making the people helpless. Though the weak portions of the embankment along the river are renovated by putting sand filled pockets in phased manner especially before the occurrence of flood, still that is not the permanent solution to keep the embankment intact. A huge farm at Kujang has already lost almost all of its area due to encroachment of river and only the plantation can save the same. I would like to mention further that Essar Steel and IFFCO established along the riverbank of Mahanadi are affected severely as the industrial area get submerged by the water of Mahanadi during flood. Since, Luhagarha and Balidiha villages, Essar Steel and IFFCO are close to the river mouth and the way the river is encroaching into the nearby areas, the same may totally be merged in Bay of Bengal in course of time if plantation, particularly mangroves plantation is not made in the river bank along these areas. In this regard, I would like to urge upon the Government that the weak portions of the embankment along the river from Cuttack to Chaumauhani be concretized along with the plantation on embankment and the area nearer to the river mouth be planned with mangroves plantation in order to reduce the magnitude of the floods and the severity of its impact in the region. My view in respect of gravity of disaster or the disaster prone states should be given more facilities. For example my state almost every year witness either flood or drought or cyclone, which subsequently make the state undeveloped and poor. Hence, I urge upon the government to provide adequate amount of funds to address the problems of poor people who are basically the victims of all type of disasters especially flood and drought in my state of Odisha. Besides, I would like to draw the attention of the Government of make the telemetry stations functional and to install temporary gauge sites during the flood period. The flood forecasting stations are also not having dedicated communication facilities. So, my demand is that these shortcomings should be rectified along with expansion and moderisation of flood forecasting and warning system all over the country, especially in Odisha.

---

*SHRI Y.S. AVINASH REDDY (KADAPA): Whenever there is heavy flood or severe drought, it is the farmers who are going to get worst affected.

Disasters occur due to heavy winds or heavy rains. Take for instance my constituency YSR District of Kadapa. Mostly due to heavy winds the banana plantation gets collapsed. Cultivating bananas is a very expensive affair. It will incur an expenditure of Rs.one lakh per acre to cultivate banana plantation. After investing such huge money, if the crop is getting collapsed just think of the fate of our farmers. There is one insurance scheme from AIC India for bananas plantation. But it is certainly of no use. A device which measures the speed of wind, which also measures rainfall

is placed in the Mandal headquarters. It measures the rainfall or wind impact only in the surrounding area and it does not even cover 10% of the Mandal. In this case, what is the use of collecting Rs.3000 per acre as insurance premium from farmers who are taking bank loans? Over the last 7-8 years, every year hundreds of areas of banana plantations is getting collapsed due to heavy winds, but not even once, insurance was paid to the farmers. Such is the condition of farmers who are affected due to heavy winds. Considering these circumstances, the Government of India should take all measure to provide necessary relief to the farmers.

And our district YSR Kadapa District is also a severe drought prone area. Having known this, our beloved late Chief Minister Dr. YSR introduced micro-irrigation programme. Under this programme, several farm ponds were built to store water in them and to use it during severe drought conditions. Also drip irrigation was introduced with a subsidy of 90%. Most of the sweet lime farmers and banana farmers use drip irrigations. Government must take measures to renew the drip to farmers once in three years presently one drip is provided to farmers

---

* Speech was laid on the Table

and it will only get affect after 10 years. It must be reduced to three years because the drip gets torn off after three years due to the low quality of water. Also Government must take measures to increase the extent of drip irrigation per farmer from three acres to five acres.

By providing such incentives or by taking such measures, farmers could face drought condition at least to some extent. Once again I would request the Government of India to rethink the insurance programme of AIC. The Government must also make sure that insurance and relief are given to farmers who are hit by heavy winds.

***SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE) :** First of all, I would like to thank our leader hon. Chief Minister of Tamilnadu Purtachi Thalaivi Amma and also the people of my Coimbatore constituency for choosing and electing me.

India is a country of a mixture of culture, lanugauge and different geographical climate etc. In one part of India it is experiencing hot, dry and drought and in another part it is experiencing with heavy rain and floods. Rainfall as the principal parameter is the basis of all definition of drought. Everyone present here is very well known that, there is heavy rain and flood in Himalayan side and Western Ghat side and another side there is no rain and shortage of water. The surplus water are drained into sea. So, the union government must take a concrete step to utilize the surplus water from one part of India to the needy place/region by linking of rivers.

India is a land of monsoons of which the South-West Monsoon is a wet monsoon, while the North-East monsoon is a dry one. Yet the rainfall produced by them is not uniformly distributed throughout India. Therefore, it leads to the occurrence of floods and droughts in different parts of the country from time to time. While floods are confined to restricted areas based on the distribution of the major river systems, droughts are only on account of rainfall failures.

In India many meteorological sub-divisions have faced severe drought during the past 11 years. As many as 99 districts, spread over 14 states, were identified by the Central Water Commission (CWC) as drought-prone in the country. Most of the drought-prone areas so identified are concentrated in the states of Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra.

Droughts unlike floods are slow-acting but a sure distress sapping the lives, property and economy of the population. Though floods and droughts are both triggered by natural meteorological causes, their impact is determined to a large extent by human factors-unpreparedness, ignorance and neglect, apart from improper design and poor execution of the hydrological projects.

Floods and droughts are the two faces of the same coin. Droughts hit food production mainly through water scarcity; floods disrupt national economy through water surplus causing wide-spread inundation, destruction of crops, dislocation of communications besides loss of human lives and live-stock.

For the past several years, many farmers, live-stock died due to drought, famine throughout India and at the same time many humans, live-stock died due to heavy rain and floods in some parts of India. In recent years, we have witnessed a number of major disasters in India which have caused untold miseries and havoc to life and property. The impact of Tsunami, earthquake, landslides and cyclone, floods and drought still being felt by the affected communities which affected the lives and livelihood of millions of people and properties destroyed. The recent one is flood and landslide in Uttarakhand. There lot of people, live-stock died and perished.

Flood creates a great barrier on the path of progress of our country. The National Flood Policy suggests various ways to control flood in the country. Union government has also established National Disaster Management to take relief measures on the spot of incident and doing their job very well. But it is only a temporary one. It would not be serve the purpose to prevent floods in the country. Our government should take permanent solutions and steps to prevent floods in the country.

Preservation and proper utilization of the rainwater, surface-water and the underground water of the area is essential to combat the problem of drought. Those areas can possibly have agricultural products by adoption of dry farming that needs less water. The underground water can be utilized by sinking wells and tube-wells.

Government of Tamil Nadu under the leadership of our able Chief Minister puratchi Thalaivi 'Amma' has taken number of steps to cope up and to prevent drought and floods in the state by taking number of measures for the last several years.

Our 'Amma' is the first one who introduced rainwater harvesting scheme in the country. It was made compulsory for every building to avoid ground water depletion. It proved excellent results within five years, and every states took it as role model. Since its implementation, Chennai saw a 50 percent rise in water level in five years and the water quality significantly improved.

To fight drought, our Chief Minister 'Amma' is encouraging planting of saplings throughout the state. Through forestation, more rain is expected and drought can disappear. Recently on her 64th birthday, around 64 lakhs of saplings have been planted throughout the state. Further our 'Amma' is taking very strict action against those who are cutting the trees. Further, our 'Amma' is always seeking and requesting the neighbouring states to supply surplus water which gets drained into sea as well as to increase the height of dams to preserve more water in the dam. But no one is acceding our 'Amma' request.

Our Chief Minister hon. Amma our visionary leader who introduced some schemes to improve forests to avoid the occurrence of drought as well to get more rain in the state. Some of the schemes are :

1) Water conservation and canopy improvement in degraded forest lands.

2) Tamil Nadu Afforestation Project (TAP) Phase-II-Utilisation Plan.

3) Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening Project (TBGP).

4) Massive Tree Planting Programme.

5) Replanting in Thane cyclone affected areas of Cuddalore and Villupuram districts.

6) Western Ghats Development Programme, and

7) Hill Area Development Programme are some of the ongoing major schemes in Tamil Nadu with an allocation of about Rs.242 crores.

No country or no state can develop and expect any growth without water. Water is used not only for drinking and bathing but it is the main source for agriculture, power generation etc. India is a agriculture country and 70% of the population lives in villages and are dependent upon agriculture. So, the surplus water which is drained into sea needs to be diverted to the needy area. Hence, our Chief Ministers urged the Union Government to take necessary steps to implement the Cauvery Water Tribunal and Supreme Court verdict. Our 'Amma' also wrote a letter to the hon. Prime Minister few days back to constitute a Cauvery Monitoring Committee, but so far no reply has been received from the PMO.

Now, we came to know that the changed new BJP government is taking some efforts to constitute a committee to prepare a feasibility report/study about the linking of rivers throughout India. If this project is implemented, there will be no drought, no famine, starvation death and no floods in our country. We can see the smiles on all the farmers face, there will be no unemployment in the country, all the educated youths who turn to the field of modern agriculture technology, will prosper in all aspects. To achieve this goal, all must unite and forget our differences of politics, region and culture etc.

It is also true that everyone knows that at the time of natural calamity and disaster occurring anywhere in India, all states share their burden voluntarily by donating money, materials and other kind of assistance for rehabilitation of the affected people.

Yes I agree that some states in our country prosper because of abundance of natural resources and some states are backward because of its non-availability or less natural resources due to geographical set up. It is the duty and responsibility of every citizen and all political leaders of the country to share our natural resources among the states for neutral growth and development of our country and India will achieve the super power status in near future.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि हमारे देश के अंदर आज भी लगभग 70 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो अपना जीवनयापन खेती-किसानी पर कर रहे हैं। चाहे बाढ़ आये या सूखा आये, यदि इसका सबसे ज्यादा कोई शिकार हुआ है, तो वे देश के किसान हैं। मेरा इस सदन में 11वां वर्ष है। इन वर्षों में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया होगा जब इस मुद्दे पर चर्चा न हुई हो। चर्चा का क्या परिणाम निकला, आज तक इस बात का एहसास कम से कम मुझे नहीं हुआ। जहां सूखा या बाढ़ से किसान तात्कालिक रूप से प्रभावित होते हैं, उनको तात्कालिक राहत की जरूरत होती है, वहीं हमारे देश की 67 साल की आजादी के बाद भी देश की सरकारों ने स्थायी इंतजाम नहीं किया है कि बाढ़ और सूखे से कैसे निपटा जाए। जहां यह तात्कालिक समस्या है, उसका निराकरण होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक स्थायी और दीर्घकालिक इंतजाम भी होना चाहिए। जहां तक सरकारों की योजनाओं का सवाल है, कल योगी आदित्यनाथ जी की बातों को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सी गंभीर बातें कही हैं, वास्तव में इस देश में योजनाएं बनती भी हैं, लेकिन बनने के बाद उन योजनाओं पर कोई सार्थक पहल नहीं हो पाती है। हमें इस सरकार की नीयत पर पूरी शंका है। यह शंका यूं ही नहीं है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। देश में आज सूखे की हालत है और बाढ़ की भी हालत है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूखा भी पड़ेगा और बाढ़ भी आएगी, लेकिन देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, जो आपदा प्रबंधन के मामले में देश की सर्वोच्च संस्था है, केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच तारतम्य बैठाने की जिसकी जिम्मेदारी है, का गठन अभी तक इस एनडीए सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मुझे शंका हो रही है कि कैसे आपदा का प्रबंधन करेंगे। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में केवल दो जनपदों - श्रावस्ती और बस्ती में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, बाकी अधिकांश जनपद ऐसे हैं, जहां सूखे की हालत बनी हुई है। धान की खेती नहीं हो पा रही है, धान की नर्सरी नहीं लग पा रही है, जिन किसानों ने नर्सरी लगा भी ली, तो उस धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों की जो धान की फसल बर्बाद हुई है, उसके लिए या तो ऋण दिलाएं, ऋण माफ कराएं और हो सके तो ब्याज को माफ करने का काम करें। बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन समय की कमी है। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी। उसके बाद 380 लोग खत्म हुए, उन लोगों के खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री जी और वर्तमान प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जिन लोगों ने अपना जीवन गवां दिया है, ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए इंतजाम होना चाहिए। वह पत्र केन्द्र

सरकार के पास मौजूद है, अभी तक कोई राहत कार्य या राहत के लिए मदद उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाई है। बहुत से प्रान्तों के साथियों ने चर्चा की है, प्रदेश सरकारों के पास संसाधनों की कमी होती है, भारत सरकार के पास अपार संसाधन हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो मांग की है, वर्ष 2013 की बाढ़ में जो लोग प्रभावित हुए थे, उनकी राहत और मदद के लिए जो मांग की है, उसे केन्द्र सरकार स्वीकार करे। साथ ही सूखे के कारण जो स्थिति आती है, वह भी आपके सामने है। उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत आपने संकल्प लिया है कि वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तक पेयजल की आपूर्ति पाइप से पहुंचाएंगे, लेकिन आप जो बजट प्रदेश सरकारों को दे रहे हैं, उसे देखकर मुझे यह विश्वास नहीं होता है कि वर्ष 2022 तक आप इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए 60,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, लेकिन इसके अगेन्स्ट आपने एक वर्ष में केवल 850 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जबकि इस काम पर 1700 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार व्यय कर रही है। मैं समझता हूं कि इतनी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार अकेले नहीं खर्च कर सकती है। लिहाजा 3500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देने का काम करें।

हमारी जल संसाधन मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र बदायूँ से आता हूं, उसमें गंगा जी का सबसे बड़ा किनारा है, जो कि हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। यह किनारा करीब 120 किलोमीटर लम्बा है। एक तरफ गंगा मैया है और दूसरे तरफ रामगंगा है। मंत्री जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गंगा मैया बाढ़ तो बदायूँ को देकर चली जाती हैं, लेकिन सिंचाई के नाम पर एक इंच जमीन भी वहां सिंचित नहीं हो रही है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया और हमारी सरकार ने बदायूँ लिफ्ट कैनाल परियोजना नाम से एक प्रस्ताव तैयार किया। उस परियोजना को केन्द्र के सेंट्रल वाटर कमीशन की अनुमति के लिए भेजा गया। फंड का प्रावधान तो हम प्रदेश सरकार से करा लेंगे, मगर मैं जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी इस परियोजना को सेंट्रल वाटर कमीशन से यथाशीघ्र अनुमति दिलाने का काम करें। इससे हम बदायूँ के लोगों की जो प्यास है, उसे दूर कर सकें और बाढ़ से जो नुकसान होता है, उसे भी रोका जा सके।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति जी, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा।

माननीय सभापति: आप पहले ही सात मिनट ले चुके हैं। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें, नहीं तो आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

श्री धर्मेन्द्र यादव : ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, प्रकृति, परमात्मा और व्यक्ति, व्यक्ति जब तक सुपरपावर खुद को बनाए रखेगा और प्रकृति तथा परमात्मा के साथ वह जब तक छेड़छाड़ करता रहेगा, तब आपदाएं आती रहेंगी। आजादी के बाद हर साल इस सदन में दो बार तो कम से कम बाढ़ और सूखे पर चर्चा होती है। कोई भी निराकरण नहीं हो सकता है, जब तक व्यक्ति खुद प्रकृति का सम्मान न करे।

मैं सिर्फ कुछ बातों पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान में 22 प्रतिशत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है और उसमें से 16 प्रतिशत सिर्फ बिहार में है। आजादी के बाद जब राजेन्द्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति थे, उनके समय में बैठक हुई थी। उसमें तय किया गया था कि किसी भी नदी पर बांध समस्या का निराकरण नहीं है। उन बातों को पिछली सरकारों ने और इस सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया। उसके बाद लगातार बिहार की जो स्थिति बनी है, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप बाढ़ से कैसे बचाएंगे, बाढ़ से कितने लोग मरते हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। बिहार में ही प्रत्येक साल बाढ़ से 1200 से 1300 लोग मारे जाते हैं। सन् 1988 में 874 लोग मारे गए थे। इसके अलावा जानमाल की अलग से हानि होती है। आजादी के बाद भी लोगों को क्या मिला कि हम पुनः इस विषय पर सदन में बहस कर रहे हैं। क्या इस बहस से देश के आम लोगों को कुछ राहत या निजात मिल सकती है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि किसी तरह की निजात मिल सकेगी या नहीं।

मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाए, जो सीधा प्राकृतिक वातावरण को क्षति पहुंचाता हो। मैं दूसरा आग्रह यह करूंगा कि आकाश में जो भी अनुसंधान हो रहा है, उससे जल प्रभावित न हो। इस बात को मंत्री महोदय ध्यान में रखें। मैं तीसरा आग्रह यह करूंगा कि जो भी शिक्षा देश में लागू की जा रही है या शिक्षा की नई योजना बनाई जाए, तो उसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से जो दुष्परिणाम होते हैं, उनका समावेश भी शिक्षा में होना चाहिए। जिससे आने वाली पीढ़ी समझ सके और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे।

आज जो उत्तराखंड या पुणे में भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई, वह व्यक्ति की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का कारण है। उत्तराखंड या पुणे जैसी विभीषिका कोई परमात्मा के कारण नहीं आई है। व्यक्ति ने जब-जब प्रकृति से छेड़छाड की है तब-तब उत्तराखंड और पूना जैसी विपदाएं आई हैं।

दूसरी चीज यह है कि अत्यधिक बारिश के कारण पानी समुद्र में चला जाता है। हमारे यहां उत्तर बिहार में तीन हिस्से बाढ़ से प्रभावित है और एक हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित है। उत्तर बिहार के पानी को यदि दक्षिण बिहार में लाने की व्यवस्था करे, तो हमारे यहां बाढ़ की जो विकराल स्थिति है वह कम होगी और दक्षिण बिहार भी सिंचित होगा। हम सुखाड़ और बाढ़ दोनों से प्रभावित हैं। हमारा इतिहास है कि आजादी के बाद से हम सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि जब जापान जैसे देशों में समुद्र के पानी को मीठा करके सिर्फ पीने के लिए ही नहीं खेती के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है तो हमारे देश में दुनिया का सबसे अत्यधिक मीठा पानी होने के बावजूद हम उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वह मीठा पानी समुद्र में चला जाता है। क्या सरकार उस मीठे पानी को पहाड़ों पर रोककर कोई व्यवस्था करेगी जिससे हमारी जमीन तो सिंचित हो ही, हमें पीने के लिए भी वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। हम जो ग्राउंड वाटर से जमीन की सिंचाई कर रहे हैं क्या उसके दुष्परिणाम के लिए हम तैयार हैं। पेट्रोल के बाद पूरी दुनिया में अगर हाहाकार होगा तो वह पानी के लिए होगा। भारत सरकार क्या उस स्थिति के लिए तैयार है?

आज हम पेड़ों की कटाई को नहीं रोक पा रहे हैं। गर्मी के प्रभाव से बादल नहीं बनते हैं और बनते हैं तो भी चले जाते हैं और फिर सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है। हमें सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि बारिश के पानी पर ही निर्भर रहकर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इससे पूर्व चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लालू जी की सरकार रही हो या नीतीश जी की सरकार रही है, बिहार की स्थिति को कमोबेश हमेशा भारत सरकार से अपनी सारी योजनाओं को देने का काम किया है। उसमें हाई-डैम है और लगातार कांग्रेस के समय में भी कई बार मीटिंग हुई, नेपाल अभी माननीय सुषमा

जी गयी हुई थीं। बिहार सरकार प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपया नेपाल सरकार को डैम के रखरखाव के लिए देती है। विश्व की सबसे खतरनाक नदी कोसी नदी है और वह कोसी नेपाल से निकलकर गंगा में आकर मिलती है। कमला है, गंडक है, महानंदा है और उनसे प्रभावित क्षेत्र बांका से लेकर भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पुर्णिया, मतलब यह है कि आप इस बात को समझ लें कि हम लोग बाढ़ के समय में जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। चार महीने से लेकर छह महीने तक हम हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कई क्षेत्रों में दो साल से सुखाड़ की स्थिति है।

महोदय, बिहार में इस साल 60 प्रतिशत भी वर्षा नहीं हुई है और आप सासाराम, गया के इलाके में चले जाइये तो आपको स्थिति की भयावहता का पता चल जाएगा। अभी केला और अन्य चीजों के बारे में हमारे मित्र बोल रहे थे। किसानों की स्थिति पर बोलने का हक शायद इस सदन के सदस्यों को नहीं रह गया है। हर साल यहां किसानों और गरीबी पर बहस होती है लेकिन सबसे बदतर स्थिति में इस देश के गरीब और किसान लोग ही रहते हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन सरकार से आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान की सदन में बैठे जो सांसद हैं उनमें 70-75 प्रतिशत सांसद किसानों के बेटे हैं, क्या किसान के प्रति उनकी कोई चिंता है, क्या किसान बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित होकर समाप्त नहीं हो जाता है। क्या बिहार सरकार के लिए कोई ऋण माफी की योजना है।

महोदय, आप जानते हैं कि बिहार के कोसी के इतिहास में चाहे धान हो, पान हो, मखाना हो, ये हमारा इतिहास है और हम विश्व को खिला सकते हैं। यदि बाढ़ की स्थिति न आए तो कोसी की धरती मध्य प्रदेश को सालों-साल अनाज दे सकती है। मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश को भी बिहार की कोसी की धरती, मिथिला की धरती से अनाज द्वारा आम आदमी को भोजन दे सकते हैं। लेकिन आज हम स्वयं भोजन के लिए लालायित हैं। हम काखों, डाखों, सूखी मछली, कच्चा कसार, जंगली साग खा कर हम अपने जीवन को बिताते हैं। आजादी के बाद आज तक हमारी तरफ ध्यान देने की किसी ने कोशिश नहीं की है। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि 17 अगस्त 2004 और 2009-2013, तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने एक योजना बना कर आपको दी थी। कोशी में हाई डैम के बाद सप्त कोसी डैम बनाने की योजना बनी थी। यदि वह योजना बनती है तो कितनी मेगावाट बिजली पैदा होगी? हमारी 11 हजार वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि संरक्षित है, क्या आज तक हाई डैम के लिए नेहरू जी से लेकर आज तक यह सवाल उठता रहा कि हाई डैम बनाने की या सप्त कोसी पर डैम बनाने की कोई योजना आपकी है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके में सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड पूरी तरह से जल मग्न है। बीस गांव समाप्त हो गए हैं और 400 आदमी मर गए हैं। हम परसों नाव से डूबते-डूबते बचे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भागलपुर के कटाव से लेकर मनिहारी, भागलपुर, नवहट्टा, सुपोल में कोसी के कटाव की स्थिति है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, सरकार कोई योजना बना रही है या नहीं और वहां के जो आम लोग हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है या नहीं? बिहार की सरकार ने भारत सरकार से जो मांग की है कि वहां के किसानों के लिए बाढ़ और सिंचाई के विषय पर, क्या सरकार बिहार के किसानों के लिए कोई योजना बनाने जा रही है या नहीं? आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

* SHRI MOHANBHAI KALYANJIBHAI KUNDARIYA (RAJKOT): Today Science has made tremendous success to make man reach even Moon. But man became helpless against nature. Recently, we are discussing in this august House about deficit monsoon this year and we are very much worried about that. The Union Government and State Government are ready to face the low rain in their respective States. But during a period of a week, there was very heavy rain in certain areas of different States. In our Country, monsoon is very unpredictable. During NDA Government, our Hon'ble Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee started a river linking scheme in our country.

In our Gujarat State, Hon'ble Chief Minister Shri Narendra Bhai Modi had done this linking of river very successfully in North Gujarat. He recently announced a SAVNI Yojana worth of Rs 10,000 crore to provide a water Saurashtra and Kutch region of Gujarat by linking river Narmada and linking it with 225 dams in Saurashtra.

---

* Speech was laid on the Table

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, राजेश रंजन जी अभी उस इलाके की कहानी के साथ-साथ कुछ सुझाव दे रहे थे। संयोग से उनका और हमारा जन्म उसी मिथिलांचल के कोसी कमला-बलान क्षेत्र में हुआ है। एक पैर बाढ़ में और एक पैर सुखाड़ में। जब नेपाल में पहाड़ पर पानी जोर से बरस जाए, तो हम बाढ़ में डूबने लगते हैं। जब पहाड़ में पानी न बरसे तो सूखाड़ की चपेट में आ जाते हैं। फिर न जाने कब बाढ़ आ जाए। मेरी जिंदगी में हथिया नक्षत्र में भी दो तीन बार बाढ़ आई है जब धान की लहलहाती फसलें बरबाद हो गयी थी और किसान बिलकुल निर्धन और दरिद्र हो जाता है। ऐसे इलाके मिथिलांचल में हमारा जन्म हुआ है, उस इलाके के लोग शुरू से मैथिली भाषा में गाते रहे

हैं -

"कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर
दुखहि जनम भेल दुखहि गमाओल सुख-सपनहु नहीं भेल
हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर।"

लेकिन आज तक न भोला बाबा सुन रहे हैं और न ही सरकार द्वारा कुछ हुआ है। वे लोग दुख में ही पड़े हुए हैं और महिलाएं गाती हैं कि 'अविरल आंसू बहे नैनन से, अब तो दया करो, हे राम कृपा करो।' उस इलाके में जनम लेने के कारण उसकी दर्दनाक कहानी मैं नहीं कह सकता हूं अगर कहने लगूं, तो इस सदन की ईंट की आंख से भी आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि इतनी वेदना और इतने दर्द के साथ उस इलाके के लोग तीन महीने तक जीवन जीते हैं।

मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं कि अगर ऐसा किया गया होता, बराह क्षेत्र में, कोसी में, शीशा पानी में, कमलाबलान में और नूनथ में अधवारा समूह में डैम बनाने की पच्चीसों वर्ष से चर्चा चल रही है, लेकिन भारत सरकार आगे बढ़ती नहीं है और न बिहार सरकार कुछ करती है। न जाने केंद्र के और बिहार के तथा नेपाल के, इन तीनों के चक्कर में हम बाढ़ में और सूखाड़ में मरते रहे हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अब आगे बढ़े। नेपाल सरकार के साथ समझौता करे। माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल जाने वाले हैं। शायद मेरी बात वहां तक पहुंचे तो इस बात पर भी वे नेपाल सरकार से चर्चा करें जिससे इन तीनों डैम का निर्माण हो जाए। इससे इतनी बिजली पैदा होगी कि बिहार की क्या बात करें बल्कि आधे भारत को बिजली मिलेगी।

<u>16.00 hrs.</u>

हमारी दो फसलें धान और गेहूं जो हम पैदा करते हैं, ये हमारी फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए।

बगहा से लेकर किशनगंज तक उसी इलाके में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी भी रहते हैं। बगहा से लेकर किशनगंज तक का जो इलाका है, नेपाल की तराई के साथ साथ हैं हम जिस समय डा.लोहिया के आंदोलन में थे, उस समय उस इलाके में बाढ़, सुखाड़ स्थायी निदान सम्मेलन किया करते थे। हम लोग तब से मांग कर रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : लोहिया जी की विचारधारा आपने छोड़ दी है।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : छोड़ी नहीं है। जो कांग्रेस के शरणागत हुए, उन्होंने विचारधारा छोड़ी। कांग्रेस के विरोधी मेरे गुरु थे। आज भी मैं कांग्रेस का विरोधी हूं। जो कांग्रेस का चरण चुम्बन कर रहे हैं, वे लोहिया के विरोधी हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross talk is allowed. Please do not disturb.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति जी, बगहा से लेकर किशनगंज तक अगर नहर की खुदाई कर दी जाती,...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri, Rajesh Ranjan ji, No, please sit down.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमें अपनी बात बोलने दीजिए। आप कभी हमसे बाद में बहस कर लीजिएगा। हमसे बहस करते करते बहुत लोहियावादी थक गये। आप तो लोहियावादी कभी नहीं थे।...(व्यवधान) आप शांत रहिए। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि बगहा से लेकर किशनगंज तक हम उस समय से आंदोलन करते रहे हैं कि बगहा से किशनगंज तक सीधे पश्चिम से पूर्व तक नदी जोड़ दी जाए जिससे उत्तर बिहार की, मिथिलांचल की सभी नदियां उसमें जुड़ जाएं। अगर किसी नदी में बाढ़ आएगी, वह पानी सभी नदियों में चला जाएगा जिसके कारण बाढ़ की समस्या का निदान होगा। इसलिए नदियों को जोड़ो। हम कहते हैं कि नदियां जोड़ो जिससे बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का निदान होगा। बगहा से किशनगंज तक लम्बी नहर खोदकर सभी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरे, पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण हुआ। पूर्वी कोसी नहर में कुछ सिंचाई हुई लेकिन बालू की समस्या से लोग पीड़ित रहे। पश्चिमी कोसी नहर अब तक अधूरी है। उसके रेखांकन गलत किये गये। डीपीआर गलत बनाया गया। साईफन बड़ा होना चाहिए तो छोटा कर दिया गया। जहां साईफन होना चाहिए, वहां साईफन नहीं बनाया। इसके कारण परेशानी है। इसलिए उसका फिर से डीपीआर बनाया जाए और फिर से उसका प्राक्कलन बनाकर, सुधार करके पश्चिमी-कोसी नहर को शीघ्र पूरा किया जाए तो मिथिलांचल के अंदर बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आहर कहते हैं, जो सिंचाई के स्रोत हैं, आहर, मृत नदियों के जितने बैड हैं और उसके साथ साथ तालाब और पोखरा हैं, इन सबकी खुदाई क्यों नहीं करवाई गई? मनरेगा पर हजारों करोड़ों रुपये खर्च किये गये। लेकिन अगर इनकी खुदाई करा दी जाती तो सिंचाई के स्रोत बढ़ जाते जितने मृत नदियों के बैड हैं, पुराने तालाब हैं, वे सब अतिक्रमण से ग्रसित हैं, उन पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया गया। इसके लिए अतिक्रमण कानून में नया संशोधन किया जाए और यह कहा जाए कि सड़क में, विद्यालय में, सिंचाई के स्रोत पर अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको नया कानून बनाकर, उस पर कार्रवाई की जाए। Prevention of Damage to Public Property Act संसद से बना हुआ है। उसके तहत कार्रवाई की जाए तो हमारी सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। लेकिन यह सरकार को करना चाहिए।

अंत में, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम उस बाढ़ में जन्मते हैं, उसी बाढ़ में पलते हैं, उसी बाढ़ में मरते हैं और मरने के बाद हमारी लाश भी बाढ़ के पानी में बहा दी जाती है क्योंकि हमें जलाने के लिए कहीं सूखी जमीन नहीं रहती है। इस विपत्ति को हम झेलते आए हैं तो कितने दिनों तक झेलेंगे? इसलिए उस इलाके के लोगों ने बड़ी आशा, उमंग और विश्वास के साथ श्री नरेन्द्र मोदी जी का साथ दिया। लोगों को जिताकर यहां भेजा। अब हम चाहते हैं कि अंत में कृषि मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी दोनों मिलकर एक आयोग बनाएं और उस आयोग के द्वारा मिथिलांचल और उत्तर बिहार में बाढ़ और अकाल से निदान के लिए एक बड़ी योजना बनाई जाए और उसके आधार पर काम किया जाए। उसमें नेपाल सरकार से भी समझौता किया जाए। अगर इतना कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में हमारे बच्चे रोएंगे नहीं।

कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा,

कखन हरब दुख मोर,

दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाओल,

सुख सपनेहुं नहीं भेल,

हे भोला बाबा, कखन हरब मोर।

ये गाते-गाते रोते आए हैं, उसका निदान होगा।

ऑश्री संजय धोत्रे (अकोला) : इस वर्ष पूरे देश में 30-40 दिन देरी से मानसून की बारिस शुरू हुई 30 जून तक पिछले 100 वर्ष का रिकार्ड टूट गया बारिश की कमी से भारी नुकसान हुआ कई क्षेत्रों में 15-20 जुलाई से बारिश शुरू हुई किसान और सारे लोग खुश हुये लेकिन कई जगह इतनी ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ आई, खेती की मिट्टी बह गई। इस तरह किसानों को दुतरफा आपत्ति का सामना करना पड़ा। विदर्भ के छः जिले अकोला, अमरावती, बुलढाना, वारीम, यवतमाल और वर्धा जहां पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्म हत्यायें कि वहां इस वर्ष फरवरी मार्च मे माह में ओलावृष्टि हुई जिसके कारण, कपास , गेहूं चना, प्याज केला और कई फलबागों का भारी नुकसान हुआ इसके बाद सूखा और बाढ़ कि मार झेल रहे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा एक दल भेजा जाये और किसानों की पर्याप्त मदद की जाये और इस तरह से आनेवाली आपदा से निपटने के लिये दीर्घकालीन शाश्वत योजना बनाई जायें ।

---

* Speech was laid on the Table

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, पहले सरकार कबूल करे कि सूखा आने वाला है। अभी कबूल ही नहीं किया क्योंकि बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। इसका मतलब है कि उनके एजेंडे में है ही नहीं कि सूखा आने वाला है। सूखा बहुत से प्रदेशों में आ चुका है। मौसम विभाग के माहिरों ने बताया है कि अगर दस परसेंट बारिश में कमी आती है तो इसका मतलब है कि 20 से 40 परसेंट देश का एरिया प्रभावित होता है। इस बार 25 परसेंट बारिश कम होने की आशंका है, ऐसा माहिर कह रहे हैं।

16.06 hrs.

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

इसका मतलब यह है कि देश का जो एरिया प्रभावित होगा वह 50 से 75 प्रतिशत होगा। इस तरह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित होगा। इसके लिए फौरन कदम उठाने की जरूरत है। आंकड़ों के मुताबिक 113 साल में जून महीना सबसे ज्यादा सूखा महीना माना गया है। राज्य और सैंटर में तालमेल की बहुत कमी है। सूखा पड़ता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष देती है और केंद्र सरकार कहती है कि यह राज्य का मामला है। तालमेल की कमी है, इस तालमेल को इमीडिएटली ठीक करने की जरूरत है।

महोदय, मैं पंजाब से आता हूं। जब पंजाब का नाम आता है तो हरियाली सामने आ जाती है। पंजाब के नाम का मतलब पांच दरिया की धरती है। पंजाब की बदकिस्मती है और आज के हालात यह हैं कि जिस राज्य का नाम पानी पर है, दरिया पर है, उसका पानी न तो पीने लायक है और न खेती के लायक है। पीने के पानी में यूरेनियम आ गया है। मालवा क्षेत्र में धान की वजह से पानी का लैवल इतना नीचे चला गया है कि किसानों के लिए ट्यूबवैल लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मेरे अपने क्षेत्र में 400-450 फुट नीचे पानी का लैवल हो गया है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें पानी का कम प्रयोग होता है। मक्की बिकने के लिए तैयार है। किसान बाजरा, सरसों, सब्जियां बीज सकता है लेकिन इनकी मार्केटिंग नहीं है। एमएसपी सही तय की जानी चाहिए। धान की फसल के कारण पानी का लैवल नीचे जा रहा है। पंजाब का एरिया जो हरियाणा और राजस्थान के साथ लगता है, वह मरुस्थल बनने जा रहा है। घग्गर नदी हरियाणा के साथ जुड़े बार्डर पर नुकसान करती है। जब बाढ़ आती है तो घग्गर नदी खास तौर से खन्नौरी, मूनख,

सरदूलगढ़ एरिया में बहुत नुकसान करती है क्योंकि यह बरसाती नदी है। अगर इस पर डैम बना दिया जाए तो घग्गर नदी का कहर खत्म हो जाएगा। बिजली भी मिलेगी और पानी का कहीं और भी प्रयोग किया जा सकता है।

महोदय, मैं संगरूर क्षेत्र से चुना गया हूं। यह पंजाब में खेती में नंबर एक आता है। बदकिस्मती से पिछली सरकारों ने खेती का बुरा हाल किया है और कोई प्लानिंग नहीं बनाई इसलिए फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं। संगरूर किसानों की आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर आता है। मूनक तहसील देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने में नंबर एक पर आई है। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से जर्नलिस्ट यहां आकर डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास शायद ये आंकड़े नहीं होंगे, यह शर्म की बात है।

मैं आखिर में यही कहूंगा कि सरकार किसानों के बारे में सोचे क्योंकि किसान देश के अन्नदाता हैं। जो किसान पूरे देश का पेट पालते थे आज वही किसान स्वयं भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए हैं। बैल के गले में डालने वाले रस्से जिससे वे घंटी या घुंघरू बांधते थे, वही रस्से अब किसान के गले की फांसी बन चुके हैं। यह ठीक है कि बुलेट ट्रेन की बातें हैं, स्मार्ट सिटी की बातें हैं। लेकिन अगर गांवों को भी स्मार्ट बनाना है तो किसानों की हालत को भी सुधारिये और स्पेशियली अगर खेती पर ध्यान दिया जाए तो हमारा देश तो खेती प्रधान देश है, कृपा करके इसे खेती प्रधान देश रहने दीजिए। हम अपने पेट को खुद पाल सकते हैं, हमारे देश की धरती बहुत अच्छी है।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि 21वीं सदी में हमारे बच्चों को यह न कहना पड़े कि 'रब्बा, रब्बा नहीं बरसा, साड्डी कोठी दाने पा।' इसलिए बारिश के बिना भी दाने आएं, उसके लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*** SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** The monsoon's below par performance this year is cause for concern. Besides arriving late, it lacks punch and has failed to gather momentum in its advance along the western coast. The below-normal monsoon has cast a cloud over the Government's plans to revive the economy. It's effort to boost the GDP growth rate will be hit adversely and business sentiment is becoming gloomy. While these are growing, it is the fate of millions of small and medium farmers that must be government's priority. These are people who have taken heavy loans to buy seeds and fertilizers. A failure of crop spells devastation for the. I would ask the Government to focus on alleviating their sufferings first.

Unlike some decades ago, when a weak monsoon spelt disaster, things have improved. A comfortable food grain buffer stock and sufficient water in most reservoirs in the country will help the Government tackle the fall out of a deficient monsoon. It is therefore necessary to call all State Governments and put across to them that the first right to water would be for drinking purpose and next is for agriculture. Hydro-power and provision for industrial units be made secondary option, immediately. Because of deficient and untimely rainfall in many States, small and marginal farmers are put to a loss. Now migration from affected villages have started.

Often discussion is made about crop insurance. Today the requirement is to have Weather Based Crop Insurance Scheme. I am told in Maharashtra this is being implemented in 12 districts only. Why not extend it to other parts of the country? It has some limitations but can not those be corrected. Odisha, one of the major rice producers has decided to implement the Agriculture Insurance Scheme during the ongoing Kharif season.

Agriculture Minister has said Government is fully prepared to tackle any situation arising out of poor monsoon. We are informed that Agriculture Ministry has a drought contingency plan for 500 districts. Prime Minister is laying stress on farm sector issues and is focusing on boosting the rural economy thereby reducing farmers distress. I would like to know what contingency plan you have in place? Whether States have been suitably advised? Is the Government assuring us that sufficient food stocks are in place and quick action will be taken in any situation arising out of flood and drought?

Even as monsoon is currently 24% below the long period average which is worse than the deficiency seen in 2009 or 2012. Crisil Research estimates that this year, there is a higher probability of a turnaround-just like in 2012. State-wise rainfall deficiency, one can say, is that in, Odisha it is minus 4 percent whereas in Punjab it is minus 60 percent. One can understand the predicament of the farmers. The fact that there were hardly any rains till mid-July is bound to leave its impact on this year's Kharif. The Agriculture Ministry's latest progressive sowing date reveals a 39-43 percent fall in pulses and coarse grain acreages over last year with 27-30 percent less for cotton and oilseeds. One can surmise that rains falling in August-September, as they did in 2009 and El Nino materializing concurrently, the resultant drought may not wreak real havoc. The effect, if any, all be more on farmers than customers. Therefore, greater stress should be given by the Government to help the farmers than being alarmed now, how to tackle the market.

With incessant rainfall in Odisha, districts like Bhadrak, Balasor, Koraput, Rayagada have been inundated and crops have been destroyed. Centre should come forward to mitigate the problem of farmers of those areas of Odisha.

Finally, I would like to draw the attention of the Government regarding the apathy of the Union Government. Odisha encountered the wrath of cyclone "Phaillin" which devastated large parts of Southern Odisha on 12^{th} October, 2013. The cyclone "Phaillin" coupled with another spell of high flood occurred immediately thereafter affecting the lives and property of the people of that region. Odisha Government had submitted two memorandum to the Union Government seeking central assistance of Rs. 5832.50 crore towards relief and immediate restoration of damaged infrastructure as per the Union Government norms. However, the High Level Committee approved a net assistance of only Rs. 460.30 crore from NDRF. A Supplementary Memorandum has been submitted. We would demand that the actual amount as per the Norms of Assistance from SDRF/NDRF be provided to Odisha at the earliest.

Odisha is facing vagaries of nature, every year, be it drought, flood and cyclone. This year Odisha has to tackle both drought and flood together. Therefore, I would urge upon the Union Government to provide support to Odisha at the earliest to help farmers at large and those affected persons, in particular.

ऑश्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत नदियों का देश कहा जाता है । करोड़ों भारतीयों के आस्था की प्रतीक गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी सहित अपार जलराशि वाली दर्जनों नदियां यहां बहती हैं । परंतु केन्द्र की कांग्रेसी सरकारों की दोषपूर्ण एवं उपेक्षित नीतियों के कारण इस महत्वपूर्ण संपदा का समुचित सदुपयोग नहीं हो सका । इसका दुष्परिणाम यह निकला है कि आजादी के 67 वर्षों बाद भी जहां हमारी साठ फीसदी धरती प्यासी है वहीं प्रतिवर्ष आने वाली प्रलयकारी बाढ़ से जन-धन की व्यापक क्षति होती है । महाराष्ट्र के मालिन गांव की हृदय विदारक घटना इसका ताजा उदाहरण है । जल संसाधन के गलत प्रबंधन के कारण ही देश हर साल बाढ़ और सूखे की त्रासदी झेलता है । वर्ष 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने नालों के नहरीकरण की योजना प्रारंभ कराई लेकिन उस सरकार के जाते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया । इसी तरह माननीय अटल जी की सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की । परंतु यूपीए की सरकार ने आते ही इसे दरकिनार कर दिया गया । मेरी मांग है कि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए । मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार जीवनदायिनी गंगा, यमुना सहित अनेक पवित्र नदियों की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के प्रति कृत संकल्पित है तथा इसके लिए पर्याप्त बजट का भी आवंटन कर दिया गया है। परंतु इसके लिए नदियों के किनारे हो रहे अंधाधुंध अतिक्रमण तथा फैक्ट्रियों द्वारा बहाए जा रहे विषाकत कचरे को समाप्त करने के लिए कठोर कानून बनाकर उसका तवरित अनुपालन कराया जाना जरूरी है ।

महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र घाघरा और गंगा नदियों से घिरा हुआ है । घाघरा नदी के कटवा से देवरिया और बलिया के कई गांव नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं तथा दर्जनों गांवों का अस्तित्व खतरे में है । नदी के कटाव से आबादी एवं कृषि भूमि को बचाने के लिए बाढ़ खंड बलिया ने बहुत समय पूर्व ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जिसका प्राक्कलन भी तैयार करके उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार को भेज दी गई । राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद यह मामला निविदा प्रक्रिया में है । परंतु केन्द्र की पिछली सरकार अपना अंशदान नहीं दिए जाने के कारण जनहित का यह कार्य बाधित है । इनमें प्रमुख हैः-

घाघरा नदी के दायें तट पर निर्मित हाहानाला के किलोमीटर 0.800 से 2.400 के मध्य ग्राम चैनपुर गुलौरा में पंचनहर एवं शिवमंदिर की सुरक्षा हेतु परियोजना रूपये 1095.80 लाख ।

---

* Speech was laid on the Table

डूहा-कठौड़ा विस्तार बांध के किलोमीटर 0.00 से 0.300 के मध्य स्थित बालखंडी बाबा मंदिर एवं आश्रम की सुरक्षा हेतु 300 मीटर में कांचित एवं पीचिंग कार्य रूपये 396.24 लाख ।

डूहा-कठौड़ा रिंग बांध के किमी. 04.200 से 5.200 के मध्य तटबंध की सुरक्षा हेतु परियोजना रूपये 682.50 लाख ।

घाघरा नदी के किनारे तुर्तीपार श्रीनगर बांध के किमी. 39.800 से 41.600 के मध्य ग्राम संगापुर गोड़ौडी, रिंवन, ककरघट्टा, एलासगढ़ के सुरक्षार्थ परियोजना रूपये 1576.60 लाख ।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि जनहित की इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए केन्द्रीय अंशदान को तत्काल निर्गत करावें ।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी यहां बाढ़ और सूखे पर चर्चा हो रही है और उसकी वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है, उससे सारा देश हर वर्ष चिंतित होता है और सारे हाउस में भी उस पर चिंता प्रकट की जाती है। यह एक नैसर्गिक आपत्ति है। नैसर्गिक आशीर्वाद पर कभी बारिश अच्छी होती है या कम होती है, इससे निर्मित परिस्थिति पर हम हर वर्ष परेशान होते हैं। इस बार जो बारिश होने के अनुमान थे, शुरू में उसके संकेत ठीक नहीं थे, संकेत यह थे कि इस बार बारिश कम होगी। लेकिन अभी हाल ही में कुछ राज्यों में बारिश होने से कुछ चिंता निश्चित रूप से कम हुई है। फिर भी बारिश विलम्ब से होने से देश के अनेक राज्यों के किसान चिंतित हैं और उन्होंने जो फसल लेनी थी, उस फसल में भी परिवर्तन करने की नौबत आई है। यह इस वर्ष की बात है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम वर्षों से इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि जो सरकारें थीं, उन सरकारों का काम था कि बारिश होनी है या बारिश नहीं होनी है। कभी बारिश ज्यादा होगी और कभी कम होगी। उनके प्रबंधन की नीति में कुछ परिवर्तन की जरूरत थी, जो नहीं किया गया है।

महोदय, भारत को हम मौसम का देश मानते हैं। यहां हर चार माह के बाद मौसम बदलता है। यह हमारा सौभाग्य है। इसके साथ ही यहां अनेकों नदियां हैं। कभी जब भारत का वर्णन होता है तो इसे नदियों का देश कहा जाता है और इतनी नदियां होने के बावजूद भी नियोजन के अभाव में हम पूरे देश को इन नदियों के जल से सिंचित नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से हर वर्ष बाढ़ की समस्या पैदा होती है और बाढ़ के साथ कभी-कभी सूखे की समस्या भी पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि इतनी जल वर्षा, इतनी नदियां और इतने नाले होने के बावजूद अगर हम ठीक से नियोजन करें तो शायद ही हमें इस देश में सूखे का मुकाबला करने की जरूरत पड़ेगी और शायद ही कभी बाढ़ की आपदा भी निर्माण होगी। अपने सामने एक बड़ा प्रोग्राम रखकर देश की इस बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा। बारिश और सूखा खेती से संबंधित विषय हैं। आज भी देश के साठ परसैन्ट से अधिक किसान और मजदूर परिवार खेती पर निर्भर करते हैं, खेती पर जीते हैं। देश के मजदूर और किसानों के अतिरिक्त देश के सौ प्रतिशत व्यक्ति इस बाढ़ और सूखे से प्रभावित होते हैं और देश का उत्पादन भी इससे प्रभावित होता है। इंडस्ट्रीज भी बिना पानी के नहीं चलती हैं। बिना जल के खेती भी नहीं होती है और बिना जल के व्यक्ति जी भी नहीं सकता है। इस प्रकार से हम यहां एक बड़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं और वहां विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है, पिछली सरकार ने एक नीति बनाई थी कि देश के कितने राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे

हैं। उसमें जो 31 जिले चुने गये थे, उसमें विदर्भ के 6 जिले चुने गये थे, जिस जिले से मैं चुनकर आता हूं। मेरा जिला यवतमाल, चंद्रपुर है। यहां के किसान आत्महत्याएं इसलिए करते हैं क्योंकि यहां उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। देश में एवरेज 60 परसैन्ट सिंचित भूमि दिखाई जाती है, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, दुर्भाग्य से इस बार पंजाब में बारिश कम होने से समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन पंजाब सरीखी स्टेट में 90-95 परसैन्ट सिंचित भूमि है। जबकि आप महाराष्ट्र और साउथ में देखेंगे तो वहां सिंचित भूमि का प्रमाण कम है। देश में 60 परसैन्ट सिंचित भूमि होने का जो एवरेज है, यदि उस एवरेज को मेनटेन भी किया जाता तो शायद हम देश के सूखे और बाढ़ का मुकाबला कर सकते थे। अगर हम हर जगह नदियों पर बैराज बना देते हैं, हर जगह पर छोटे-बड़े बांध बना देते हैं। हम गांव-गांव में जो छोटे तालाब बनाते हैं, उनको भी बढ़ावा देते तो शायद हम इतनी बड़ी समस्या का मुकाबला सहजता से कर सकते थे। जहां महाराष्ट्र में 19 प्रतिशत सिंचित भूमि है वहीं पर किसी स्टेट में 90 प्रतिशत से ज्यादा है। यह असमानता भी है। ऐसे मौके पर मैं कहूंगा कि अगर हम सभी नदियों का अच्छी तरह से प्रबंधन करें, उस पर बांध बनाएं, उस पर बैराज बनाएं तो अच्छा होगा। अटल जी की सरकार ने नदियों को जोड़ने का जो प्रोग्राम बनाया था, उस पर भी अमल करने की जरूरत है। यह भी बाढ़ से मुकाबला करने का और बाढ़ से बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि सूखे से मुकाबला करने के लिए यह इस वर्ष की समस्या नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो कई जिलों के किसानों ने दो-तीन बार बुवाई की है। लेकिन फसल उगी नहीं है। उनकी खेती और मज़दूरी का खर्च और बढ़ गया। अब वहां राज्य सरकार द्वारा सर्वे होगा।

जैसा हमारे साथियों ने दो-तीन बार कहा कि उन्हें इतना कम अनुदान मिलता है कि वह ऊँट के मुंह में ज़ीरा साबित होता है। किसान की इतनी मेहनत और पूरे वर्ष की फसल जब जाती है, तो वह आत्महत्या कैसे रूकेगी। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के अनेक जिलों में अकाल की स्थिति है। पूरे विदर्भ में, मराठवाड़ा में, दो-दो, तीन-तीन बार बुवाई हुई है। आज के विषय - सूखा और बाढ़ की चर्चा पर मैं सरकार से विनती करूंगा कि निश्चित ही महाराष्ट्र में एक सर्वे कराया जाए, अधिकारियों की एक टीम भेजी जाए और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिन-जिन राज्यों में ऐसी स्थिति है, वहां पर निश्चित ही सेंट्रल गवर्मेंट की तरफ से सर्वे होना चाहिए, टीम जानी चाहिए, अधिकारी भेजे जाने चाहिए और कहां कितना नुकसान हुआ है, इन किसानों के जीवन स्तर, किसानों की आत्महत्याएं, इसके बारे में चिंता होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि कई जगहों पर बांधों का काम और बैराज का काम एंवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलने से, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से वर्षों से लंबित हैं। ऐसी कई जगहे हैं, जहां पर अगर हम बैराज बांधते हैं, बांध बांधते हैं या बड़ी परियोजनाएं बनाते हैं तो ये समस्या हल हो सकती है। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि आप इसकी सूची बनाइए। अगर खेती को हम न्याय देना चाहते हैं तो कितने बैराज, कितने बांध और कितनी परियोजनाएं लंबित हैं और कहां पर फॉरेस्ट और एंवायरमेंट क्लियरेंस से काम रूका है, यह सभी मंत्रालयों से कोऑर्डिनेशन कर के, सभी मंत्रालयों के साथ मीटिंग कर के अगर हम यह काम पूरा कर लेते हैं तो शायद हम देश में बाढ़ से भी बचायेंगे और सिंचित भूमि भी बढ़ा सकते हैं। मैं इतनी विनती करता हूँ और चाहता हूँ कि इस बार जहां-जहां पर सूखे की स्थिति है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर निर्भर न रहें, राज्य सरकारें अनेक राज्यों में मदद करती हैं, कई राज्यों में कम मदद करती हैं। इस बार केंद्र सरकार बीच में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*SHRI D. K. SURESH (BANGALORE RURAL):** This year again the State of Karnataka has experienced a worst drought. It is the fourth year in a row. The June month recorded the lowest rainfall in the past 52 years, the state needed 47% deficit rainfall in June. "It is the fourth time in the past 100 years that the State recorded such a low rainfall. The improper rain has affected agriculture activity, drinking water and power generation,"

During monsoon, sowing takes place on an average 74 lakh hectares in the state. By June 30, the average sowing area should have been 25.36 lakh hectares, but is only 18.92 lakh hectares. "Even the rain-fed crops cultivated in Mysore, Mandya, Chamarajnagar, Hassan, Tamkur, Chitradurga, Davangere, Ramanagaram, Dharwad, Bellary, Gadag and Yadgir are withering due to inadequate rains".

Karnataka state government had declared 125 talukas out of 176 talukas (revenue sub-divisions) as drought-hit talukas. The drought-hit areas received less than rainfall with a continuous dry spell for the last 2 to 3 months.

Bangalore Rural is my Parliamentary Constituency which comprises my home district Ramnagar and also Kunigal taluk of Tamkur District. Most parts of my Lok Sabha constituency are badly affected by drought.

Therefore, I urge upon the Union Government to come forward to rescue farmers of the drought affected areas and release adequate funds to take up drought relief measures like providing drinking water, fodder for cattle other livestock and foodgrain supply. My suggestions in this regard are - to take urgent steps to resolve the water crisis, ensure cattle fodder, and jobs for the people:-

The Government should direct authorities concerned to take up the Rejuvenation and Repair of bore wells to provide better access to drinking water.

Crop Insurance should be provided to all farmers irrespective of the size of the land holdings.

Compensation to crop failed due to drought should be given after taking into consideration all the expenditure including the cost of own laborer.

All agriculture laborers should be provided at least 100 days wages during the drought period.

*SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I will highlight the present situation of onset of drought in the country, its impact on farmers and the action we seek from the Centre. Rainfall deficit is the most important indicator of drought in the country. The months of June and July are particularly important since they constitute the sowing period. For the country as a whole, this year's monsoon has so far upto 23 July been 25% below the normal average or long period Average. The deficit, being more than 19 % is clearly a matter of concern. Deficit in Northwest is 36%, in South Peninsula region it is 25% and in Northeast, East and Central region, it is 22%.

The Met Department also divides the Country into 36 subdivisions and categorizes these into normal, deficit or scanty rainfall. As on 27th July, rainfall has been deficit in 21 subdivisions, scanty in 1 division and normal in 14 divisions. 62% of our country has had deficit rain of over 25% since June 2014.The Met department has forecast normal rainfall for the central and eastern regions for the next two weeks but rainfall in Peninsula and western region, as per its forecast is said to be below normal for the next two weeks as well.

As far as sowing of crops is concerned, area sown this year under Kharif crops is 345.60 lakh hectares. It is important to see this figure in comparison to the figure last year. Last year, in the same period, 627.44 lakh hectares of area had been sown under Kharif corp. This reflects a

downfall of over 45% from the last year.

The sheer number of people impacted by drought makes it the most important point of concern right now. The water reservoirs in the country are below the normal storage mark. In 85 reservoirs monitored by Central Water Commission, live storage (as on 17th July) is 40.00 BCM. This figure last year in the same period was 65.73 BCM. This means we have only 61% of the last years' storage.

There is already a water crisis being experienced with regard to availability of drinking water in various parts of the country including Tamil Nadu and Maharashtra. But more importantly, I urge you to consider the situation of farmers in the country. Their misery in times of lack of rainfall needs due attention. Farmer suicides in the agriculture and farming have been very high over the years. In the year 2013, 11,772 farmers had committed suicide. Although there was a decline from the previous year of 2012, the plight of farmers is still a matter of concern. Since drought has a clear link to low agricultural productivity, they are the most directly impacted from this crisis. With the onset of drought, their situation is only worsening everyday. Action is required by the Government.

Time and funds are two crucial factors for States with regard to the present situation. We need to act fast to tackle the issues at hand. Also, the State's ability to deal with such situation is limited due to funding constraints. Drought is not a singular issue; it impacts water availability, fodder, agriculture labour, employment and productivity. I request the Centre to support and aid State Governments with more funds to tackle the situation and step up relief operations in areas where onset of drought is being observed.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Chairman, Sir, I am deeply grateful for having been given this opportunity to participate in such an important discussion.

India is a vast country, and every year, our country witnesses one calamity or the other. The worst affected by such calamities are the poor, the weaker sections, and also, the disadvantaged sections of the society.

Our country is mainly dependent on agriculture, and around 70 per cent of our people are directly or indirectly involved in agriculture for their existence as also, for their livelihood. Agriculture production and productivity depends mainly upon the vagaries of nature and weather plays a critical role in deciding the prospects of our people.

Sir, time and again, we have had the opportunity to discuss the issues relating to flood as well as drought in this very august House. But it always ends up in rituals. What is required is a holistic approach to address the issue of natural calamities.

This year, we have had a deficient monsoon because of the El Nino phenomenon. According to the Indian Meteorological Department (IMD), rains have been deficient by 43 per cent this June. However, we are fortunate to have fairly good rain in July in various parts of the country.

Whenever there is deficit rainfall, it not only affects agricultural production, but also it badly affects the availability of drinking water. It is a paradox that a State like Kerala, which is blessed with more than 40 perennial rivers and which receives heavy downpour during South-West Monsoon and North-East Monsoon, experiences acute shortage of drinking water immediately after the rainy season is over.

All studies go to show that the groundwater level is depleting in the State of Kerala, and it is going to cause an alarming situation in the days to come. The depletion of groundwater is something which is not peculiar to Kerala alone. It is a frightening reality in almost all the States. If we do not enlighten the people on the importance of water literacy, I am afraid the problem of drinking water will soon be the most vital issue being faced by the nation.

Sir, a proposal has come from this Government for linking the rivers of India so that the question of water availability could be resolved. I do not know whether the Government is pursuing this programme with the desired amount of scientific input or precision. We all know that no scientific study as such has been undertaken by this Government when it comes to the question of interlinking of rivers. Rivers are naturally formed water flow systems and tampering with them will only kill the rivers.

We have the Russian experience of linking the rivers during the 1930s when Soviet Russia was at its peak, which led to the doom of their rivers in the 1930s. Our greed and short-sightedness should not lead us to destruction of the environment and ecology, which will be a definite fall-out of diverting the natural course of our perennial rivers. We cannot kill our riverine eco-system by meddling with the nature. Global warming and climate change are clear signals of the dangers which lie ahead.

Sir, water resource is a State subject and before taking such a critical decision, we should take all the State as also all other stakeholders into confidence. The scientific community also must be taken on board before taking such an important decision. I understand the scientific community across the spectrum are against linking of rivers. The major political parties of my State, Kerala, are one when it comes to the question of opposing the proposal to link all the rivers.

Sir, floods cause great havoc year after year and it is a recurring phenomenon witnessed across the country. The Uttarakhand deluge and the spate in the northern rivers opened our eyes and the time has come for us to strengthen our water management system and disaster preparedness. It is a well-known fact that India has gone far ahead in her preparedness to meet any eventuality following any natural calamity. This is amply proved during the Uttarakhand floods as also the Phailin cyclonic storm that has hit the coast of Odisha and Andhra Pradesh last year. The Union Government should take all necessary steps to support the States in their efforts to strengthen their disaster management and preparedness. People also should be enlightened on the paramount need to save themselves as also their fellow citizens. Japan is a good model for us to emulate.

Sir, during every monsoon, the long coastal belt of Kerala is badly affected by sea erosion. Thousands of fisher-folk living along the coastal belt are put to untold miseries. The Government of Kerala is doing its best to meet the situation. Sea walls along the coastal belt is being

constructed by the State Government in a phased manner year after year, but it is a fact that sea erosion continues unabated and it cannot be prevented by constructing sea walls alone. More scientific study is to be made on the issue and more innovative steps are to be taken so that huge damage along the seashore is averted. The Government of Kerala have made a request to the Union Government to include 'sea erosion' as also 'lightening' in the category of natural calamities. I strongly appeal to this Government to consider this matter so that it may be referred to the Finance Commission for its final decision.

I have one last point to make. The hon. Chief Minister of Kerala had come to Delhi several times. He made an appeal to set up a unit of the National Disaster Response Force in the State of Kerala. That proposal is hanging fire for a long time. Unfortunately, nothing has been done. I once again request the Government to consider the matter favourably.

With these words, I thank you, Sir, for having given me this opportunity and I conclude.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I would like to draw the attention of the Government, through you, Sir, to the drought situation in the State of Karnataka. A total of 1016 villages of 125 talukas are facing severe drought condition. A total of 1286 villages were very severely hit by drought. Even drinking water is not available in those villages. Water is supplied through tankers. In many cases, it is reported that there is non- availability of potable water in the villages. Even non-potable water – fluoride water is being supplied through tankers. That is the situation in some of the districts of Karnataka. I am happy to tell that in July, 2014, we have received some amount of rain in some of the districts. The major monsoon season for sowing the crops is the month of June. The State of Karnataka received the lowest rainfall in the last 52 years. The State recorded 47 per cent deficit rainfall in June. We should have received 194 mm of rainfall whereas we have received just 116 mm. It is the third or fourth time in the past hundred years that the State has recorded such a low rainfall. This improper rainfall has affected the agricultural activity. The power situation is very grim. Only five to six hours of power is being supplied in the villages. There is no drinking water. Fodder has become a big issue. In the monsoon, a total of 74 lakh hectares of sowing was to take place. By that calculation, by the end of June, average sowing area should have been 26 lakh hectares but now, it is only 18.92 lakh hectare.

Sir, you can imagine the situation. Water table has gone down in a few districts like Yadgir, Bidar, Ramnagar and many other areas. At least in 7 districts, it has gone as deep as 1500 feet. There is shortage of fodder. Farmers are selling their livestock to the butchers and people are migrating from villages to big cities like Goa, Mumbai. The Karnataka Disaster Management Authority has said that five districts have received excess rainfall like Chikkamagaluru, Hassan, Kodugu and Uttar Kanada in contrast to 19 districts which is still having deficit rain. The districts Yadgir, Dharwad, Ram nagar, Tumkur have received very less amount of rain which is creating a lot of problem not only for the farmers but also to the common people. In the last report of Drought Research Unit of IMD Pune, it mentioned about the aridity condition of the entire nation. That is in India. It includes severe arid condition also in the northern part of the Karnataka. When the situation is so severe, both the Central and the State Governments should come to the help of the farmers. The methodology by which we are helping the farmers is through the National Disaster Management Relief Fund. On the one hand, we are foregoing crores of rupees through NPAs of banks and bigger corporate houses, and on the other, we are paying a very meagre amount to the farmers. Recently, the Kingfisher issue had come up and in one go, we had foregone more than Rs.7,800 crore. Loans have been sanctioned only on personal guarantees. What are we paying to the farmers? It is only Rs.4,500 per hectare on sown area. That means, it comes to around Rs.1,500 for each acre. This amount is for rain fed area. For the irrigated area, it comes to Rs.9,000 per hectare. In the case of perennial crop, it is Rs.12,000 per hectare. When it is Rs.9000 per hectare for irrigated area, that means, it comes to almost Rs.4,000 per acre. For perennial crop, it comes to around Rs.4,500 to Rs.5,000 per acre.

The NDMRF norms provide assistance for any of the natural calamities including drought or flood or earthquake and so on. When the farmer loses the crop and we provide the assistance, it should be linked and calculated on the basis of investment made for the sowing, fertilizer and everything. On that basis, the NDMRF norms should be revised. We had appealed to the previous Government to revise the norms many times. But, unfortunately, it did not happen. The Agriculture Minister is farmer-friendly. I would suggest the Government to kindly look into this matter.

If the farmer lives happily, the entire country will live happily. I would also request the Government for making the improvement in the crop insurance area. There are some States which do it on the basis of the 12th Five Year Plan and some States are doing it on the basis of 13th Five Year Plan. By that, it is creating a lot of problem. So, I would urge the Government that a farmer-friendly crop insurance and weather based insurance scheme should be adopted.

In recent days, the International Rice Research Institute has stated that flood-tolerant rice saves the farmer's livelihood. It has been experimented in many countries like Brazil and others. I would urge the Government to popularise it. For example, if the paddy is full of water even after two weeks, it will not get spoiled. I would urge the Government to kindly consider all these suggestions so that the farmer could be saved. With these words, I conclude my speech.

ऒश्री गणेश सिंह (सतना) : सदन में नियम 193 के तहत देश के विभिनन क्षेत्रों में सूखा एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर जो चर्चा हो रही है उसमें भाग लेते हुए कहना चाहता हूं कि मौसम में हो रहे परिवर्तन से पूरा दुनिया चिंतित है प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है । कहीं तो अतिवर्षा से लोग तबाह हो रहे हैं कहीं अल्प वर्षा से लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं निरंतर जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल को रोकने अधिक से अधिक जल को जमीन के अंदर स्टोर करने की जरूरत है और इसकी शुरूआत श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया है माननीय अटल जी की योजना नदी जोड़ने की उन्हें मूर्त रूप दे दिया गया है और मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने मेरे देश मध्य प्रदेश की काली सिंध, बेतवा, नदी को जोड़ने हेतु डी.पी.आर. बनाकर कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया है।

पूर्व में जलग्रहण योजना में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई थी लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। देश के कई जिले ऐसे है जहां पेयजल का संकट है ऐसे जिलो का चयन किया जाना चाहिए और उन जिलो में दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए। मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां इस वर्ष कम वारिश होने के कारण बोई

गई फसल का अंकुरन नहीं हो पाया, और किसनों को कड़ी आर्थिक क्षति हुई है ।

प्रदेश में कम वर्षा वाले जिले सतना, दतिया, धार, सागर, विदिशा, रीवा, सिंगरौली अनुपपुर, गुना, सीधी, शाजापुर , आगर मलवा देवास, अशोकनगर, नीमत , दमोह, छत्तरपुर श्योपुर, रतलाम, मंदसौर ढिढोरी, ग्वालियर, पन्ना, शहडोल, उमरिया, भिण्ड एवं मुरैना जिलो में अत्यंत कम वर्षा से फसलों को भारी नुकसान हुआ है । मेरी मांग है कि किसानों को उसके नुकसान की भरपायी की जाये मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष सोयाबीन तथा चना मसूर की जो फसलें नष्ट हो गई थी ऐसे पिड़ित किसानों को सहायता दिये जाने हेतु धनराशि की मांग की थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला ।

मेरी मांग है तत्काल राहत राशि दी जाये, मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना, जबलपुर, कटनी, रीवा, जिले के 205 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी वरगी बांध की दयी तट नहर से पहुचाना प्रस्तावित है उस परियोजना को राष्ट्रीय परियाजना में शामिल किया जाये प्रस्ताव विचाराधीन है यह योजना लगभग चार हजार करोड़ की है ।

---

* Speech was laid on the Table

हमारे देश की खेती भगवान भरोसे है जिससे किसान लंबा घाटा उठा रहे हैं आत्म हत्या कर्ज से डूबने के कारण करने हेतु मजबूर हो रहे हैं ।

खेती के घाटे के धंधे को फायदे का बनाने के लिए अब तक के तो प्रयास किये गये हैं वह अपर्याप्त है, केन्द्र सरकार से मेरी मांग है यदि किसानों को बचाना है तो 100 प्रतिशत फसल बी योजना लगाना पड़ेगा । किसान की खेत को ईकाई बनाना होगा । प्रीमियम की राशि का 80 औ हिस्सा शासकीय खजाने से भुगतान करना होगा, तभी किसान आगे बढ़ पायेग, अन्यथा खेती के धंधे को छोड़ना देगा ।

कृषि के लिए पानी की जरूरत है और उसके भंडारण के लिए सरकार को दीर्घकालीन योजना को अंतिम रूप समयबद्ध बनाना होगा ।

मेरे क्षेत्र सतना में मैहर तथा अमीरपाटन क्षेत्र में किसान पान की खेती करते हैं लेकिनह उन्हें अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला । पान वाटेज से बीमा तथा राहत सुविधा से वंचित रखा गया है उसे शामिल किया जाना चाहिए ।

बाढ़ एवं सूखे से बचाव के लिए निम्न लिखित सुझाव है,

1. नदी जोड़ों अभियान,
2. वर्षा जल का संग्रहण
3. वर्षा जल को रोकने वाले किसानों को अनुदान
4. खाली पड़ी भूमि में जलसंग्रहण की अनिवार्यता
5. मध्य प्रदेश में अटल ताल योजना, को पूरे देश में लागू करना
6. प्रत्येक निजी क्षेत्र में लगे उद्योगों को वर्षा जल रोकने का टारगेट देना
7. जलाशयों को पुनर्जीवन देने हेतु वित्तीय सहायता
8. कुओं के वर्षा जल रिचार्ज करने हेतु योजना बनाना
9. जंगलो एवं जहाड़ों से आनेवाले नाले जो सीधे नदियों में जाकर वह जाते हैं उनका रास्ता बदलकर तथा छोटे-छोटे जलाशयों का निर्माण करना
10. मेरे लेकसभा क्षेत्र में प्रत्येक नं0 3 पंचायतों में एक-एक बड़े जलाशयों का निर्माण कराया जाना

अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा राहत एवं बचाव कार्य हेतु वही धनराशि दी जाती है लेकिन उस धनराशि का भयंकर दुरूपयोग हुआ है उसकी जांच करायी जाये ऐसी मेरी मांग है ।

लोगों का विश्वास मौसम विभाग की भविष्य वाणियों से उठता जा रहा है उसे और कारगर बनाने की जरूरत है ।

पुराने समय में ऐसी प्राचीन प्राकृतिक संकेत होते थे जिनके चलते ग्रामीणों को पूर्व में ऐसी आपदाओं के क्षति के संकेतों का पता लग जाता था, ऐसी पुरानी पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के लिए कारगर योजना बनाने की जरूरत है ।

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली): आज़ादी को 67 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आज तक हर बार लोक सभा में सूखे और बाढ़ पर चर्चा होती आई है। बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रतिवर्ष राहत हेतु लगभग 1 लाख करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की जाती है। देश के आधे राज्य सूखे तथा आधे राज्य बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। इन दोनों समस्याओं से Suffering बहुत होती है, जिसकी गणना करना संभव नहीं होता। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए विस्तृत चर्चा का समय आ गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के समय सड़कों और नदियों को जोड़ने का सपना देख था, सड़के तो जुड़ गई अब समय है नदियों को जोड़ने की योजना बनाने का। इस योजना में मोटे रूप से लगभग 5 लाख 60 हज़ार करोड़ रूपये की धनराशि खर्च होनी है, जिसके लिए 10 वर्ष की योजना बनना भारत जैसे देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। धन जुटाने के लिए विदेशी सहायता ली जा सकती है, जिसे किश्तों के माध्यम से चुकाया जा सकता है।

नदियों को जोड़ना ूसूखे व बाढ़ की समस्या का ही हल नहीं बल्कि इसके माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध करवाने के साधन भी उपलब्ध होंगे, कृषि हेतु सिंचाई के लिए भी उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। कृषि में विकास होने पर जी.डी.पी. में कृषि का योगदान बढ़ेगा और देश तेजी से विकास के मार्ग की ओर बढ़ेगा।

हमारे देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यह सर्वविदित है कि मानसून 5 वर्षों में लगभग 2 बार ही ठीक रहता है, जिसका किसान पूरा-पूरा लाभ ले पाता है। वर्षा का जल संचय करने में भी हमारा देश काफी पीछे है। हमारे देश में वर्षा के जल का 6 प्रतिशत हिस्सा ही काम में लिया जाता है बाकी 94 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। यदि इस 94 प्रतिशत पानी का बांधों के माध्यम से संचय किया जाता है तो इसके माध्यम से 25 मिलियन हैक्टेयर पर सिंचाई की जा सकेगी, 24000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा तथा 10 मि.ली. हैक्टेयर क्षेत्र के ग्राउण्ड वाटर में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। इसके साथ-साथ देश खाद्यान्न, फल, सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक देश भी हो सकता है और हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। देश के किसान को खेती व युवाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे तो देश को फूड सिक्योरिटी व मनरेगा जैसी योजनाएं चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों रूपये बचा कर इफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है, ताकि देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि के क्षेत्र में भरपूर विकास किया जा सकेगा।

कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के अलावा कृषि को संरक्षण की भी आवश्यकता है। सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को पिछले तीन सालों में 2.5 लाख करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि तथा 2.5 लाख करोड़ रूपये की विभिन्न छूटें प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र को भी इस तर्ज पर प्रोत्साहन राशि व छूट देने की भी आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नदियों को जोड़कर सूखे व बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे राज्यों को राहत देने की योजना तैयार करने की कृपा करें।

* **DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY) :** Floods and drought are a recurring feature. Management of floods is a state subject. But the stark reality is that states always face financial crisis. States become hapless and helpless. Coming to my state, West Bengal, last year floods affected districts, resulting in paddy output drop by more than 30%.

West Bengal has not only faced the brunt of floods but also heat spell. In April-May, 2014, due to heat spell, jute cultivation in West Bengal suffered heavily. There was a drought like situation in April-May, 2014 (specifically in districts in South Bengal). When rains are deficient; heat spell hover around; and at some other time, floods creates panic, people of West Bengal are put at high risk and great distress. Added to this, West Bengal Government, which is already in financial quagmire, face the daunting task of taking care of these natural calamities-floods and droughts.

There were reports of El Nino effect in India which resulted in drought or may result 2014 in drought. EI Nino would lead to a weak monsoon. Without the help and assistance in every form, how the State Government fend for itself? It is a known fact that Centre offers very little in the form of financial assistance to States. Past experience proves this analogy.

When the Government of India is having paraphernalia to study, analyse and act in advance, why is the Central Government not taking appropriate steps to address floods and droughts, well in advance, by extending data or information or by allocating funds to attend to the after-effects of droughts and floods? I want a straight answer from the hon. Minister.

It is worthwhile to note here the remarks of the Finance Minister, and I quote : "The Centre will give complete support.". These are the remarks of the Finance Minister while addressing a conference of State Food Ministers. Hoarding and rise in food prices are the outcome of below normal monsoon. How would the State act in such a multifarious problems being faced by it? There was no panic situation.

Ministry of Agriculture data shows that West Bengal have received sub-normal rainfall. West Bengal Government which is in the financial

crisis created by the 34 years misrule of Left Front Government, how can it tackle natural calamities like receiving subnormal rainfall, 9 districts of West Bengal facing floods last year? There is a need for the Central Government to give special emphasis and importance to those states which face the nature's brunt almost every year; or twice or more every year, backed by 34 years misrule of Left Front Government. I hope the hon. Minister, who is privy to the financial problems of West Bengal Government and knows its predicament, should come forward and announce special financial package to tackle impending floods, El Nino effect, heat spell, deficient rainfall, etc.

Would the hon. Minister like to assure the Government of West Bengal and the Members of Parliament from West Bengal to this effect?

National Disaster Response Fund should be used generously when it comes to West Bengal Government which is not financially sound. I would also urge the Central Government to see that more funds are allocated to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana and other schemes to mitigate the situation of deficient rainfall in West Bengal?

The hon. Minister of Agriculture, Shri Radha Mohan Singh has stated that Central Government is ready to meet deficient monsoon. I would like to know how ready it is to face the nature's wrath. What about facing the floods which is looming large in some states, including West Bengal?

It is reported in the Press that Centre has prepared contingency plans for 500 districts to face drought. Would the Government state how many districts of West Bengal picture in the said contingency plan, as drought is looming large in West Bengal?

Would the Centre inform the august House about tackling floods in the coming months? Is our flood warning system working well? An estimated 8.35 lakh population of West Bengal was affected during floods in 2013; West Bengal lost 112 lives in 2013 due to floods; and the total damage is to the tune of Rs.4114 lakhs.

In the end, I would like to summarise a few important points. There is an urgent need to take preventive measures to face floods. Efforts should also be undertaken to ensure full utilization of flood water. Erosion of arable land by floods is a major problem, which needs to be attended to by the Central Government on war footing. Will an Action Plan be put in place at the Centre as well as state level, which should be reviewed at regular intervals? Losses incurred by floods and drought by States should be adequately compensated. An expert body should conduct study on floods and droughts and come out with remedial measures and recommendations to be followed by the Centre and States in letter and spirit.

Our Trinamool Congress Government in West Bengal, headed by Kumari Mamata Banerjee, the Chief Minister has been doing outstanding work, with limited financial resources, for the poor and disadvantaged people of society. We would strive harder in future too to see that common man is not affected by floods and droughts.

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I express my profound thanks to you for according me this opportunity to speak. I also thank my Party Chief Dr. Purtachi Thalaivi Amma from the bottom of my heart for reposing tremendous confidence in me; but for whose benign grace and immense kindness, I would not have found myself here now.

Allow me to congratulate the hon. Member who has initiated this discussion on the Flood and Drought Situation in India. This debate could not have come at a more appropriate time than this since the South West monsoon is blowing across the landscape of India, although ever so slowly.

The Southwest Monsoon has set in rather late and the country is predicted to receive less than normal rainfall. The prediction is based on the El Nino factor and owing to it India would face a drought like situation this year that would affect the lives of crores and crores of people. So, it is high time we really made a scientific study of this El Nino factor so as to analyse the prospective consequences and its implications so far as our agrarian projects are concerned.

Sir, the fate of Indian agriculture is dependent on the vagaries of climatic conditions prevalent in India. It is tossed up between the two extremes, of floods on the one hand and the droughts on the other. When we receive significant monsoon rains, the waters charge up the rivers to create a spate. Floods in India occur with regularity every few years. The floods take a toll of hundreds if not thousands of lives, almost every few years; and we have become numb to the spectacle of seeing dead bodies strewn over the ground. It is not unoften that we see that whilst one part of India is reeling under the rivers in spate, another part of India suffers from the pangs of drought. We have become psychologically acclimatised to living under these ironic conditions.

In the recent years, we have seen that Brahmaputra rose in spate and caused havoc in the North-Eastern States. So also we have witnessed the gory spectacle of Kedarnath being washed away in the floods. Yet, we are still not prepared enough to handle this kind of situation. At times, even Chennai gets floods due to cyclonic formations in the Bay of Bengal. Of course, of late, this is being handled with great preparedness and efficiency.

In our nation though death, displacement and disease come in the wake of floods, we are too poorly equipped to handle such situations. Flooding is regarded as a natural disaster. The mechanism put in place to handle the floods has hardly risen to the occasion. The National Disaster Management Authority, created under the Disaster Management Act, 2005, is hardly well equipped to handle this sort of situation. More often than not it is the armed forces that come to the rescue of the people afflicted.

Sir, this being the situation of flood-stricken India on the one hand, drought which is characterised by shortage of food and water is brought about by the failure of monsoons. Drought in the subcontinent is caused by the failure of successive monsoons and consequent to receipt of inadequate rainfall over a long period of time. It appears from history that between 18th and 20th centuries more than 60 million people have died of famine and drought in India.

Therefore, we need to undertake a sincere and earnest study of the causes, particularly of the El Nino factor which is said to be affecting our climatic condition. It appears that El Nino - which stands for the 'small boy' meaning Christ - which causes a rise in the temperatures of the Pacific Ocean, affects not only the climatic condition in the South and Northern Americas but brings drought and dry climate over India. We need to undertake a study of this matter. So also, we need to apportion the available water resources, particularly those in the inter-State rivers amicably and sensibly.

I thank you for having given me this opportunity.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने नियम 193 के अधीन देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में जो चर्चा योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया।

यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। हर वर्ष देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति रहती है और लगभग पिछले 60-70 वर्षों से, खास करके आजादी के बाद से इस प्रकार की चर्चा होती आई है, परन्तु इसका कोई परमानेंट समाधान, ठोस समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। यह सही है कि आज दिनों-दिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। जो 1951 में एक करोड़ हैक्टेयर था, वह आज सात गुना बढ़कर सात करोड़ हैक्टेयर हो गया है। वही स्थिति कमोबेश इस देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र की भी है।

मैं हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। इस बात की हम सब लोग चर्चा करते हैं कि इस देश में कहीं पर बाढ़ होती है, तो उसी समय किसी दूसरी जगह सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। पहाड़ों की अपनी एक अलग स्थिति है। जो हिन्दुस्तान के 11 पहाड़ी राज्य हैं, उन राज्यों में भी बरसात के दिनों में बादल फटने आदि की घटनाएं घटती रहती हैं। आजकल भी अखबारों की सुर्खियों में लगातार देखने में आता है कि कभी उत्तराखण्ड में बादल फट रहे हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में बादल फट रहे हैं। इस प्रकार की ये स्थितियां हमारे पहाड़ी क्षेत्र में चली आ रही हैं।

पिछली टैन्योर में, 2009 में मैंने प्राइवेट मैम्बर्स रैजोल्यूशन के माध्यम मेने यह विषय उठाया था, जो कि उस समय का पहला प्राइवेट मैम्बर्स रैजोल्यूशन था। उसमें हमने इस बात को रखा था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जो हमारे 11 पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए अलग से हिमालयन डैवलपमेंट बोर्ड गठित करना चाहिए, क्योंकि, वहां की विकास के लिए जो परिस्थितियां हैं, उसके लिए अलग से इस प्रकार का मंत्रालय हो। अगर इस प्रकार का डैवलपमेंट बोर्ड गठित किया जायेगा तो वहां की परिस्थितियों के अनुसार वहां प्लानिंग होगी, वहां के लिए नीतियों का निर्धारण होगा। हमें इस बात की खुशी है कि इस बार एन.डी.ए. की सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी है, उसने इसे गम्भीरता से लिया है। हमें उम्मीद है कि हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से इस प्रकार की नीतियां आने वाले दिनों में बनेंगी।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे 11 पहाड़ी राज्य हैं, इनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के साथ एक खास अन्याय होता चला आ रहा है, क्योंकि, नोर्थ ईस्ट के जो हमारे आठ राज्य हैं, उनको अलग कर दिया गया है और जो हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड हैं, जहां पर बहुत सी बर्बादियां इस बरसात में होती हैं, आपने पिछले वर्ष देखा कि हमारा केदारनाथ मंदिर किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, सैंकड़ों सैलानी जो वहां पर गये थे, वे उसमें दब गये। इसी तरह कल ही हमारा टिहरी में घनसाली गांव है, वहां पर काफी लोगों को परेशानी हुई है, उसमें वे मरे हैं।

इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी चार दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 6-7 पंचायतों में बादल फटने से वहां पर जो सेव के बगीचे हैं, वे पूरी तरह से तहस-नहस हुए हैं। माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो आपका नेशनल कैलेमिटी फंड दिया जाता है, वह खास करके 80:20 की रेश्यो से दिया जा रहा है। इसमें 80 प्रतिशत सैण्टर देता है और 20 प्रतिशत प्रदेश देता है। जहां पर इस प्रकार की कैलेमिटी होती है, वहां पर यह दिया जाता है। परन्तु हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं, जैसे अभी जोशी जी भी कह रहे थे कि ये नैचुरल कैलेमिटी फंड के जो नोर्म्स हैं, वे बहुत ही हास्यास्पद हैं। किसी किसान का, किसी व्यक्ति का लाखों रुपये का नुकसान होता है, उसकी लाखों रुपये की बिल्डिंग गिर जाती है और जब वहां पर पटवारी, तहसीलदार या एस.डी.एम. जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स जाते हैं तो वे मात्र कुछ सैंकड़ों में, हजारों में वहां पर कहकर आते हैं कि यही आपका हिसाब-किताब बनता है, यह बड़ी परेशानी की बात है। बहुत से सांसद लगातार इस बात को कहते आये हैं कि यह आपके जो नैचुरल कैलेमिटी फंड के नोर्म्स हैं, ये आपके बदलने चाहिए।परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कितना नुकसान हुआ है, उसके अनुसार वहां का मुआवजा अगर दिया जाएगा, तो वह बहुत अच्छा रहेगा।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए पिछले दिनों जो कैलेमिटी रिलीफ फंड दिया गया था, वह 245 करोड़ रूपए था। मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक 95 करोड़ रूपए ही रिलीज किए गए हैं। न जाने क्यों अभी तक वह किश्त रोकी हुई है? पिछले दिनों प्रदेश की सरकार ने भी इस बारे में आपसे शायद बात की होगी। इसमें जो आपके नॉर्म्स हैं, उसमें स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है, वह एकार्डिंग टू दी पॉपुलेशन यानी उसके साइज के अनुसार दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कम है, परन्तु जो उसका ज्योग्राफिकल और ट्रॉपिकल एरिया है, वह बहुत ज्यादा है। इसी तरह से मैं उत्तराखंड की बात कहूं, जम्मू-कश्मीर की बात मैं कहूं, तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली केन्द्रीय सरकार को लानी चाहिए। केवल मात्र आप साइज के अनुसार न करें, इसके साथ-साथ ज्योग्राफिकल साइज भी आप देखेंगे तो वह ज्यादा बेहतर होगा।

ये जो सारी परिस्थितियां आज बन रही हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लिए आप अलग से प्लान बनायें। जो वहां के कुएं हैं, जो बड़े वाटर बांड्स हैं, उनके लिए आप अलग से पैसे का प्रावधान करें। जो पानी ऊपर से पहाड़ से आ रहा है, जो पानी नीचे पहाड़ों में आता है और फिर वह नदी, नालों में बहकर सारी सिल्ट नदियों में चली जाती है, उसके लिए हमको वहां पर छोटे-छोटे चैक डेम बनाने पड़ेंगे। उसके दो लाभ होंगे, एक तो उनसे पानी रूकेगा, पानी रूकने का फायदा यह होगा कि वहां पर वाटर लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ ऊपर से जितनी भी सिल्ट आ रही है, गाद आ रही है, वह ऊपर ही पहाड़ में रूक जायेगी। हमारी नदियां जब सिल्ट से भर जाती हैं तो मैदानी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह की स्थिति बन जाती है क्योंकि नदी का लेवल ऊपर गाद की वजह से हो जाता है, उसमें भी कमी आयेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Discussion under Rule 193 on the flood and drought situation in the country.

Natural calamity is a serious negative event which includes mainly floods, cyclones, earthquakes, droughts, tsunamis, health disasters, etc. Natural calamity can cause immense loss of life and property. Different parts of our country are vulnerable to different types of natural calamities affecting the lives and property. It is mostly the economically and socially weaker sections of the society which are seriously affected both in terms of human lives and property and most importantly their livelihood.

The impact of the disaster depends on the severity, frequency, magnitude and intensity of the disaster. It also depends on the resilience of the people and their ability to recover.

We have witnessed varied types of natural disasters, the recent one being the Uttarakhand flood causing deaths of thousands of people and damaging property. Kurnool town, which is a part of my constituency, suffered severe damage on account of floods, locking people for over a week without food and sanitation facilities. Cyclones are a regular feature in Andhra Pradesh. On the other hand, Rayalaseema, where my constituency lies, is a perennially drought prone area and people are suffering for want of drinking water and irrigation facilities.

Having accepted that natural calamities are a recurring phenomenon in our country, we must find ways to face them and minimize their affect. An integrated approach is required for this. The local bodies and the governmental departments must be empowered to quickly rise to the occasion so that the damage to life and property could be minimized. Similarly, the local people must be prepared to face such eventualities and must have a stronger say in recovery and rehabilitation programmes.

The Government shall also take necessary steps to prevent disasters occurring for lack of foresight. The Kurnool flood is an appropriate example in this regard. These floods could have easily been avoided with a little foresight by releasing water from the downstream projects.

Once we are faced with disaster, the response and mitigation mechanisms are very crucial in minimizing the damage. Protection of people and their livelihood should be given top priority in managing the natural disasters. We need an integrated approach and strong coordination among the Departments involved in managing the disasters.

The National Disaster Management Authority is a right step in combating the natural disaster though there is a lot to be done in making this Authority more effective in dealing with natural disasters. I am afraid that the noble objective of creating this Authority has not been fully achieved. From the past experience, we can learn lessons and make this Authority much more pro-active and responsive to meet the challenges that lie ahead.

I am sure that this Government will definitely take a re-look into the functioning of NDMA and would strengthen the organisation right up to the district level to make it much more meaningful and effective in handling the natural disaster so as to minimise the loss of valuable human lives and property.

I would conclude by stating that my State, Andhra Pradesh, is regularly hit by floods or droughts. Rayalseema has been facing severe drought for the past two decades. Hence, special attention may be given by the Centre to support these drought-hit districts and thereby promote peaceful living.

*श्री नारणभाई कछाड़िया (अमरेली)ः भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1999 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अमल में लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर होने वाले खतरे जैसे की बवन्डर, सूखा, बाढ़, बरसात इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन में होने वाली फसल के नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। गुजरात राज्य के कुल 188 लाख हैक्टेयर भौगोलिक विस्तार में से 97.45 लाख हैक्टेयर का विस्तार खेती-बाड़ी में उपयोग होता है। गुजरात के सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में बरसात की कमी के कारण वर्ष 2012 में फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। राज्य की 45 तालुका के 59,500 किसानों को उनकी फसल के बीमा-दावों को कृषि बीमा कम्पनी के द्वारा मंजूर किया गया था, जिनका आज तक पूर्व सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, और न ही इस विषय पर कोई कार्यवाही हुई है, जबकि किसानों के द्वारा बीमे की सारी किश्त जमा की जा चुकी हैं। इस कारण किसानों में काफी असंतोष और गुस्सा है। किसानों को उनकी फसल के बीमे की राशि मिले और उनके साथ न्याय किया जाये। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय में जल्द से जल्द कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री भरत सिंह (बलिया) : अधिष्ठाता महोदय, सूखा और बाढ़ के संबंध में हो रही चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, बलिया लोक सभा क्षेत्र के सबसे इंटीरियर इलाका लोकनायक जयप्रकाश जी की जो जन्मभूमि है-सिताबदियरा, उस इलाके में पिछले 20 दिनों से घाघरा का कटान इतना तीव्र है कि इब्राहिमाबाद नोबरार जिसे आठगांवा गांव कहते हैं, उस गांव के कम से कम 150 घर घाघरा में विलीन हो गए हैं। प्रतिदिन 10 से 15 घर कट कर घाघरा नदी में गिर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, हम लोग 16 मई को लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तब से मैं इसके लिए प्रयासरत हूं। मैंने बलिया लोक सभा क्षेत्र के इस कटान और वहां के बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा अपने प्रधान मंत्री जी और अपने जल संसाधन मंत्री जी को भी सुनाई थी। मैंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के संज्ञान में भी इस बात को लाया था।

मान्यवर, जिन गरीब लोगों के घर गिरे हैं, उनमें से 90 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वे दूसरे जगह जा कर जमीन खरीद कर बस जाएं। वे लोग बकुलाहा-संसारटोला बंधे पर बसे हुए हैं। जहां वे डेरा डाले हैं, वहां उनके लिए टेन्ट नहीं है। उनके पास लाइट नहीं है। उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वे लोग दो-तीन किलोमीटर से पानी ला कर पी रहे हैं। इतने कारुणिक हाल हैं, वहां घर गिर रहे हैं। जहां घर गिरते हैं, वहां महिलाएं इतनी कारुणिक सीन उपस्थित करती हैं कि उसे आप देख नहीं पाएंगे। हम चौथे दिन वहां गए थे। हमें हजारों लोगों ने घेर लिया।

मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार का, आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुश्री उमा भारती जी का और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बगल में बिहार है। बिहार में भी कटान है। बिहार के कलैक्टर, एसपी, अधिकारी, हमारे माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह का क्षेत्र है। वहीं रूडी जी का क्षेत्र लगा हुआ है। वहीं श्री आर.के. सिंह, पूर्व गृह सचिव का भी क्षेत्र मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में जमीन-आसमान का फर्क है। बिहार के अधिकारी कदम-कदम पर मौजूद हैं। वहां कटान पीड़ित लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कटान पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता दी जाए। उन्हें बसाने के लिए सुरक्षित जगह पर प्लॉट दिए जाएं।

मैं दर्जनों गांवों के नाम गिनाना चाहता हूं। पिछले साल जगदीशपुर, भुसौला, नरदरा, गडेरिया एवं श्रीनगर गाजीपुर के शेरपुर सेमरा आदि गांव गंगा में विलीन हो गए। आज भी हजारों लोग सड़कों पर हैं। कई लोगों ने स्कूल में शैल्टर लिया हुआ है। अभी तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अभी तो शुरुआत है। अभी डेढ़ सौ घर ही गिरे हैं। अगर यही स्पीड रही तो हजारों घर गिर जाएंगे। यह वे लोग हैं जो सदियों से वहां बसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन इस पर ध्यान दे।...(व्यवधान) घाघरा के कटान से तीलापुर, दतहा का इलाका प्रभावित है। अभी कटान चालू नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जब नेपाल का पानी छूटेगा और बाढ़ और बढ़ेगी तो यह इलाका भी खतरे में आ जाएगा। ...(व्यवधान) मुझे एक मिनट और बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान) तीलापुर इलाके के लिए व्यवस्था की जाए। जो लोग सालों से कटान पीड़ित हैं, उन्हें बसाने की व्यवस्था की जाए। गंगा या घाघरा में जिनके घर गिर गए हैं, उन्हें बसाने की व्यवस्था की जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजे में भेदभाव करती है। किसी को 90 हजार रुपये देती है तो किसी को 35 हजार रुपये देती है। शासन के सामने हर व्यक्ति बराबर है। इसलिए सबको एक तरह की सहायता दी जाए। ...(व्यवधान) बलिया के अधिकारी जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है, वे कान में तेल डालकर सो रहे हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाए।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐसा विषय है जिस पर इस सदन में बहुत बार चर्चा हुई है। बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा होती है। इससे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सम्पूर्ण देश प्रभावित है। काल खंड में कभी उत्तर, कभी पश्चिम, कभी पूर्व तमाम देश इससे प्रभावित होता है। हमें किसी ठोस निर्णय पर आना चाहिए। हम इस चर्चा के माध्यम से आज कोई तफसील में बात नहीं करना चाहते। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दो-तीन सवालों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

17.00 hrs.

उत्तर बिहार का अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। नेपाल से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए जो प्रबंधन किया गया है, उसके तहत वहां हमेशा दीवार खड़ी की जाती है। लेकिन उसके अंदर जो सिल्टिंग हो रही है, उसे कभी डीसिल्ट नहीं किया जाता। हम दक्षिण बिहार के रहने वाले हैं इसलिए उसे झेलते नहीं हैं। हम सुखाड़ झेलते है, लेकिन बाढ़ देखते हैं। जब बाढ़ देखने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि लंबे दिनों से अवैज्ञानिक तरीके से बाढ़ के दिनों में तटबंध को मजबूत किया जाता है। सालों-साल तटबंध ऊंचा होता जा रहा है, गांव नीचा होता जा रहा है और रीवरबेड भी ऊंचा होता चला जा रहा है। इस अवैज्ञानिक तरीके से जो प्रबंधन किया जा रहा है, यह एक खतरनाक संकेत है। यही कारण है कि पिछली बार जब उत्तर बिहार में बाढ़ आयी, तो उसकी विभीषिका से लाखों लोग प्रभावित हुए। वहां रिहैबिलिटेशन के नाम पर बहुत खेल-तमाशा हुआ, लेकिन अभी तक जो लोग विस्थापित हुए थे, उनके लिए कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमने बचपन में एक बार दक्षिण बिहार के इलाके में बाढ़ सुनी थी, लेकिन उसके बाद बाढ़ कभी नहीं आयी। हमें प्रतिवर्ष सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। इस बार ऐसी स्थिति है कि सोन नहर में भी पानी नहीं है। वहां पानी के लिए काफी हंगामा होता है। जहां केनाल नहीं है, फल्गू, मोराहर, तिलइया-ढाढर है, जहां ये सब नदियां हैं, वहां पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। हमारा पहाड़ी इलाका है। यहां विंध्य पर्वत की श्रृंखला कैमूर से लेकर जमुई तक है। उस सारे इलाके में बरसात के दिनों में भी पानी का संकट है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर संकट की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। हमें जल संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। सरकार ने संकल्प लिया है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में भी यह तय हुआ था कि नदियों को नदियों से जोड़ेंगे। हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि वहां पीडीएस योजना कहकर कई बार आंदोलन भी चला। जब नीतीश जी वहां के मुख्य मंत्री बने तब भूल गये। नीतीश जी के साथ हमने भी पदयात्रा की थी। उस प्रस्ताव को वे भूल गये। कुनकुन, दर्दा, मोराहर परियोजना पर काफी आंदोलन भी हुआ था। जब वे सरकार में नहीं थे तब हम भी उस आंदोलन में शरीक थे। लेकिन हम सरकार

से अनुरोध करना चाहेंगे कि कुनकुन को यदि दर्दा से लिंक किया जाये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने एक मिनट में ही घंटी बजा दी। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, घंटी समय पर ही बजती है।

डॉ. अरुण कुमार: ठीक है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

आप घंटी बजाकर गाड़ी पटरी से उतार देते हैं। मैं जबरन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उस आदत का नहीं हूं। मैं केवल एक सलाह देना चाहता हूं। तेरहवीं लोक सभा में मैं एनर्जी कमेटी का मैम्बर था। उस समय भारत सरकार ने नेपाल से निकलने वाली नदियों के ऊपर एक रिपोर्ट बनायी है कि यदि बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल से त्रिपक्षीय समझौता हो, तो उससे 85 हजार मेगावाट क्षमता वाली हाईड्रो इलैक्ट्रिक पैदा की जा सकती है। यह भारत सरकार की एक रिपोर्ट है। यदि डीसिल्ट और इम्बैंकमैंट की स्ट्रेन्थिंग का काम होता है, तो उससे बेहतर है कि एक ठोस योजना बनाकर हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर को पैदा किया जाये। इससे पानी की बढ़िया टैपिंग भी होगी और उससे बर्बादी, तबाही नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, आपने सूखे के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई जून माह के अंत तक हो जाती है। लेकिन इस बार समय पर वर्षा न होने के कारण समय पर बुआई नहीं हो सकी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में बरसात हुई, वह भी सम्पूर्ण क्षेत्र में न होकर कुछ ही भागों में वर्षा हुई है। एक भाग में वर्षा हुई, तो दूसरे भाग में आज भी सूखा पड़ा है और बुआई का समय खत्म हो चुका है। जिसके कारण किसानों को जितना फायदा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है। क्षेत्र में चारे व पानी की विकट समस्या है। चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। जून के अंतिम सप्ताह में चुरू जिले में कहीं-कहीं वर्षा हुई, उसी दौरान किसानों ने फसल की बुआई की थी। लेकिन दुबारा देरी से वर्षा होने के कारण, वह फसल नष्ट हो गयी और इसके कारण दो-तीन बार फसल की बुआई करनी पड़ी, जिसके कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। The Rajasthan Government has demanded financial assistance from the Centre in the wake of drought-like situation. The State is facing over 80 per cent rainfall deficit leading to shortage of drinking water in many districts.

सभापति महोदय, आजादी के बाद मेरे क्षेत्र में अधिकांश समय सूखा पड़ा है। लोगों को अकाल के समय हमेशा दूसरे स्थानों पर काम करने के लिए पलायन करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई परियोजना का पानी मिलता है, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। वर्ष 1981 में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए पानी के समझौते के मुताबिक 8.6 एमएएफ पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था, जिसमें से 0.6 एमएएफ पानी आज भी नहीं मिल रहा है, जो नर्मदा के पानी से भी ज्यादा है। At the meeting held during 12-15th January, 1982, the Secretary of the BBMB decided that the reasonable requirement of Rajasthan for irrigating Nohar and Sidhmukh areas by flow is assessed as 0.47 MAF. The Bhakra areas being served by Southern Ghaggar Canal and Jandwala distributary should be transferred to Rajasthan feeder and the water thus saved be diverted to Nohar and Sidhmukh areas to convey 0.30 MAF. The remaining 0.17 MAF shall be diverted to Rajasthan ex. Nangal via BML, after it is restored to its original capacity. Taking immediate action for restoration of BML to its original capacity had already been decided in a meeting held on 7th November, 1981.

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सिद्धमुख कैनाल व अमर सिंह बैराज को आवंटित पानी का पूरा हिस्सा इस क्षेत्र को नहीं मिल रहा है और इसके लिए संघर्षरत है। राजस्थान सरकार व सांसदों ने इस पानी की मांग के लिए हमेशा अथक प्रयास किया है। सरकार ने कई बार पत्र लिखे, लेकिन राजस्थान को पानी का पूरा हिस्सा न मिलने के कारण लोगों में भारी आक्रोश है। अगर यह पानी किसान को मिल जाता है, तो किसान तो लाभांवित होगा ही, साथ ही देश को अनाज का विशाल भंडार मिलेगा। Our Chief Minister, hon. Vasundhara Raje has demanded that the neighbouring States like Punjab and Haryana should release due share of water to Rajasthan. Along with it, the State has also requested the Centre to put pressure on Punjab to release more water for Rajasthan from the Pong Dam. A demand has been made to the Union Minister for Water Resources, Uma Bharti ji to urge Haryana not to usurp Rajasthan's share of water from Yamuna. An undertaking had already been taken by the Bhakra – Beas Management Board, BBMB, that Rajasthan would compensate Punjab and Haryana for the loss of their share of water.

सभापति महोदय, मेरी मांग है कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सिद्धमुख कैनाल, अमर सिंह बैराज का पूरा पानी दिया जाए। हरियाणा में राजस्थान के हिस्से के पानी की चोरी होती है, उसे रोकने की पुख्ता व्यवस्था की जाए तथा जिस क्षेत्र को सिंचित घोषित किया गया है, वहां पक्के नाले व खालों का निर्माण किया जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार को विशेष अनुदान दी जाए ताकि किसान खुशहाल हो और चारे तथा पानी के संकट का समाधान हो सके। जहाँ पर मीठा पानी है, वहां कृषि कुएं बने हुए हैं। कृषि कनेक्शन अविलम्ब किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों की फसल बीमा के बारे में कहना चाहूँगा। बीमा कंपनियों के द्वारा टर्म-शीट में तापमान के पैरामीटर को माइनस एक डिग्री

सेंटीग्रेड से संशोधन करते हुए सीधे गेहूं में माइनस 3, चना में माइनस 2.7, सरसों में माइनस 2.7 कर दिया गया। यह बहुत कठोर शर्त है, यह मापदण्ड अवैधानिक है। मौसम आधारित संयंत्रों के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। फसल बीमा के लिए प्रीमियम में की गयी बढ़ोत्तरी वापस ली जानी चाहिए।

ऑडॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : यूं तो मानसून जून महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू होता है और फिर पूरे देश में वह आगे बढ़ता है। मगर पिछले कुछ सालों से मानसून के आगमन में अनियमित्तता देखी जाती है । इस वर्ष को देखें तो पूरे देश में मानसून आने के समय में देरी हुई है । मेरा स्पष्ट मानना हे कि इस देरी के लिए क्लाइमेट चेंज जवाबदार है ।

अगर पूरे देश के संदर्भ में देखें तो इस वर्ष मानसून अब तक कमजोर रहा है । देश के कई प्रदेशों में मानसून कमजोर रहा है और किसान मानसून की प्रतीक्षा में कई राज्यों में अब तक फसल नहीं बो सका है ।

जहां तक मानसून का सवाल है, शुरू से ही मानसून कमजोर रहा है । मगर पिछले कुछ दिनों से पूरे गुजरात में अच्छी बारिश हो रही है । सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात के सभी प्रदेशों, फिर चाहे वह उत्तर गुजरात हो, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य गुजरात या फिर दक्षिण गुजरात हो, सभी जगह बारिश अच्छी हुई है। इसकी वजह से पूरे गुजरात में प्रसन्नता हुई है और किसान खुश हो गए हैं ।

मगर, पिछले कुछ दिनों से गुजरात में भारी मात्रा में बारिश हुई है और कई जगहों से अतिवृष्टि हुई है और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है ।

मैं अहमदाबाद से लोक सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पिछले कुछ दिनों में भारी वर्षा हुई है। सन् 2000 के बाद, पिछले पन्द्र सालों में इस साल भारी मात्रा में बारिश हुई है । 24 घंटों में अहमदाबाद शहर में करीबन 20 इंच बारिश होने की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था और पूर की स्थिति उत्पन्न हुई थी । लो-लेवल की जगहों पर लोगों के घरों में तथा सड़कों पर 5 से 6 फीट पानी भर गया था । इसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है ।

अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कार्यवाही की वजह से भारी नुकसान होते हुए भी लोगों को सही वक्त पर फायदा मिला है ।

मेरी विनती है कि केन्द्र सरकार अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों तथा प्रदेशा में बाढ़ की स्थिति आई है, वहां राज्य सरकार की सिफारिश के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए ।

---

* Speech was laid on the Table

बाढ़ के बाद गंदगी के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाए ।

जहां तक सूखे का सवाल है सूखाग्रस्त प्रदेशों में खासकर किसानों को राहत प्रदान की जानी चाहिए और किसानों को ऋण में काफी देनी चाहिए ।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का मौका दिया।

महोदय, आज आधा हिन्दुस्तान फ्लड की वजह से रो रहा है और आधा हिन्दुस्तान सूखे से झुलस रहा है। कहीं लोग पानी के लिए रो रहे हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों में दुआएं कर रहे हैं और कहीं फ्लड से बचने के लिए दुआएं कर रहे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान के आजाद हुए लगभग 67 साल हो गए, लेकिन हम इस प्राब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हर साल यह मसला पार्लियामेंट में उठता है, बहुत ही सीरियसली उठता है। मैं यह समझता हूं कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए आई हुई है, किसानों के लिए बड़े वादे किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर पूरा ध्यान देंगे। अभी महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों में लोग सूखे से ग्रस्त हैं। लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, किसान भी आत्महत्या करने को मजबूर है। इसी तरह से आप असम को लीजिए, बिहार को लीजिए, वेस्ट बंगाल को लीजिए, उड़ीसा को लीजिए। इन सभी राज्यों में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। छह-छह महीने इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है, जो लोग वहां के रहने वाले नहीं हैं, वे इस बात को महसूस नहीं कर सकते हैं। कीड़े-मकौड़े, जंगली जानवर भी शायद इनसे अच्छी हालत में रहते हैं, इनसे भी बुरी हालत उन लोगों की है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इनके लिए कोई प्रभावी क़दम उठाएगी कि जरूरत के समय हकीकत में इन लोगों की मुश्किलों को सोल्व किया जा सके।

महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है और मुझे यह कहना भी नहीं चाहिए कि हम जब बड़े-बड़े मंत्रियों की अपने राज्यों में बातें सुनते हैं, उनके सचिवों की बातें सुनते हैं, ऑफिसरों की बातें सुनते हैं कि मंत्रियों के यहां दुआएं मांगी जाती हैं कि हमारे यहां इस साल बाढ़ क्यों नहीं आ रही है, हमने अपने साला-साली और रिश्तेदारों के प्रोग्राम यूरोप और अमेरिका का बनाया था। अगर फ्लड नहीं आएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे तो ये अमेरिका घूमने के लिए कैसे जाएंगे? यहां गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, उनके झोपड़ों में रहने की

जगह नहीं है, वे जानवरों से बुरी हालत में रह रहे हैं और मंत्री प्लान बनाते हैं कि हर साल बाढ़ आएगी और इतने पैसे हम उसमें से निकालेंगे तथा अमेरिका और लंदन घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, हनीमून मनाने जाएंगे। यह बहुत अफसोस की बात है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जो भी पैसा भेजती है, वह पैसा सही लोगों तक पहुंचे, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। सरकार इसका कोई न कोई इंतजाम करे, यह हमारी पार्टी की डिमांड है।

महोदय, मैं असम से आता हूं। अभी कल पूना में भूस्खलन हुआ है। कितने दुर्भाग्य की बात है। उत्तराखंड में भूस्खलन वर्ष 2013 में हुआ था। इतने लोग मारे गए। दस दिन पहले टेलीविजन में उत्तराखंड की त्रासदी के बारे में दिखाया जा रहा था कि आज तक सही मायने में लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। लोग बुरे हालत में वहां रह रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से हमारे असम में बराक वैली से सिल्चर, करीमगंज वगैरह से जो लोग गुहाटी आते हैं, वहां बहुत बड़ा मेघालय का पहाड़ पड़ता है और हर साल उसमें दसों-बीसों लैंड स्लाइड के वाकिये होते हैं। चूंकि हम असम के गरीब इलाके के लोग हैं, हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है। सैंटर से जो भी फंड जाता है, वह बीच में ही खत्म हो जाता है तथा लोगों को कुछ राहत नहीं मिलती है, न इस दिशा में कोई कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से फ्लड इरोज़न के साथ, ड्रॉट के साथ मैंने हमेशा यहां यह बात उठाई है कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारे लिए एक देव बन चुका है। इसे कंट्रोल करने के लिए नेशनल कैलेमिटी कैसी डिक्लेयर किया जाए। मैं मंत्री जी से एक आवेदन करूंगा कि वे हमारी इस बात को सुनें, इस बात को नोट करें कि जब तक ब्रहमपुत्र नदी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक असम के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक लाख 27 हजार हेक्टेयर जमीन अब तक बह चुकी है और तीस लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। नेपाल से, भूटान से जो पानी आता है, भूटान से जो पानी आता है, यह पानी बारपेटा के पूरे इलाके को बहाकर ले जाता है। लोगों की लाखों बीघे जमीन बर्बाद हो जाती है। लोग रास्तों पर आकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देखें लखीपुर में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से हर साल पानी आता है, जिसके कारण हमारे यहां लाखों लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। असम के मामले में फौरन ध्यान देकर वहां बाढ़ से आई विभीषिका को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। धीमाजी, मजुली और बारपेड़ा, बोरझार के इलाके हैं, इन सबको बचाने की कोशिश की जाए। आपकी स्पेशल इंटेंशन इस तरफ हो, यह जरूरी है। मेरे पास डेटा तो बहुत है, लेकिन उसे यहां बताने का समय नहीं है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह अपने दोस्तों से बातें जरूर कर लें, लेकिन हम गरीबों की बातों को भी नोट करें। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): My views on drought and flood situation in the country are as follows:-

1. Punjab State suffers 58% rain deficiency but crops in Punjab have been protected for farmers by using excess electricity which costs 1500 crore. Secondly, burnt diesel for tubewells costs excess in more than Rs. 700 crore Wear and tare Tare expenses costs Rs. 300 crore. The Punjab Government has demanded Rs.2350 crore. This amount should be paid.
2. Desiliting in rivers becomes the reason for flood. Desilting comes under Mining Department. So it should be taken under Water Resource Ministry.
3. Check Dams and lake and deep Talab should be built
4. Compensation amount should be increased to Rs.3500 per acre from Rs.2000 per acre.
5. Water resources should be taken in infrastructure sector so that adequate funds can be allocated taken from the budget.
6. Irrigation scheme should be funded for hilly areas.
7. Per drop more crop scheme should be implemented first.
8. At least Rs.20,000 crores should be reserved for Pradhan Mantri Gram Sinchayi Yojna. Funds Rs.1000 crore funds are very small.

---

* Speech was laid on the Table

***SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR) :** The Sunderbans is the largest mangrove forest ecosystem in the world and consists of an intricate network of tidal waterways, marshy patches, mudflats and numerous islands. It is famous for its rich biological diversity, the prime attraction being the expansive mangrove forests; the ecosystem is one of a kind the world over.

Annually 2.4 billion tons of sediments is transported by the major rivers of Bangladesh. This situation is having a profound effect on the floodplains and the coastal region. Silt deposition in the north eastern part of the forest poses a threat to the existence and vigorous growth of mangrove vegetation. Progressive silt deposition has caused a rise in the forest floor and due to irregular flow of tidal water, mangroves are not properly regenerated. Further due to years of dumping plastic waste, water flow is severely obstructed leading to merging of forest land with human habitation regions, consequently endangering human life in the neighbouring villages.

Further, salinity levels have increased in the Sunderbans since he Mathabhanga, Kobadak and other rivers bringing fresh water from the Ganges to the south were silted up excessively thus losing their connection with the Ganges. As a result, the regeneration of Sundari, the dominant timber species in the forest has been reduced in the southwestern part of the Sundarbans.

Mangrove holds the soil firmly and prevents soil erosion. Mangroves are also the protection of the Gangetic plains of West Bengal including Kolkata from the cyclonic storms coming from the sea, hence they should be preserved.

The Sunderbans is on the verge of disintegrating and disappearing. In light of how things have progressed in the Sunderbans as depicted in a nutshell above, I would like to humbly submit before this House that the call of the hour is to immediately take actions to ameliorate this dire situation before we lose an element of national pride in its entirely.

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): Thank you, Hon. Chairman, Sir. I come from a flood-prone area, that is, Assam. Flood is a curse for Assam. After Independence, many floods have visited Assam resulting in loss of many lives, and erosion of large chunks of lands. We have abundant water but due to climate change and deforestation, we have drought. This is very unfortunate for Assam because we have mighty river, Brahmaputra, which supplies potable water to the people of Assam, gives water for irrigation in Assam. Civilization is growing in both the banks from time immemorial but we could not manage the water of Brahmaputra. If we can manage the water of Brahmaputra, we can alone produce 29,000 mw of power, which can serve the entire country.

Time and again, we have raised this issue here, in Parliament, and outside. People started movements but nothing happened. So, I urge upon the new Government, through you, under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Agriculture Minister and the Water Resources Minister, who are present here, to take this into cognizance and take steps to restrain the floods from Brahmaputra and its tributaries.

We have the Brahmaputra Board. Parliament passed the Bill in 1981 and the Brahmaputra Board was formed. But it is a white elephant. They have not done anything to protect the Majuli and other parts as far as erosion is concerned. Erosion is the major problem for us. That is why, I always demand that erosion should be declared as a national calamity because we lost lands in various floods. In my constituency, Udalguri also, we have seen erosion in our rivers. All of us know that Majuli is the largest river island of Asia but we lost many kilometers due to erosion in Majuli. So, I demand and urge the Government to protect Majuli from erosion.

Further, I demand that water in Assam should be managed properly so that people of Assam and the rest of the country can get the fruits of water. After many years of Independence, people are saying that next war will be fought on water. Water would be a major issue because we are exploiting water from ground, and not using our river waters, not using water from the springs and other sources and tributaries. We fail to manage water even after 65 years of Independence. Due to siltation, the capacity of Brahmaputra and its tributaries has come down now. So, floods have become a recurrence which people say that it is a festival, a festival of curse. And the bunds are unscientific, which was constructed after Independence. Life of those bunds have ended. It should be reconstructed scientifically. So, I urge upon the Water Resources Minister to survey all bunds of Assam so that bunds can be reconstructed. Works of MGNREGA can also be distributed there.

Last time also I raised this point that through NREGS we can repair these bunds after the rainy season. So, I would like to urge upon the Government that flood and erosion problems of Assam should be taken seriously and the Government should evolve a long-term policy so that the people of Assam are not affected by flood again and again.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this very important debate.

Sir, our country is really living in a fear complex either due to flood or drought. Our country is prone to flood because ours is a peninsular country surrounded by the Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. The top 10 flood prone States in India are West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Kerala, Assam, Gujarat, Haryana, Punjab and Bihar. We all know that the hardship caused to the people due to flood is unexplainable. Loss of life and property, irreparable damage to infrastructure, hellish experience faced by the people and havoc caused by flood, we all know that very well. We were discussing about this in the morning also. Last year, we had a hellish experience in Uttarakhand and we all still remember that.

Sir, 60 per cent of our agricultural production comes from rain-fed area and 17 per cent of our GDP comes from our agriculture sector. Considering all this, we have to think about certain things loudly. The first is in respect of hydro power generation. For power generation, hydro power projects are more useful. At the same time, we have to think twice before sanctioning new hydro power projects. We have to go for alternative power generation projects and we must think loudly about this kind of projects.

As far as rivers are concerned, my learned friends were saying that our rivers are getting dry these days. Some rivers are even disappearing from the geographical map of India. Actually, I would like to say that criminal offenders are really killing the rivers. So we have to think as to how we can preserve all our rivers. It is quite unfortunate that the rivers have become dumping places of unwanted and useless materials. Sand mafias are controlling all the rivers now. We have to take maximum possible efforts to preserve our rivers which are gifts of the God.

Coming to drought, we very much apprehend drought this year in our country. As far as Kerala is concerned, 14 districts are declared as drought affected districts. Several proposals for water supply schemes are pending before the Government of India as well as before the State Level Clearance Committee. I suggest that we must take expeditious steps to clear these proposals. The Government of India should seriously consider allocating adequate funds for this kind of projects.

River management fund is also very negligible. The Government of India should seriously think about this also. Sustainability of water resources is another big issue today. We have to discuss that also in a meticulous way. There are many pumping stations in the rivers of our country. But almost all of them are not working properly. There are two reasons for this. One is power shortage and the other is lack of proper

maintenance of pumping stations. So, we have to make serious efforts to repair them. We have to think loudly about construction of check dams in rivers so that river water can be preserved to some extent.

Sir, another important thing is rainwater harvesting. We can do a lot of things in that. Due to time constraint, I would not like to go into the details. Rain water is really a natural resource that we can preserve through rain water harvesting. It reduces flooding. Similarly, contamination of surface water with pesticides is also reduced by water harvesting. It is an excellent source of water for irrigation because there are no chemicals such as fluoride, chlorine in that. So, it is clean. That also is a benefit of water harvesting. We have to think about these kinds of things.

Then, I would like to say that the laws pertaining to protection of rivers, lakes, ponds etc. are to be made more stringent.

Kerala has submitted a memorandum for additional fund allocation in respect of meeting the crisis.

We have to think of using reverse osmosis process because, as we all know, that is a technical method for purifying the saline water. It is really very expensive but it is very useful for semiconductors, food processing, biotechnology, pharmaceuticals, power generation and sea water desilting. That also can be very seriously considered.

Calamities are made by whom? They are made by men. Man-made calamities are very much there in our country because we are cruel to nature. That is resulting in calamities. So we have to make awareness programmes for this.

We are all talking about disaster management. In our curriculum, we must include disaster management.

We are all talking about sustainable development. We must ensure the cooperation of every stakeholder for ensuring sustainable development in our country.

With these few words, I conclude.

*SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM) : I express my views on the very serious subject matter of "the flood and drought situation in the country" in this august House. Floods can be controlled, whenever flood comes, it can be regulated, controlled and sent to the place where there is no proper rainfall. It is more important to see that the flood is controlled properly and wherever flood arises, wherever necessity of water is not there, it has to be regulated and sent to the places where they are in need of water. The only potential solution is to tap the excess water and natural springs, is to get all our rivers internally linked.

Shri Narendra Modiji's vision, commitment and concerted effort for Linking of Rivers and also to bring entire India under irrigation is a praiseworthy. The Government has emphasized the need for giving high priority to water security and completion of pending irrigation projects. Shri Narendra Modiji, might have foreseen the serious drought situation in coming days. Therefore, he is motivating himself and motivating others with the motto of 'Har Khet ko paani". It is possible, when you concentrate on rivers that are flowing from the very area but without irrigating surrounding farm lands. For example, the River Godavari is passing though Telangana State but at the time of need we are not getting a drop of water, as it is flowing and accumulating at the ending point and even overflowing into the sea. The geographical features and characteristics are not facilitating to harness the water from Godavari river, though there is a possibility to tap it. Whenever there is a rain and cyclonic condition, the river wash out our farm lands, huts and villages. To harness the maximum water, we need to construct small dams wherever possible apart from diverting rivers into needy areas.

This is due to Elnino effect, monsoon has become very scanty and so far only 24% below rainfall recorded which is worse than the deficiency seen in 2009-2012.

Today, the farmers are in a state of total frustration, and they are waiting for some relief from the Government. The farmers need a uniform crop insurance policy. Some crops are insured at premium level, and some other crops are insured at some other premium-level and Government is implementing these Agriculture Insurance Schemes in some selected states and districts only, which in turn causes regional imbalance. What to do with the farmers belonging to the other areas, where the crop insurance schemes are not applicable. Hence, we have to give protection to the farmers by giving a uniform farmers insurance and security package.

The "Southern Water Grid", which the Government has proposed with 16 river linkages in different states, including Godavari and Krishna in Telangana state for ensuring optimal use of our water resources and to prevent the recurrence of floods and drought situations, should be completed in a time bound manner. This effort will facilitate to divert the surplus water from Godavari basin to Krishna basin, thereby the burden on Krishna river basin will be reduced. The surplus water in Godavari basin which will be flowing into the sea can be taped for irrigation purposes.

I would, therefore, request the government to expedite the process of Inter Linking of Rivers in Telangana so as to enable to store the maximum surplus water from Godavari basin for irrigation needs.

As far as the State of Telangana is concerned, especially my constituency i.e. Khamma is dry land and hilly areas, where drought like situation is very common. During rainy season, we have surplus water and during summer water scarcity kills many people every year.

Lack of drinking water is a very important problem in Telangana and also in other parts of our country. Lack of drinking water has become a major problem not only in the villages of Telangana, but also in urban areas and towns. So, we do not have water either for irrigation or drinking purpose. The problem needs to be addressed forthwith by giving it top priority.

I would request the Government to allocate sufficient funds to Telangana state from AIBFM programme to develop minor irrigation tanks to recharge ground water in the drought prone area of Telangana and also to control floods.

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आजादी के बाद से किसान के ऊपर ही चोट पड़ती है चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ खींचना चाहती हूं। मैं दिल्ली से लेकर आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, इलाहाबाद और बुंदेलखंड के सातों जनपद की बात कहना चाहती हूं। कल आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि 30 परसेंट बारिश हुई है। यह सरकारी आंकड़ा था। मैं वहां रहती हूं और इसलिए कहना चाहती हूं कि वहां आज भी खेतों में हल नहीं चल रहे हैं क्योंकि बरसात नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेरित करें कि किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली दी जाए ताकि धान या अन्य फसलें सुरक्षित रह सकें। हमें किसानों की पीड़ा और वेदना को समझना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि वह खेती पर ही निर्भर करता है। वह पूरा साल प्रतीक्षा करता है कि मेरी खेत में कुछ पैदा होगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, बेटे की शादी करूंगा। अगर कभी बाढ़ नहीं आती, सूखा नहीं पड़ता है तो ओला पड़ जाता है। इस तरह उसके मन में मनसूबे अधूरे रह जाते हैं। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जिनकी फसलें बाढ़, सूखे या ओले की चपेट में आ जाती हैं और वे ज़हर खाकर मृत्यु के घाट उतर जाते हैं।

मैं उस क्षेत्र से आती हूं जिस जनपद ने सदन के लिए माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी दिए। मैं बुंदेलखंड से विधायक थी और मुझे लगा कि फतेहपुर बहुत अच्छा होगा। यहां बुंदेलखंड और फतेहपुर की चर्चा हुई है। मैं बुंदेलखंड, फतेहपुर और कानपुर देहात की पीड़ा व्यक्त करना चाहती हूं। यह दो नदियों यमुना और गंगा के मध्य में बसा हुआ इलाका है और बुंदेलखंड केन-बेतवा और जमुना के मध्य में बसा हुआ इलाका है। पिछले वर्ष 2013 में दो महीने लगातार नदी भरी रही, दसियों हजार आदमी उस बाढ़ से प्रभावित रहे। ऐसा लगा कि इस आपदा में सरकार कुछ देगी। जब बाढ़ या सूखा आता है तो किसान की पीड़ा और उसकी वेदना वहीं रह जाती है। लेकिन उसके माध्यम से अधिकारियों का कमाने का मौका मिल जाता है, चाहे सूखा हो, चाहे ओले पड़े, चाहे बाढ़ आये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आप किसानों को सूखे का मुआवजा देना चाहते हैं या बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देना चाहते हैं तो यदि आप वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को माध्यम बनाकर मुआवजा देंगे तो वह किसानों तक पहुंचेगा, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ दोनों में किसान पीड़ित होता है - 'जा के पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीड़ पराई।' इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि बुंदेलखंड पर उधर की बैठी हुई सरकार ने भी चिंता प्रकट की है, किसान पार्टी का नहीं होता है, किसान, किसान होता है, किसान की वेदना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद से अनेकों बार किसानों के प्रति पीड़ा व्यक्त की गई, आजादी आई थी, लेकिन कायम हैं गुलामी की रस्में, आज किसान उसी गुलामी की मार झेल रहा है। मेरी मातृभूमि के लिए आज बाढ़ पर चिंता प्रकट की जा रही है, सूखे पर चिंता प्रकट की जा रही है। मेरी शस्य श्यामला धरा के पहाड़ तोड़ दिये गये, पेड़ काट लिये गये, नदियों का अंधाधुंध दोहन हुआ, इसके कारण प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है और बाढ़ की विभीषिका को किसानों को झेलना पड़ रहा है। "जहां शस्य श्यामला धरा न हो, नवहिंद धूम से भरा न हो, जहां प्रकृति सुन्दरी के अधरों पर, मदमाती मुस्कान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं"। मेरे हिंदुस्तान की पहचान नदियों से है, मेरे हिंदुस्तान की पहचान पहाड़ों से है, मेरे हिंदुस्तान की पहचान किसानों से है। किसानों की पीड़ा पूरे सदन की पीड़ा है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 193 के तहत चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और पूरे सदन ने इस बात पर चिंता जताई है कि चाहे बिहार हो या पूरा देश हो, आज जो सुखाड़ और बाढ़ की प्रक्रिया है, आजादी के 67 बीतने के बाद भी उसका कोई निदान नहीं हो सका। चाहे किसी की सरकार हो, मैं किसी के ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम बिहार से आते हैं, हमारे उत्तरी बिहार में एक तरफ यदि बाढ़ है तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ है। हमारे माननीय सांसद, श्री राजेश रंजन जी तथा अन्य कई लोगों ने इस बारे में चर्चा की है कि उत्तरी बिहार में इस तरीके की बाढ़ आती है कि उसकी वेदना सदन में व्यक्त नहीं की जाती है, जाने कितने ही जानवर मर जाते हैं, कितने ही आदमी मर जाते हैं, वहां के लोग रात भर पानी में ही चलते रहते हैं, आखिर उस तरीके की वेदना कब तक रहेगी। माननीय मंत्री जी बिहार के हैं, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार नहीं, बल्कि पूरे देश के जितने भी संसदीय क्षेत्रों के सांसद हैं, उन्हें बुलाकर आप बैठक कीजिए और एक योजनाबद्ध तैयारी कीजिए कि हर जिले में इसका कैसे समाधान हो, कैसे हम हर खेत को पानी दें, इसका समाधान जरूर होना चाहिए। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव में वायदा किया था कि मैं हर खेत को पानी दूंगा, हर हाथ को काम दूंगा। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सभी माननीय सांसदों को यह मौका दें कि हमारे कृषि प्रधान देश में हम कैसे खेतों को पानी दें।

महोदय, हर प्रदेश की बनावट अलग है, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है। एक जिले में भी दो-दो, तीन-तीन तरह की बनावट है। जिले में भी कहीं दो प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं और दो प्रखंड सुखाड़ से प्रभावित हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, नालंदा मेरा संसदीय क्षेत्र है। उत्तरी बिहार बाढ़ के इलाके में है तो हम लोग दक्षिणी बिहार में आते हैं। अभी अरूण बाबू अपनी वेदना सुना रहे थे। जहां पर बरसाती नदी है, जो झारखण्ड से आती है, फलगू नदी मुख्य रूप से वहां है और उसी का पानी लोगों को मिलता है। जब झारखण्ड में बारिश होती है, तब दक्षिणी बिहार के लोगों को पानी मिलता है और उसी से पटवन होता है।

महोदय, इस साल तो यह हालत है कि आप औरंगाबाद चले जाएं, नालंदा, नवादा और जम्मू तक वह हालत है कि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग संसदीय क्षेत्र में थे, लोग नीचे टयूबवेल से पानी खींच कर लाते हैं और किसान मेहनत से धान की रोपाई कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपसे विनती और निवेदन करूंगा कि उनकी वेदना को आप देख कि किसान किस तरीके से किस मुसीबत में अपना पेट पालने काम कर रहा है। माननीय मंत्री जी बिहार से हैं। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी देता हूँ कि ऐसा मौका आया है कि आप मंत्री बने हैं। आप बिहार के सांसद थे, कई बार आपने गरीबी को झेला है, आपने सुखाड़ को देखा है, आपने बाढ़ को देखा है। मैं समझता हूँ हर संसदीय क्षेत्र में इसकी व्यवस्था करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, एक कहावत है कि - का बरसानी, जब कृषि सुखानी। जब कृषि सूख जाए तो वर्षा होने का कोई महत्व नहीं होता है। इस वर्ष भी स्थिति करीब-करीब वही हुई है। आगे के दिनों के इंतजार में हैं कि शायद वर्षा हो। लेकिन उस वर्षा से बाढ़ तो आ सकती है, लेकिन कृषि को फायदा नहीं हो सकता है।

जब सुखाड़ की बात करते हैं तो लगातार बात आ रही है कि किसानों को नुकसान हो रहा है, खेतीहर मज़दूरों को नुकसान हो रहा है। स्थिति यह हो गई है कि मानसून कम आएगा, इसकी चर्चा हुई तो देश में महंगाई एकाएक आ गई। जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी भी चिंतित हुए। जब सुखाड़ आती है या बाढ़ आती

है तो देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने लगती है। विकास दर भी प्रभावित होने लगती है। इसलिए सब लोगों की चिंता है। अब यह दूसरी बात है कि हम इसके लिए चिंतित हो रहे हैं, लेकिन इस तर्क को भी रख रहे हैं कि जब से यह सदन बना है, तब से मानसून सत्र में इसकी चर्चा होती है, लेकिन कोई निदान नहीं निकल पाता है। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि चर्चा में कुछ निदान निकलेगा। जब अटल जी देश के प्रधान मंत्री थे, उनके सपने थे कि हम नदियों को जोड़ेंगे। वह अच्छी योजना थी। आज सारे सदस्य, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जहां सुखाड़ है, जहां पानी का प्रबंधन नहीं है, जहां बाढ़ है, ऐसी नदियों को हम जोड़ने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि यहां परिणाम तो निकलना शुरू हो जाता है। जिस समय अटल जी ने इस सपने को देखा और उसको साकार रूप देने की कोशिश की, उनकी सरकार जाने के बाद दस वर्षों का समय इस राष्ट्र के लिए बर्बाद हुआ और जिससे सारी चीज़ें प्रभावित हुईं। यहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, एक-एक गरीब प्रभावित होता है। उस मुद्दे को लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अब गंभीरता से पूरा सदन, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पहली बार चिंता करनी शुरू की है।

मैं झारखण्ड से आता हूँ। वहां पर पूरा राज्य सुखाड़ से पीड़ित है। पिछले वर्ष भी, उसके पूर्व भी और हर वर्ष एक-एक इतिहास लिखा, जब वहां पर सुखाड़ आया। पूरे हिंदुस्तान में अगर सुखाड़ ने सबसे ज्यादा कहीं प्रभाव डाला तो वह पलामू का क्षेत्र रहा है। वहां पर लाख की संख्या में या तो जानवर मर गए या हजारों की संख्या में आदमी भूख से तड़पते हुए मर गए। लेकिन आज तक वहां कोई प्रबंधन नहीं है। महोदय, वहां दो प्रमुख परियोजनाएं हैं। हमारे बिहार के साथी इसे जानते होंगे। माननीय मंत्री जी भी गंडक परियोजना के क्षेत्र से आते हैं। टकसाल मशीन, जिस तरह से नोट छापने वाली मशीन होती है, उस तरह से पुराने बिहार में उत्तर में गंडक परियोजना चली और दक्षिण में स्वर्ण रेखा परियोजना चली। लगभग तीस हजार करोड़ रूपए अभी तक खर्च हो गया होगा, लेकिन दोनों के काम पूरे नहीं हुए हैं। कभी उसके तटबंध टूट जाते हैं, कभी जमीन टूट जाती है, कभी लूट हो जाती है। वहां बाढ़ आती है, बाढ़ से वहां तटबंध टूट जाना एक आम बात हो गयी है। मैं दो मिनट में अपने राज्य की बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, हमारे यहां कृत्रिम बाढ़ भी आती है। डीवीसी का तिलैया डैम है, डीवीसी का पन्चेत डैम है, हमारी कांस्टीच्युएंसी में डीवीसी का मैथन डैम है, उधर चांडिल डैम स्वर्ण रेखा का है, बरसात होने के बाद अचानक लोग पानी छोड़ देते हैं। कृत्रिम बाढ़ की वजह से मैं समझता हूं कि साल में कम से कम सभी डैम्स से छोड़े गए पानी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसको कोई देखने वाला नहीं है।

महोदय, पन्चेत डीवीसी का डैम हमारे यहां है, लेकिन उससे सिंचाई का प्रबंधन नहीं है। हमारे लोगों की जमीन पर वह डैम है, वहां के हजारों लोग विस्थापित हुए, लेकिन एक धूर जमीन सिंचाई का प्रबंधन नहीं है। इसलिए विनम्रतापूर्वक सरकार से मैं मांग करूंगा कि जितने प्रकार के डैम है, डैम के पानी का वहां पर उचित उपयोग हो, पीने के पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, वहां के जानवर को तीन-चार किलोमीटर जाकर पानी पिलाना पड़ता है। यह पूरे राज्य की तस्वीर है। इस राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए सरकार निश्चित रूप से ठोस कदम उठाए। यही निवेदन करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

***SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD) :** My state West Bengal is always affected by either flood or drought. In the middle Bengal, some of our districts are too much affected by drought this year. Monsoon is going on but still now we are in a shortfall of rain. In these districts, specially my constituency Murshidabad district is suffering badly due to shortage of rainfall. Jute and Paddy are the main crops in these areas. Jute is the only money earning crop in Murshidabad. This year due to shortfall of rain Jute plouging is seriously affected. Now, it is the time to help the cultivation, otherwise some of them will be compelled to commit suicide.

So, I like to bring into the notice of concerned Deptt. of Government of India to take some positive steps in consultation with the State Government so that drought affected farmers of Bengal, particularly of my District Murshidabad, get some benefit to sustain their livelihood.

DR. P. VENUGOPA.L (TIRUVALLUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the discussion on the natural calamities like drought and floods that we face in India perennially.

Natural disaster is a major adverse event resulting from natural processes of the earth. A natural disaster causes loss of life and property. Besides, there is a huge economic impact on the country also.

Sir, when we talk about natural calamities in India, we face droughts, flash floods, cyclones every year and there are huge loss of life and property.

Indian economy depends on agriculture. Whenever there is failure of monsoon, there is drought and whenever there is more of monsoon rains, we have floods. Both cause tremendous damage.

If we talk about natural disasters, in 2012 alone, there were 905 natural catastrophes in the world and about 95 per cent of them were weather-related disasters.

A few of natural disasters that struck India in the recent history were Uttarakhand floods in 2013; tsunami in 2004; earthquake in Bhuj, Gujarat in 2001; super cyclone in Odisha in 1999; and earthquake in Latur, Maharashtra in 1993. Wednesday morning, at least, 20 people were killed in Malin village, which is just 100 kilometres away from Pune city, due to landslide.

Some disasters are man-made. For industrial and other developments and also for construction/formation of roads, we cut trees and forest but we do not replant them. Last week, there was a report saying that there is a slight increase in the forest cover. But the sad part is that there is also a report which says that the water table in India has been constantly decreasing. We do not replenish the natural resource. Our air-conditioners and fridges emit CFC and HCFC, which are ozone-depleting Green House Gases.They cause holes in the ozone layer. With the result, temperature of the world rises. Rise in temperature causes the glaciers to melt. When it is unchecked, it may cause rise in the sea level.

If we are mindful of these day-to-day practices, much of the disasters can be avoided. When we cut trees and forests for our development, we have to plant more trees if we want to stop disasters.

We are not bothered even to stop polluting the rivers. Effluents from the factories are let into our rivers, causing great damage to the environment. We let out carbon monoxide, sulphur and other obnoxious gases from our factories and vehicles. This causes air pollution, making a dent on the ozone protective layer. These damages are irreparable and we need to take care of the Mother Earth.

In August 2005, Hurricane Katrina caused widespread damage to the US. It is the costliest natural disaster and one of the deadliest hurricanes to have struck the US. At least 1800 people died and the economic damage was estimated to be about 100 billion US dollars.

When this happened, for more than a week the dead bodies could not be removed; there was no milk; there was no water; and there were no food supplies to the affected parts of the US. Such was the damage in a developed nation like the US. Though we cannot compare disasters, when Tsunami struck the Indian coasts, the Tamil Nadu Government, under the able leadership of Chief Minister, Madam Maanbimiku Amma Puratchi Thalaivi Jayalalithaa, took immediate action and brought the situation under control within no time.

Now, let me come to the specific issue of droughts and floods in India. It is a perennial problem that we have drought in one part of the country and at the same time, there is severe flood in another part. People suffer because of both. We are not able to channelize the excess water due to flood in one part and take it to the other part where there is severe drought.

Mr. Chairman, Sir, there are solutions to this problem. Before I come to interlinking of rivers, I would like to say a word about rainwater harvesting. The Government of Tamil Nadu, under the leadership of hon. Chief Minister, Dr. Jayalalithaa, has adopted a system of rainwater harvesting which is a huge success throughout the State. Due to rainwater harvesting, it is seen that the groundwater table increased and the saline water entering the ground in coastal areas is stopped. Here, I would like to remind the House that the hon. Prime Minister of India appreciated the efforts of the Government of Tamil Nadu when he was replying to the Motion of Thanks to the President's Address.

Over the years what we have seen is that whenever there is rain and flood, the entire water inundates the villages on the way and enters the seas. If the course of the river is streamlined and interlinked, this huge quantity of rainwater could be put to future use. On the other hand, when there is drought, we do not get water even for drinking purposes, leave alone for agriculture and irrigation purposes. We are always at the mercy of other States which have surplus water.

First of all, the Government of India has to take a very bold decision and nationalize all the rivers of the country. Presently, the subject of water is in the State List whereas the subject of National Waterways is in the Union List. It is high time that we ponder over this and bring it to the Central List or at least to the Concurrent List so that effectively something could be done for the benefit of the nation.

It is not that only Tamil Nadu is facing such a crisis of water but many States are also facing this problem; rather the entire world is facing this problem. There are articles which quote the experts who have estimated that by 2025, more than half of the world's population will be facing water-based vulnerability. Another report says that by 2030 in some developing countries, water demand will exceed the supply by 50 per cent. These are all alarming situations and therefore, we need to conserve and preserve water for the future generations.

HON. CHAIRPERSON : Please wind up.

DR. P. VENUGOPA.L: So, interlinking of rivers is absolutely necessary to tackle the constant drought and flood problem that I touched upon earlier. While I accept that there will be some problems in doing this, they could be resolved by mutual consultations. When the NDA Government was in power earlier, it constituted a Task Force which submitted a detailed report on this subject. It could be re-visited to see whether its recommendations could be implemented now.

I understand that the concerned States have to accept the proposal for interlinking. As of now, we see that there is an objection from the Odisha Government because there would be some submergence problem. This could be sorted out. Similarly, Kerala has some problem which could also be resolved.

The forward-looking Prime Minister could convene a meeting of all the Chief Ministers of States under the aegis of NIC or NDC to thrash out issues and take a final decision so that permanently we put an end to the water crisis, and we could be a model for the world. Otherwise, what we see is a dispute in sharing of water. The upper riparian States have the old habit of releasing water when they are threatened with flood. But, the lower riparian States under normal circumstances do not get water and face huge crisis. To solve this water sharing dispute, we could also think of having a water grid similar to power grid that we have. Like power, water also can be transferred from one part to the other part of the country and even reverse flow could also be made. Like States draw power when there is a need, water can also be drawn by needy States, which could be monitored at the grid.

With these words, I conclude.

HON. CHAIRPERSON : I want to make a request to hon. Members. I have noticed a problem. Most of the Members are new. When a Member is speaking, some new Members come in front him and come between the Chair and the speaker. That creates a lot of problem.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Some senior Members also do it.

HON. CHAIRPERSON: That is why, I request that when a Member is speaking, do not try to go towards him or cross between him and the Chair. Sometimes Members sit in front of him also. It disturbs him in his speech. It is not a correct thing. Therefore, I request all of you to follow the rules.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, आपने मुझे बाढ़ और सुखाड़ पर इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं बिहार के उस इलाके से चुन कर आता हूं जो इलाका प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित होता है। बिहार में दोनों तरह की समस्याएं हैं। आज देश के बहुत बड़े हिस्से में

सूखे की स्थिति है। हमारे राज्य में एक तरफ बाढ़ की स्थिति होती है और दूसरी तरफ सूखाड़ की स्थिति होती है। जिस इलाके से मैं चुन कर आता हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद है, जो मगध का एक भाग है। यहां करीब-करीब हर वर्ष सूखा पड़ता है। यह दूसरा वर्ष है जब लगातार सूखे की सम्भावना बन गई है। पिछले वर्ष तो सूखा था ही, इस वर्ष की स्थिति यह है कि यदि एक सप्ताह और वर्षा नहीं हुई, तो यहां पूरा का पूरा सूखा पड़ जाएगा। थोड़ा-सा हिस्सा ऐसा है, जहां नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा है, जहां अभी धान के बीचड़े लग रहे हैं लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वहां धान का दस प्रतिशत बीचड़ा भी नहीं लगा है। ऐसी संभावना है कि वहां अब सूखा पड़ जाएगा। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार को बताना चाहता हूं कि जब हम सूखे के विषय में चर्चा करते हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, जब सूखा पड़ता है तो उसका तात्कालिक कोई उपाय या राहत किसान को मिले और दूसरा, स्थायी रूप से उसके निदान के लिए क़दम उठाने की आवश्यकता है। जब इस तरह की समस्या आए, कम आए या न आए लेकिन यहां बात हमेशा तात्कालिक होती है, जो स्थायी निदान है, उसके विषय में सदन में जरूर चर्चा होती है लेकिन कोई कारगर क़दम नहीं उठाया जाता है। मैं एक स्पष्ट उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। आज से चालीस साल पहले यानी वर्ष 1975 में उस सिंचाई योजना पर कार्य आरंभ हुआ। उसकी प्रारंभिक लागत मात्र 80 करोड़ रुपए की थी। अभी तक एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इस सिंचाई परियोजना पर खर्च हो चुके हैं और प्रति वर्ष 14-15 करोड़ रुपए स्थापना व्यय पर खर्च हो रहा है, कर्मियों आदि की तनख्वाह पर खर्च हो रहा है। लेकिन उसका प्रतिफल शून्य है। उसका रिजल्ट ज़ीरो है। चालीस साल बीत चुके हैं, एक हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया है, लेकिन किसान को उसका फायदा शून्य है। कारण यह है कि वर्ष 2007 में यूपीए-1 की सरकार ने वन पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से उसके कुटकू डैम में लोहे के फाटक लगाने पर, स्लूइस गेट लगाने पर मनाही कर दी।उसका कारण यह बताया गया कि इस से राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होगा, जल जमाव से जंगल सूखेंगे।...(व्यवधान) महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। कृपा कर मुझे अपनी बात को पूरी करने दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि चालीस साल बीत गए, एक हजार करोड़ रुपये खर्च हो गए और एक अनुमति के अभाव में दो राज्यों झारखण्ड और बिहार के तीन जिलों - पलामू, औरंगाबाद और गया में सवा लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है। वह सिंचाई से वंचित है। जब हम इसके स्थायी हल की दिशा में बढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा वरना हमें हर साल इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) जहां तक तात्कालिक लाभ की बात है तो वह ऋण माफी है, मालगुज़ारी माफी है। अगले साल के लिए खाद या बीज के लिए ऋण की सुविधा सरकार दे, यह मेरा अनुरोध है। इसके साथ-साथ कृषि मज़दूरों को भी काम मिले।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए यह कहा है कि कम से कम सिंचाई और कम से कम खाद का उपयोग हो और अधिक से अधिक उपज हो।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Now, Shri N.K. Premachandran will speak. We have to wind up at 6 o'clock.

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, यह उनकी एक सोच है, उनका एक स्वप्न है। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: The time is over. We have to adjourn at 6 o'clock.

Okay, you finish your speech.

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, हमारे बिहार राज्य की जो सरकार है, उसकी क्या सोच है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी सोच यह है कि अभी तक औसत से दो प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। इसलिए बिहार में अकाल की स्थिति नहीं है। पता नहीं किस दुनिया में बिहार की सरकार जी रही है, यह हम नहीं जानते। हम लोगों ने गांव में एक कहावत सुना है कि किसी एक ज्ञानी आदमी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया, इस नदी में कितना पानी है? इसे कैसे पार करेंगे? उसने औसत निकाल कर बता दिया कि इतना पानी है और वह बेचारा नदी पार करने लगा और डूब गया। वही स्थिति बिहार सरकार की है।...(व्यवधान)

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख का दक्षिणी भाग हर साल बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आता है। इसके दक्षिणी भाग से गंगा नदी का प्रवाह है। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में गर्रा नदी सढियापुर गांव के पास गंगा नदी में मिलती है। गर्रा नदी के गंगा में मिलने के कारण पानी का आवेग अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण गंगा नदी के बायें तट पर 5-6 कि.मी. की सीमा में आने वाले 100 से अधिक गांव हर साल बाढ़ की तबाही का मंजर देखते हैं। इन गांवों की खरीफ की फसलें पूरी तरह तबाह एवं बर्बाद हो जाती है और लाखों लोग बाढ़ की इस विभीषिका में बेघर-बार हो जाते हैं। इनकी जमीनें कट जाती है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास कोई उद्योग धंधा नहीं है। ये पूरी तरह कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर हैं। हर साल बाढ़ की इस समस्या के कारण इनके घर-मकान भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग बेहद गरीब और कुपोषण के शिकार हैं। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में आता है। इसका एक बड़ा कारण बाढ़ द्वारा लायी गयी यह तबाही भी है।

इस तबाही को रोका जा सकता है। लाखों लोगों को अमानवीय जीवन जीने के हालातों से बाहर लाया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में जहां पर गर्रा नदी गंगा नदी में मिलती है। वहां से गहरिपुरवां उन्नाव जनपद की सीमा तक लगभग 25 कि.मी. की लंबाई में गंगा तट पर यदि पक्का बांध बना दिया जाये तो हर साल आने वाली बाढ़ की इस विभीषिका से बचा जा सकता है और लाखों लोगों को बेहतर जिन्दगी दी जा सकती है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में अवश्य पहल करे तथा सर्वांगीण विकास वाले एक उन्नत और बेहतर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए गंगा तट पर पक्के बांध की योजना लेकर सामने आये। आज यहां पर हम बाढ़ की जिस विभीषिका की चर्चा कर रहे हैं उसका समाधान यही है कि इस दिशा में एक ठोस पहल की जाये और इसका स्थायी समाधान तलाशा जाये। बाढ़ पीड़ितों को कुछ मुआवजा राशि दे देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। बाढ़ हमारे जीवन में एक समस्या नहीं है बल्कि यह एक आपदा है। जब कोई क्षेत्र आपदाग्रस्त हो जाता है तो वहां का जनजीवन कैसा होता है इसका आकलना करना संभव नहीं होता। कितनी जन-धन की हानि होती है यह पता नहीं लग पाता। आज की इक्कीसवीं सदी का भारत यदि आपदाग्रस्त रहता है तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको आपदा मुक्त भारत का निर्माण करने का प्रयास करना होगा।

ॐश्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) : मेरा संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में घाघरा नदी के दाएं किनारे पर बाढ़ नियंत्रण हेतु चहलारी घाट से एल्गिन पुल के अपस्ट्रीम में स्थित

गणेशपुर बांध तक लगभग 54.6 किमी. लंबे नए बांध का निमाण किया जाना था। क्षेत्रवासियों के द्वारा बांध निर्माण में की जा रही घोर अनियमितताओं की लगातार शिकायत की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मेरे स्थल का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अनेकों क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में मैंने पाया कि बांध निर्माण में अनेकों गंभीर अनियमितताएं की गई। बांध का कम्पेक्शन व ग्राउंड लेबल तथा लंबाई और चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है। निर्माण कार्य में सामग्री का मानक के अनुसार प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधिक वर्षा व नदी में अधिक जल बहाव होने पर बांध कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे शासकीय धनराशि का अधिक दुरूपयोग होगा ही बांध क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को अपार जन-धन की हानि भी हो सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि बांध निर्माण में हो रही अनियमितता में सम्मिलित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच दल से जांच कराई जाए और बांध को यथोचित मानक के अनुरूप पूर्ण करायें ताकि बार-बार बांध टुटने और बाढ़ से होने वाली जन व धन हानि को रोका जा सके।

---

* Speech was laid on the Table

* **DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR) :** India is going through an environment turmoil. Some places there is drought and at the same time somewhere there is flood studded area. First of all we must analyze the causes of changing scenario in land and river belts of India, part of it is nature made and part of it is man made. So far as natural condition is concerned there is excessive rain fall and melting of ice in Himalayan areas. The pathetic example is of Himachal Pradesh. We observed in recent past the reason of man made flood is construction of dams in different locations or states over the same river. The restriction of natural flow leads to silt deposition, reducing the river bed both in depth and width. This leads to overflow of rivers in rainy season and causes flood in adjacent areas. When the water level in dam reservoirs reaches danger level, release of water leads to man made flood in vast areas.

The causes of drought is also nature made and man made. Due to global warming and environment change often there is less rain fall and drought. On the other hand, due to urbanization, there is reduction of cultivable land as well as deforestation due to cutting of trees. It leads to less rainfall and drought. Moreover for irrigation purpose inadvertent use of deep tubewells leads to water level going down. These factors are responsible for drought and changing the land scenario of India.

While dealing with construction of dams there should be consensus of opinion and joint scientific approach among different states and nations for removal of silts from various flood prone rivers. There should be a calculated balance approach for inter-linking of rivers. It is good idea but while planning inter-linking of rivers, the flow direction and eco-balance should be taken seriously.

While planning land procurement for urbanization and industrialization, deforestation and cutting of trees should be minimum. Plantation of new trees around the sides of roads should be considered seriously.

* **SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR) :** The entire country is reeling under severe drought. The State of Karnataka has very frequently experienced drought. June month of this year recorded the lowest rainfall in the past 52 years. The improper rain has affected agriculture activity, drinking water and power generation.

In Karnataka most areas are repeatedly facing drought. "The rain-fed crops cultivated in Mysore, Mandya, Chamarajnagar, Hassan, Tumkur, Chitradurga, Davangere, Ramanagarm, Dharwad, Bellary, Gadag and Yadgir are withering due to inadequate rains."

Government of India should come forward to rescue the State of Karnataka from severe drought by providing more financial assistance.

Government should also create awareness programmes among farmers to grow crops which require less water and yield more.

Therefore, I urge upon Government of India to come forward to take up planting of saplings in all parts of the country of rejuvenate more thick forests to enable to get more rains and to check drought situations permanently. And, I also would urge the Union Government to release adequate funds to take up drought relief measures like water conservation, storage of rain water, recharging of underground water, etc. I would also like to suggest to take adequate steps to store excess water during flood situation by creating provision through more minor and small tanks.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is a strange occasion to see in this House that we are discussing two issues, that is, drought and flood together. Maybe, it is for the first time in this House that we are discussing both these subjects together. These are diametrically opposite subjects, but they are related.

HON. CHAIRPERSON : You have only two minutes. You have to speak very briefly. I have to adjourn the House at 6 o'clock.

...(*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, it is very difficult to complete in two minutes. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What to do about it?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : When we discuss these issues of drought and floods simultaneously, it is such an alarming situation which is being faced in our country that this year we are having the apprehension of having a big shortfall in rainfall. For the time being, the statistics would go to show that it is 43 per cent less than that of the previous year. That is the total cumulative rainfall.

Coming to the capacity of reservoirs, the Central Water Commission is monitoring 85 reservoirs in our country and the total reservoir capacity is 155.05 billion cubic metres of water at full reservoir level. Current live storage is only 36.49 billion cubic metres as against 55.44 billion cubic metres in the corresponding period of the last year. The average for one decade was 40.55 billion cubic metres. That means a severe drought is going to come in. That is an alarming situation which our country faces. I do appreciate and congratulate the hon. Agriculture Minister, Shri Radha Mohan Singh, for at least having a programme or an action plan for 500 districts for mitigating or addressing this situation.

Regarding agriculture crops also, another very serious situation which our country is facing now is that our agricultural, cultivable or sowing area of *kharif* crops across the country is down by 43 per cent.

18.00 hrs.

Further, shortfall in acreage is being reported from various parts of the country. Major crops like rice, pulses, coarse, cereals, oil seeds and cotton are going to ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please wait for a minute. Now, it is 6 o'clock, and all the new Members have to go for an Orientation Programme. If the House accepts, then we can extend the time of the House for 10 more minutes as one more speaker wants to speak on this issue. So, if the House accepts, we can extend the time of the House for a maximum of 10 more minutes.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Okay, give five-five minutes each to both of them.

HON. CHAIRPERSON: No, you please try to wind up in 2-3 minutes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Thank you very much, Sir.

The severity of the forthcoming situation is to be taken into consideration, and some concrete precautionary measures are to be taken to address the situation. This is my submission.

How to address the drought situation? This is the pertinent point that is to be taken into consideration. The long-term measures, which I would like to suggest -- and for which a detailed discussion is required -- is that all this is because of climate change, that is, drought, shortage of rainfall and flood is due to climate change. Why is there climate change? It is because of uncontrolled utilization or exploitation of natural resources without considering the environment and ecology on the grounds of development where development means GDP growth and economic growth and on that basis uncontrolled utilization or exploitation is there. If you are not able to address that issue, then we have to spend crores of rupees during the time of drought and flood also.

Within two weeks from the inception of this Government in power, they have already given Rs. 5.5 million worth project of environmental / forest clearance and Rs. 4.5 million crore worth of project is also pending. If this be the situation and if you are taking environment / ecology in such a manner, then definitely we would have to spend a lot of money on drought / flood situation at the time of flood and drought also.

Sir, I am having certain suggestions. ...(*Interruptions*) I am having five minutes at my disposal to speak.

HON. CHAIRPERSON: No, it is not five minutes as one more Member has to speak on this issue.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am only going to give some suggestions.

As far as the National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authority is concerned, what is the compensation being given? The compensation is totally inadequate. I would like to give an example. As far as banana plant is concerned, what is the amount being paid as compensation? It is just Rs. 3.50 for a banana plant if it is lost due to flood or drought. Further, if one hectare of paddy cultivation is lost, then one will be given just Rs. 2,500. In our State, we are paying Rs. 10,000 per hectare of paddy cultivation. So, the compensation has to be adequately increased.

As regards flood also, I would like to give a new suggestion that has not come in the House. The initiator of the discussion has just made a mention of it, namely, desilting of dams. I would urge upon the Government of India to formulate a policy in respect of desiltation of dams in our country, so that capacity of water reservoirs can be increased, sand will be available, and rivers can be protected. These suggestions may be taken into consideration.

With these words, I thank you very much, Sir, and I conclude my speech.

*SHRI B. N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): India is generally affected by two major hydro-meteorological disasters, namely, drought and flood. Drought is perennial feature in the country. As per one estimate, about 16 percent of India's total area is drought prone and approximately 50 million people are affected annually by drought. This largely hits the sown area of the country. About 70 percent of total sown area in India is vulnerable to drought. As per the report of the National Disaster Management authority, 2012, about 15.2 percent of total geographical area is flood prone and on an average 10 to 12 million hectare is actually affected every year causing a range of miseries.

My State Karnataka is one State where there is simultaneous occurrence of flood and drought. In one part of Karnataka there is flood and in another part, that is, in my constituency Chitragurga, there is drought. Added to the drought condition in my constituency, there is a shortage of drinking water. People have to go to far off areas to get a pot full of water. According to the WHO estimate, every 20 seconds, one infant dies for want of drinking water. Secondly, the water that is available is full of fluoride in it.

What is really needed is the realistic assessment of agricultural condition during drought and flood in the country. This would help in providing relief and rehabilitation measures. The relief and rehabilitation measures should be based on the needs of each state.

I would also urge the Government one more thing. Since both these disasters impact a large area, hence satellite based monitoring is extremely useful. The satellite based imagery would help in locating the actual problem in each area separately. I would urge the Central government to formulate an area specific approach for the State of Karnataka in consultation with the State Government for tackling the problem of drought and flood. This approach would set a healthy trend in tackling the problem in a better way. This would also help the farmers who are the bread-earners for the people of our country.

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर)ः अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भाँति बाढ़ भी अनादिकाल से मानवजाति को भयभीत करती रही है तथा जान-माल की अपार क्षति पहुँचाती रही है। परंतु विडंबना यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति के बावजूद आज भी मनुष्य बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है। लेकिन यह संतोष की बात है कि अधिकांश विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रदान करने के लिए नए-नए तरीके खोज लिए गए हैं और समय पर सावधानियाँ बरतकर इनसे होने वाली क्षति के परिणाम को कम किया जा सकता है। इस दिशा में समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य परस्पर सहयोग एवं समन्वय विशेष रूप से वांछनीय एवं महत्वपूर्ण है।

सृष्टि के निर्माण से ही पानी का बहुत योगदान है। जहां-जहां पर पानी है या नदियां बहती है वहां पर ही बड़े-बड़े शहर विकसित हुए हैं। पानी एवं भूमि का सम्बंध एक अनुपात में होना चाहिए। अगर यह संबंध सही रहे और पानी का अनुपात ठीक रहे तो भूमि अपनी उर्वरता से देश के विकास में बहुत ज्यादा योगदान देती है। परंतु भारत में कई जगह पानी जरूरत से ज्यादा है और कहीं पर पानी जरूरत से कम है। इससे एक ओर बाढ़ का वातावरण पैदा होता है तो दूसरी ओर सुखाड़ जैसा वातावरण रहता है। इससे दोनों ही परिस्थितियों में लोगों को जान-माल की क्षति होती रहती है। देश के कुछ हिस्सों में हर साल बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप रहता है और इन प्रकोपों से हर साल कई जाने चली जाती है। किसानों की खरबों की फसले बर्बाद हो जाती है और मवेशी भी हज़ारों की संख्या में मारे जाते हैं। इन प्रकोपों से सबसे ज्यादा किसान वर्ग प्रभावित होता है और यही वर्ग बर्बाद होता है। आज़ादी के 67 साल के बाद भी इन प्रकोपों का प्रभाव कम होने की बजाय बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मेरे गृह राज्य बिहार का संस्कृति एवं सभ्यता के मामले में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। परंतु बिहार बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों से पीड़ित है। बिहार की मिट्टी में गुणात्मक उर्वरता के बावजूद दोनों प्रकोपों के कारण आज भी बिहार अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा है। बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है और भूमि की उर्वरता भी ज्यादा है, परंतु सुखाड़ एवं बाढ़ के कारण ही विकास नहीं कर पा रहा है। बाढ़ और सुखाड़ ने बिहार के विकास को बांध कर रख दिया है। इसी कारण बाढ़ को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ की विनाशकारी प्रकृति का मुख्य कारण है बाढ़ की विशाल जनराशि में छिपी अथाह शक्ति। बाढ़ का प्रभाव तत्काल दिखाई देता है। अति तीव्रता से बहने वाली जलराशि अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को तहस-नहस कर देती है। कोई मानव शक्ति उसे रोकने में समर्थ नहीं हो पाती। प्रत्यक्ष रूप में बाढ़ के कारण फसल, भवन, सड़क, संचार साधन, यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को बहुत ही क्षति पहुंचती है, जिसे पुनः बहाल करने में काफी समय लग जाता है। बाढ़ जल की तीव्रता के कारण टेलीफोन तार के खंभे उखड़कर गिर जाते है और सम्पर्क व्यवस्था ठप्प हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से संपर्क टूट जाने के कारण राहत एवं सहायता कार्यों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा पीड़ित लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है। बाढ़ की चपेट में आने वाले मवेशी एवं मनुष्य, काल के विकराल गाल में समा जाते हैं। बाढ़ का पानी तेजी से प्रत्येक स्थान में प्रवेश कर जाता है। छोटे-बड़े नालों व नालीयों की हानिकारक गंदगी भी पेयजल में समा जाती है। जिससे पेयजल दूषित होता है, जिसे पीने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। बिहार में तटबंध टूट जाते है और नदियों के किनारे बसे लोग उजड़ने लगते हैं। नेपाल का पानी बरसात के दिनों में भीषण गर्जना के साथ बिहार में घुसता है और बिहार में तबाही मचा देता है। तीव्र वेग से बढ़ता बाढ़ का पानी नहर एवं नालों को निगलता हुआ सर्वप्रथम आस-पास के खुले क्षेत्रों तथा खेत-खलिहानों में फैल जाता है। खेतों में खड़ी

फसलें बाढ़ के जल में डूबकर नष्ट हो जाती हैं। फसल बोए जाने के समय बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी, उपयोगी खाद और बीज बह जाते हैं। विस्तृत चारागाह भी जलमग्न हो जाते हैं जिसके कारण पशुओं के लिए चारे की कमी पैदा हो जाती है। नेपाल भी कभी-कभी दो लाख क्यूसेक पानी छोड़ता है, जो उत्तरी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ का एक कारण बनता है। और जब पानी बिहार में आता है तो नदियों का बहाव इतना तेज जोता है कि जंगली जानवर तक बह जाते हैं। बाढ़ के समय कई लोग पेड़ों में अपना स्थल बना लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि एक डाल पर कई आदमी है और दूसरी डाल पर जहरीले साँप होते हैं और यह साँप पानी से बचने के लिए पहले पेड़ पर चढ़ जाते हैं और नदी पर चलने वाली नाँवे जो राहत कार्य में लगी रहती है, उसमें गिर जाते हैं और नाव में बैठे हुए लोगों को डस लेते हैं और इस तरह से भी मृत्यु हो जाती है। बाढ़ एवं सुखाड़ के समय राहत कार्यों में जो धनराशि राहत के नाम से आती है उसमें सरकारी अधिकारियों का अलग से अर्थशास्त्र होता है, उसमें कितनी कमाई की जाये यह ज्यादा चर्चा का विषय होता है। जबकि काम होना चाहिए राहत उपलब्ध कराने का। बिहार की जनता बाढ़ से इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कहना शुरू कर दिया है कि उनको भोजन, कपड़ा एवं पैसा नहीं चाहिए बल्कि इसका स्थाई समाधान करना चाहिए क्योंकि इस बाढ़ से बच्चों की पढ़ाई पर तीन माह से चार माह तक असर रहता है।

औद्योगिक क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाली क्षति आर्थिक दृष्टि से काफी गंभीर स्थिति धारण कर लेती है। उत्पादकता एवं व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। जिसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। रेल व सड़क मार्ग अवरूद्ध होने के कारण आवश्यक वस्तुओं का आवागमन रूक जाता है। अतः दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुओं की कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है तथा समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक संकट का शिकार हो जाता है। कुछ स्वार्थी एवं असामाजिक लोग इस प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई संकटकारी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।

बाढ़ से केवल फसल खराब नहीं होती बल्कि लोगों का जीवन तीन-चार माह के लिए नारकीय बन जाता है। जगह-जगह पानी भर जाता है और जल भराव की समस्या बन जाती है, जिसके कारण कई बीमारियाँ फैल जाती है और इन बीमारियों से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ऐसे मरने वालों के रिकॉर्ड नहीं होते बल्कि जबकि यह मरते बाढ़ के कारण ही हैं।

कई दशक पूर्व नेपाल एवं भारत में एक संधि हुई थी, जिसमें प्रावधान था कि नेपाल में जब आठ से दस दिन तक बारिश लगातार होगी तो उसकी सूचना भारत सरकार को दी जाएगी। परंतु वर्तमान समय में नेपाल में लगातार बारिश होने के बाद भी इसकी सूचना भारत सरकार को नहीं दी जाती है जिसके कारण यह पानी नेपाल से होते हुए भारत में तबाही मचाता है। कई दशक पूर्व तराई क्षेत्र में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण यह पानी बड़ी तेजी के साथ भारत में प्रवेश करता है। जब पेड़ थे तब यह पानी के वेग को रोकते थे और इन पेड़ों से पानी की गति भी धीमी होती थी जिसके कारण भारत सरकार सचेत हो जाती थी और राहत कार्य की व्यवस्था समय पर कर ली जाती थी। परंतु घटते पेड़ों के कारण बाढ़ की समस्या अब बढ़ गई है। नेपाल से जो पानी आता है अगर उसका सही उपयोग किया जाये तो हम अपने देश का विकास अच्छे ढंग से कर सकते है। कई दशकों से नेपाल से बातचीत हो रही है परंतु आज तक इसका कोई सकारात्मक उपाय नहीं निकला है। नेपाल से आने वाला पानी और उत्तरी बिहार में फालतू बह रहे पानी से हम पन बिजली के माध्यम से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और इस ढंग से बिजली पैदा करके इस देश में बिजली पैदा करके इस देश में बिजली की कमी को दूर कर सकते हैं और तबाही के पानी को खुशहाल पानी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आज जहां-जहां पर पानी ज्यादा है, नदियाँ हैं, वहाँ पर हाइड्रो तकनीक से बिजली पैदा करने के कई प्लांट सरकार लगा रही है। ऐसी पहल बिहार में भी होना चाहिए। इन प्रयासों से भारत के साथ नेपाल का भी विकास हो सकता है, परंतु कुछ पड़ोसी देश पर्दे के पीछे से नेपाल को गरीब देश ही रखना चाहते हैं क्योंकि नेपाल के विकसित होने से उनको काफी खतरा हो सकता है, उनके लिए सिरदर्द बन सकता है। भारत सरकार भूटान की सरकार के साथ बिजली पैदा करने के प्रयास कर रही है और सरकार उत्तरी एवं पूर्वी भारत के राज्यों में पानी से बिजली बनाने, जिसे पन बिजली या हाइड्रो पद्धति कहते हैं, के माध्यम से बिजली पैदा कर सकते हैं और दूसरी ओर इस फालतू पानी को नियंत्रित करके उसको डैम के माध्यम से संचय कर सकते हैं और किसानों को जरूरत पड़ने पर उनके खेतों को सिंचित किया जा सकता है। इससे सुखाड़ प्रभावित इलाकों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जा सकता है। इससे सुखाड़ क्षेत्र के किसानों की फसल सूखकर खराब नहीं हो पाएगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को देश के जल संकट से उबरने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने का ऐतिहासिक निर्देश दिया गया था। सरकार ने अपने शपथ-पत्र में वर्ष 2035 तक प्रायद्विपीय नदियों और वर्ष 2043 तक हिमालयी नदियों को जोड़ने का वायदा किया था। नदियों को आपस में जोड़ने व जल ग्रिड बनाने का प्रस्ताव लगभग तीन दशकों से देश की फिज़ाओं में तैर रहा है। कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की वाजपेयी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी।

भारत में नदियों के प्रवाह के आधार पर दो प्रमुख जल धाराएं है, जिन्हें आपस में जोड़ने की चर्चा चल रही है। ये जल धाराएं उत्तर भारतीय हिमालयी जल धाराएं तथा दक्षिण भारतीय प्रायद्विपीय जल धाराएं हैं। हिमालय जल धारा की प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज एवं इनकी तमाम सहायक नदियां हैं। जबकि दक्षिण भारतीय प्रायद्विपीय जल धारा की प्रमुख नदियां नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, वैतरणी, सुवर्णरेखा एवं इनकी सहायक नदियां हैं। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण हेतु कई योजनाएं चलाई है और इसके लिए डैम बनाने एवं जल आधारित विद्युत योजना के प्रयास किये है। परंतु इसके बावजूद लोग बाढ़ एवं सुखाड़ से परेशान है। विश्व में बाढ़ एवं सुखाड़ को रोकने के लिए नई-नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है इसमें एक इंसेट उपग्रहों के माध्यम से बाढ़ एवं सुखाड़ का अनुमान लगाये जा रहे हैं। भारत में इस तरह से 223 केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और 222 केन्द्र स्थापित होने वाले हैं। इन केन्द्रों से हम केवल बाढ़ एवं सुखाड़ के क्षेत्र का पता लगा पायंगे, परंतु बाढ़ में राहत पहुँचाने के लिए जो गतिविधियाँ हैं उनमें नाहक देरी होती है। बिहार में बाढ़ से परेशान है और दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक होने के बाद जो निर्णय लिये जाते है उस पर कार्यवाही होते-होते एक महीना बीत जाता है यानी एक महीने बाद राहत पहुँचती है। राहत जब जरूरत हो उस वक्त ही उपलब्ध करानी चाहिए, न कि एक महीने बाद।

सरकार बाढ़ की बार-बार आने वाली समस्या का सामना करने के लिए कार्यदल का गठन भी करती है। इस कार्यदल को शीघ्रता के साथ काम करना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए एक साथ छोटे-छोटे कई बाँधों में जल का भंडारण किया जा सकता है। जब एक बाँध भर जाये तो दूसरे बाँध में पानी भरे, तब तीसरे, चौथे, पाँचवें में इससे न सिर्फ नदी के जल का आयतन घटेगा बल्कि बाढ़ भी रूक जायेंगी। इन जल भंडारणों के जल को सिंचाई, मत्स्य पालन, उद्योग, मनोरंजन, बिजली आदि के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नेपाल सरकार के साथ बातचीत ही नहीं अपितु सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए जिससे शीघ्र हल निकल सके। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत केवल राहत में राशि करने का प्रावधान है। बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई भी इस निधि से की जाये। इस तरह से बाढ़ से किसानों को तथा गरीब लोगों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाये। साथ ही साथ, मेरा सरकार से अनुरोध है कि बांध के निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी का मैटेरियल का प्रयोग किया जाये और डैम भी क्वालिटी वाले होने चाहिए। अगर इन बांध एवं डैम् में कोई खराबी आये या कोई कटाव आये तो अधिशासी अभियंता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

यह भी देखा जाता है कि जहाँ पर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। वहाँ पर पक्के मकान बने, पक्की सड़के बनें और पुलों का निर्माण किये जाने चाहिए। जिन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है, वहाँ पर 8 किलोमीटर के तटबंध बनने चाहिए।

सुखाड़ भी एक भयावह समस्या है और कई राज्यों में सुखाड़ का प्रकोप रहता है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिसा हैं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और झारखंड भी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष कमज़ोर मानसून के कारण एक चौथाई खेती चौपट हो गयी है और अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। पिछले वर्ष ज़ुलाई 2013 तक 517 हैक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल की बुआई हो चुकी थी। जबकि, इस वर्ष अभी तक सिर्फ 256 लाख हैक्टेयर भूमि में ही खरीफ की फसल की बुआई हुई है।

जोकि चिंता का विषय है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र देश के बड़े हिस्से की तरह सूखे के विकट संकट से जूझ रहा है। राज्य के बांधों-जलाशयों का स्तर इतना नीचे हो गया है कि खेती-किसानी, उद्योग, बिजलीघर के लिए तो मुश्किल वक्त तो है ही, पीने के पानी के भी लाले पड़ गये हैं। सुखाड़ के लिए सरकार ने कई स्कीमें चला रखी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध हे कि बिहार में जहाँ पर 68 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़ प्रवण क्षेत्र में है और बाढ़ से हर साल प्रभावित रहता है। इनके लिए एक पैकेज दिया जाये जिससे बाढ़ से प्रभावित बिहार का उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र बाढ़ से निज़ात पा सके।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पड़ोसी देशों के साथ ठोस एवं सकारात्मक नीति बनाकर देश के जल संरक्षण के लिए लंबी दीर्घकालिक योजनाओं का आरंभ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का संकल्प लिया जाये जिससे बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखे जैसी विभीषिका से देश के लोगों को बचाया जा सके।

*__SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR):__ The objectives of the scheme were to restore and augment storage capacities of water bodies and also to recover and extend their lost irrigation potential. These projects cover 556 water bodies with total original cultivable command area of 5000 acres.

After RRR works, an additional irrigation potential of 5000 acres is likely to be generated. If the physical work for restoration is completed in 556 water bodies in district of Thanjavur, Tamil Nadu. The irrigation potential created subsequent to pilot scheme will be 500 acres approximately.

The main objective of the project is : Comprehensive improvement of selected tank systems including restoration; Improvement of catchement areas of tank; Community participation and self-supporting system for sustainable management for water bodies covered by the programme; Ground Recharge; Capacity Building of communities, user groups standing committee for Panchayats and State Government/Central Government Agencies concerned with planning, implementation and monitoring of the project and; Increase in storage capacity of water bodies;

Environmental benefits through improved water use efficiency; irrigation benefits through restoration of water bodies, supplementation of the groundwater use and promotion of conjunctive use of surface and groundwater; Development of tourism, cultural activities etc.; and Increased availability of drinking water.

Keeping in view of above, I humbly urge upon the hon'ble Minister to kindly take necessary steps to enable this project in Thanjavur, Tamilnadu at the earliest.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन केवल कुछ बिन्दु हैं, जो महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी इस सूखे और बाढ़ की बहस का उत्तर का उत्तर दें तो निश्चित तौर से जो मेरे द्वारा प्रश्न उठाये जा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे दें।

मेरे बहुत से साथियों ने यहां अपने विचार रखे हैं। अभी कल भी हमारे बहुत से नये साथी, भरत सिंह जी हैं, शरद जी हैं और भी तमाम साथी अपने विचार रखेंगे तो मैं उस पर समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि some steps are being taken by the Government of India और जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि : "Crop contingency plans have been developed for 500 out of about 540 agricultural districts by the Central Research Institute of Dryland Agriculture (CRIDA) in collaboration with the State Agriculture Universities and concerned State Governments to deal with the challenges posed by aberrant monsoon. Secondly, the States have been advised to consult the National Crisis Management Plan on Drought, 2014 while managing any probable drought / rainfall deficit situation."

The measures to be taken का मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं यह उल्लेख कर रहा हूं कि जिन दो स्टैप्स को भारत सरकार ने टेक अप किया है तो माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि सैण्ट्रल रिसर्च इंस्टीटयूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ने 500 जिलों के लिए जो कार्ययोजना बनाई है, उसके सम्बन्ध में राज्य क्या कर रहे हैं। हर राज्य का मैं पढ़ रहा था तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने एक सूखा कार्ययोजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया है। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमें अपने जिले में नहीं मालूम है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का जो पत्र जिलाधिकारी को गया है, वह वास्तविकता के धरातल पर कब उतरेगा? अगर भारत सरकार कोई निर्देश दे रही है, कह रहे हैं कि इस चर्चा की क्या सार्थकता है? चर्चा की सार्थकता है, मैं तो भारत सरकार के बधाई दूंगा। आखिर पंचवर्षीय में आपने केवल इस नेचुरल कैलेमिटी में बारह हजार करोड़ रूपए राज्यों को दिया है। आप हिसाब लें या न लें, हमें याद है कि पन्द्रहवीं लोक सभा में बिहार में बाढ़ आयी थी, एक हजार करोड़ रूपए यहीं से बिहार की कोसी की बाढ़ के लिए दिया गया था। गीते जी और हम सब लोग मौजूद हैं। आज जो सूखे की स्थिति है, केवल यह नहीं कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे गोडाउंस भरे हुए हैं, अब अन्न की वह स्थिति नहीं होगी, हमें पीएल 480 मंगाना पड़े, दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़े। आज जो वर्ल्ड

में हम सबसे ज्यादा सुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल, कुकिंग ऑयल, राइस, कॉटन, यह हम केवल सबसे ज्यादा दुनिया में नहीं पैदा कर रहे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब हमारा मानसून कम हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। जो हम जीडीपी में 14 परसेंट एग्रीकल्चर के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वह कहां हो पाएगा, यह चिंता का विषय है।

आप जानते हैं कि जून की जो इंडियन मेटोलिजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 43 परसेंट जून में सामान्य से कम वर्षा हुयी। जो चार्ट है, आप उसे देख लीजिए, सिचुएशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया ड्यू टू ड्राट, मतलब ऑल क्रॉप्स को मैं अलग-अलग नहीं पढ़ना चाहता हूं। टोटल जो नॉर्मल एरिया ऑफ होल सीजन है, जो क्रॉप होनी चाहिए, जो सोइंग होनी चाहिए, वह 1054.67 लाख हेक्टेअर टोटल होना चाहिए। आपके पास इसकी जानकारी होगी। 18 जुलाई तक कितनी सोइंग हुई है, अभी तक पूरे देश में कितनी बुआई हुई है? 570.56 लाख हेक्टेअर अभी तक बुआई हुई है। पिछले साल वर्ष 2013 में 627.44 लाख हेक्टेअर इसी 18 जुलाई तक हुई थी। आखिर इसका मतलब है कि ये तो आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम वर्षा हुई है। सामान्य से वर्षा कम होने के कारण बुआई कम हो रही है। जो हम लोगों का इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, एक बाढ़ नीयत थी, जब वहां सूखा पड़ गया, सिद्धार्थनगर में सूखा है, कुशीनगर में सूखा है, श्रावस्ती में सूखा है, बहराइच में, गोंडा में, संतकबीर नगर में सूखा है तो आप कल्पना कर सकते हैं। जहां आप कोसी से प्रभावित होते थे, हम बाणगंगा से प्रभावित होते थे, करनाली से, जलकुंडी से प्रभावित होते थे तो उस बाढ़ की स्थिति में हम क्या कहें? स्वाभाविक है कि जब इस सूखे के कारण हम इस साल वर्ष 2014 में हमने अभी तक केवल 345.60 लाख हेक्टेअर की बुआई की है तो मतलब पिछले साल का आधा किया और नॉर्मल होना चाहिए 1054 लाख हेक्टेअर।

महोदय, मैं केवल एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इसलिए यह बात बहुत गम्भीर है। जो आप कह रहे हैं, बाढ़ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण हर साल 432 करोड़ की फसल प्रभावित होती है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 12.5 परसेंट भूभाग पर हर साल बाढ़ आती है। आप देखिये अभी कहा जा रहा था कि बिहार बाढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है। 7.336 मिलियन हेक्टेअर बाढ़ से प्रभावित होता है, जब बाढ़ आती है, बिहार 4.26 है, पंजाब 3.6 है, राजस्थान 3.26 है, असम 3.15 है। मैं समझता हूं कि आज हमारे यहां जो शारदा है, राप्ती है, गंडक है, वहां बाढ़ की स्थिति है। हम उसी इलाके से आते हैं, इसलिए मेरा दर्द है। मैंने आपसे इसीलिए अनुरोध किया क्योंकि आखिर हम चुनकर आते हैं, हमारा उत्तरदायित्व है, बाढ़ में एक फसल खरीफ की हमें कभी मिलती ही नहीं थी, वह फसल इसलिए नहीं मिलती थी कि बाढ़ में जिस तरीके से नेपाल की नदियों का पानी आता है, थोड़ी भी नेपाल में बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है। मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि 23 वर्षों के बाद पहली बार भारत की विदेश मंत्री सुषमा जी नेपाल गयीं और संयुक्त आयोग की बैठक हुई और एक नया रिश्ता फिर से शुरू हो रहा है। हमारा अपने पड़ोसी राष्ट्रों से कोई रिश्ता ही नहीं था। कहा जा रहा है कि बिहार वहां पैसा देता है, हमारा वहां जल विभाग का एक कार्यालय है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद यह जो पानी बाढ़ की शक्ल में आता है, शायद हम वहां से कोई पावर स्टेशन भी बनाने में नेपाल को सहयोग करें या हम सड़कों के लिए हुलाकी जो कोस्टल एरिया है ईस्ट से वेस्ट नेपाल के पैरलल, वहां हम इसे करें। निश्चित तौर से इस बार प्रधानमंत्री का दौरा भारत और नेपाल के रिश्ते में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में बाढ़ को रोकेगा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो कार्य योजना आपने बनायी है, वह कार्य योजना राज्य में कितनी अमल हो रही है? इस बात का उत्तर देते समय जरूर आप जिक्र करें। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि कितने जोन हैं? कुल 36 जोन हैं। जोन में अलग-अलग स्थिति है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, जैसा हमारे साथी ने कहा कि दोनों अलग-अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट हम एक साथ डिसकस कर रहे हैं। उस स्थिति पर अब हमें राज्यवार नहीं बल्कि हमें जिलेवार इसकी कार्य योजना बनानी होगी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

ॲश्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय सभापति महोदय, देश में सूखा और बाढ़ की स्थिति में मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहती हूं। देश में क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं सूखा और कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है । सूखे की स्थिति का सामना करने से कई पूर्व सरकारों ने भी किए । उन्होंने जागरूकता नहीं जताई है जिनके परिणाम देश की जनता भुगत रही है । जब बारिश आती है, वहां उनका जल संचय भी करना चाहिए । गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में सिंचित करना चाहिए । जैसे गुजरात में करीब-करीब ये सारा साल होता है । चैकडेम सबसे ज्यादा वहां है । जिनके कारण उनका लाभ किसानों को मिलता है ।

नदी को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया था लेकिन उसको यूपीए 1, 2 ने बंद किया । अब एनडीए की सरकार ने फिर से ये नदी जोड़ो काम शुरू किया है । देश के किसान और लोगों को फायदा होगा । जहां बाढ़ है वहां का पानी को रोकने के लिए कोई बांध की व्यवस्था नहीं है । हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है, यह सराहनीय है । हमारी सरकार ने कार्य प्रोग्राम बनाए हैं वे सराहनीय हैं ।

* Speech was laid on the Table

***SHRIMATI SANTOSH AHLAWAT (JHUNJHUNU):** The conventional attitude to a drought as a phenomenon of arid and semi-arid areas is changing because even areas with high rainfall often face acute water scarcity. Cheerapunji, the world's highest rainfall area, is facing severe drinking water shortages. Drought in the state of Orissa, with an average rainfall of 1100 mm, surprised many. A water scarcity condition in the Himalayan region is also not uncommon. This shows that drought is just not the scarcity or absence of rainfall, but is more related to water resource management (or mismanagement).

In case of Rajasthan, there have been 48 drought years of varied intensity since 1901. (last 102 years). A more detailed analysis reveals that only in 9 out of 102 years, there were none of the districts in the State affected by droughts. At the village level, the number of drought-free years will be even less. Therefore, every year some part(s) of Rajasthan is affected by drought. Despite this, the State considers drought as a transient phenomenon where short term relief measures are considered to be a solution.

Jhunjhunu district located in the arid western Rajasthan is highly vulnerable to extreme climatic conditions and drought compared to other arid regions of the country. It is characterized by very hot summers and very cold winters with poor rainfall during south-west monsoon period. In May and June, the maximum temperature may sometimes goes upto 49ℜ° C. The potential evapotranspiration rates are quite high, especially during May and June. The total annual potential evapotranspiration is 1502.6 mm. Out of 6463.2 sq. km of cropped are, only 2267.9 sq km (35.1%) area has irrigation facility aggregating drought impact on crop production in the district. Agriculture activity is spread over both Kharif and rabi cultivation. Kharif cultivation is rainfed and rabi cultivation is mostly based on ground water.

The issue of vulnerability to drought and attempts to highlight the need for proper identification of target areas and population for efficient planning of drought relief measures in the state are based more on conventional perceptions, e.g., that Below Poverty Line (BPL) population and population within certain castes are the only vulnerable groups and that the Western region of the State is the most vulnerable.

Rajasthan is the largest State of India with an area of 342,000 sq. km (10.4% of the country total) and population of 56. 5 million (5% of the country total of which 76.6% is rural. The state has only 1% of India's water resources (GOI 2004). Administratively, the State is divided into 32 districts and 241 tehsils.

For historical and geographical reasons, the State remain socially and economically backward. Recurrent drought, a poor resource base for economic development, the highest cost of development per capita due to aridity and very low density of population, low level of literacy (particularly among women), a very rate of population of growth and scarcity and water make the task of socio-economic development a challenge compared to many states in the country. The climate of Rajasthan State varies from arid to sub-humid.

Three main physiographic regions can be delineated in the State. To the west of Aravali hills range, there are 11 districts covering approximately 50% of the area. The climate here is characterized by low and erratic rainfall, extreme of diurnal and annual temperatures, low humidity and high wind velocity. To the east of Aravali, the climate is semi-arid to sub-humid. The 12 districts in this region are characterized by more or less the same extremes in temperatures, relatively lower wind velocity and high humidity with better rainfall. The remaining area falls within the Aravali range with high rainfall, hilly topography and forest cover is classified as a tribal area.

The average rainfall of Rajasthan is 574 mm but it varies significantly across different regions. In the western Rajasthan, the average annual rainfall ranges from less than 100 mm in north-western part of Jaisalmer (lowest in the State) to over 400 mm in Sikar, Jhunjhunu and Pali regions and along the western fringes of the Aravali range.

Drought results from long continued dry weather and / or insufficiency of rain, which causes exhaustion of soil moisture, depletion of underground water supply and reduction of stream flow. Drought is frequently defined according to disciplinary perspective.

The National Commission on Agriculture in India defines three types of droughts, namely, meteorological, agricultural and hydrological droughts. Meteorological drought is defined as a situation when there is significant decrease from normal precipitation over an area (i.e. more than 25%). Agricultural drought occurs when soil moisture and rainfall are inadequate during the growing season to support healthy crop growth to maturity and causes crop stress and wilting. Hydrological drought may be a result of long term meteorological droughts which result in the drying up of reservoirs, lakes, streams and rivers, and fall in groundwater level.

The impact of a drought on the overall economy of the country is evident at macro (State and national level) and micro-levels (village and household levels). The impacts could be direct or indirect and vary in nature and intensity. The extent and intensity of drought impacts is determined by prevailing economic conditions, the structure of the agricultural sector, management of water resources, cereal reserves, internal and external conflicts, etc.

Micro level impact is largely on the entitlement to produce and procure food. The impact varies depending upon the social structure (class, caste) and village and household resource endowments.

The direct impacts of drought can be classified under four broad categories, viz. physical, social, economic and environmental. The initial direct physical effects of drought on the production sectors are similar regardless of the type of economy, although the relative and absolute magnitudes of each impact will depend on specific country characteristics. Drought entails a loss of assets in the form of crop, livestock and productive capital damage as a direct consequence of water shortage or related power cuts. In the industrial sector, agro-based industries are the ones directly affected, as the lower domestic production of agro-processing inputs reduces non-agricultural production.

Domestic availability of water is also restricted. This latter aspect has implications for health and household activities, including the time required for collecting water. As water becomes scarce, competition among within sectors may increase.

Droughts have potentially important implications for government policies, first and foremost, via their impact on the budgetary balance. A drought is likely to reduce tax revenue via a decline in income, employment and exports. On the expenditure side, increased expenditure on relief, social welfare, health and water supplies, consumption-related subsidies on food distribution, and the logistical costs of drought-related imports may confront government. Law and order services could be put under greater pressure by a rise in crime, in turn associated with temporary unemployment, migration and increased destitution. In addition, these are likely to be pressures for the increased provisions of subsidies and credit to affected productive sectors, including public utilities. Government policies can exacerbate the impact of drought.

Due to scanty and inadequate rainfall for the last two years in Rajasthan, the crop has been severely affected. The scarcity problem has been reported in 23406 villages spread in 26 districts and hence on 9.1.2000 these villages were declared as scarcity (drought) affected villages. In all, 26.1 million people and 34.5 million animals are affected. The drought condition is worsening year after year over the last three years.

Vulnerability is another concept to consider in drought impact assessment. It is closely related to food insecurity and can be defined as the probability of an acute decline in food excess or consumption levels below minimum survival needs. In drought years, food insecurity increases due to severe decline in food production/availability, both from individual farms and in the market and because of increased uncertainty of income related to lack of employment opportunities and livelihood. Vulnerability may be assessed in terms of multiple factors/indicators, which expose people to food insecurity through reduced food availability, access and utilization.

Vulnerability indicators are mostly relative and qualitative, and therefore, difficult to quantify. However, some broad indicators can be listed, including forced migration, borrowings, skipping meals or food shortage, change of occupation, forced unemployment, falling health conditions, etc.

Vulnerability assessment may be done for different socio-economic groups based on caste, land ownership, primary occupation, income group and gender. They can be assessed at a state, district, village or households level. It was shown that both low-income and middle-income households are vulnerable to droughts. In a context of farm sizes, it is marginal and small farmers that are normally most vulnerable, whereas in desert region, even the large land holders are vulnerable due to the inferior quality of land with no irrigation facilities and direct dependency on erratic rainfall. Landless households are better off as they are less dependent on agriculture and livestock for their livelihood and more mobile.

Identification of vulnerable population, villages and districts are important for policy makers, particularly the Drought Relief Department, for identification of target population. It also helps in streamlining and planning in advance the activisties of Relief Department.

---

*श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर)ः 34 जिलों में से ज्यादातर जिले सूखे की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है, खासकर अहमदनगर जिला और संपूर्ण मराठवाड़ा क्षेत्र पीने की पानी की गंभीर समस्या से ग्रसित है। जिनमें से अधिकांश गांवों में टेंकरों के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। अहमदनगर जिले में 14 तहसील हैं, उनमें से पाथर्डी, पारणेर, कर्जत, श्रीगोंदा, अहमदनगर, जामखेड़ और शेवगांव बुरी तरह प्रभावित हैं। फसल न होने एवं सूखे की वजह से इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। दूसरी चीज़े सामने आयी हैं। फसलों के दुप्रभावित होने से गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर जो लोग हैं, उन सबकी स्थिति प्रभावित हुयी है और जो लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं वे भी इस समस्या से प्रभावित हुए है। सूखे ने खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है।

पीने के पानी की गंभीर समस्या ने सिर्फ ग्रामीण इलाकों को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि शहरी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि कम मात्रा में पानी होने से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। छोटे शहर जो पूर्ण रूप से भूमिगत पानी पर निर्भर हैं, वे भी पानी की कमी एवं पानी के जल स्तर की गिरावट से दुप्रभावित है।

इन प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रीय राहत कोष से अधिकतम राहत राशि प्रदान की जाए। आपकी यह मदद ग्रसित लोगों को एवं जरूरतमंद लोगों को सूखे की समस्या से जूझने में मदद पहुंचाएगी। आपके इस अनुदान एवं उठाये गये जरूरी कदम के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा।

अतः आपसे निवेदन है कि अकाल से निज़ात दिलाने के लिए जल संधारण को तीव्रता से बढ़ाने की आवश्यक है।

जल संसाधन बढ़ाने हैं तो पहले जो तालाब व बांध बंधे हुए हैं, उनमें गाद का प्रमाण काफी मात्रा में है। इसी वजह से इनमें जलग्रहण क्षमतानुरूप नहीं होता। इसलिए ऐसे बांध व तालाब में से गाद निकाला (De-Silting) जाना चाहिए। इससे जलग्रहण क्षमता बढ़ने के साथ-साथ पीने का पानी तथा सिंचन क्षेत्र का कारोबार बढ़ेगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आर.आर.आर. (रिपेयर, रिस्टोरेशन तथा रिनोवेशन) स्किम के अंतर्गत ऐसा कार्य किया जा रहा है। देश में बहने वाली नदियाँ हज़ारों वर्षों से चल रही हैं उनमें भी गाद का प्रमाण काफी मात्रा में है। महाराष्ट्र राज्य में सुचारू रूप से चल रहे शिरपुर पैटर्न का प्रयोग इन नदियों पर किया जाए तो उनकी वहन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ सिंचन क्षेत्र में भारी मात्रा में सुधार हो जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/ नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे और केन्द्रीय सड़क योजना के अंतर्गत सड़के बनाई जाती हैं। उनके कॉन्ट्रेक्टर को पुराने तालाब व बांध से गाद निकालने को कहा जाये, तो वे गाद से सड़क की साईट पट्टियाँ बन सकती हैं, उससे जमीन कटाव में भी कमी आएगी और सड़कें भी चौड़ी बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए सिर्फ इतना ही करना होगा। सरकार द्वारा गाद पर रॉयल्टी लगायी जाती है, उस पर कॉन्ट्रेक्टर को माफी/रियायत दी जाये ताकि वे आसानी से कार्य करें और यह रियायत कॉन्ट्रेक्टरों को उस क्षेत्र में दी जाये जहां उनका कार्य चल रहा है। उन्हें 1 से 5 कि.मी. क्षेत्र के तालाब/बांध से गाद निकालने की अनुमति

दी जाये।

इस क्षेत्र में मूलभूत ढाँचा बनाने की जरूरत है। हमने अपने जिले में चार गाँवों में ऐसा प्रयोग किया, वहाँ अब अकाल सदृष्य स्थिति में आसानी से पीने का पानी मिल रहा है। उसी के साथ-साथ सिंचाई में भी बढ़ोत्तरी हो गयी है। यह तरीका सब जगह अपनाया जाये तो जल संसाधन क्षेत्र में काफी मात्रा में सुधार हो जायेगा। अतः मेरी सरकार से विनती है कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करके उसे अपनाया जाये। मेरा यह सुझाव है कि देश में जल संसाधन का दायरा बढ़ाने के लिए उक्त प्रस्ताव पर गौर किया जाये जिससे अकाल से राहत मिलने में बड़ा सहयोग होगा।

ऑश्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मैं सूखे से उत्पन्न देश की स्थिति पर चर्चा के दौरान सरकार को अपने बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बुंदेलखण्ड लगातार कई वर्षों से इस समस्या से ग्रस्त है। वहां पर मेरा संसदीय क्षेत्र बाँदा-चित्रकूट तो और पिछले 5 वर्षों से लगातार इन समस्याओं से सामना कर रहा है। इस समय सूखे के कारण आदमियों को एवं जानवरों के लिए पेयजल व्यवस्था आदि गड़बड़ा गई है। मेरे क्षेत्र में पाढा का वह एरिया भी आता है। जहाँ पर कहावत है कि "भौंरा मुझ पर ऐसा रहम कर जाए कि गगरी न फूटे चाहे खसम भर जाए" यानि एक गगरी पानी का इतना पेयजल के लिए महत्व है कि महिला कह रही है कि गगरी (घड़ा) न फूंटे चाहे पति मर जाए। अतः मान्यवर वहाँ पर पेयजल यानी पेयजल योजनाओं की विशेष बजट देकर चिन्ता करना चाहिए। सूखे की राहत के लिए पिछले सालों के केन्द्रीय टीम के सर्वे के अनुसार किसानों को कर्जा माफी होनी चाहिए। उनको जारी बैंक की वसूली एवं आर.सी पर अविलंब लगायी जानी चाहिए। और इसकी घोषणा शीघ्र माननीय मंत्री जी द्वारा इसी बहस के अंदर होनी चाहिए।

* Speech was laid on the Table

ऑडॉ. रामशंकर कठेरिया (आगरा) : मेरा क्षेत्र आगरा है जहां पर पानी की भारी कमी है । वर्षा पर्याप्त न होने के कारण मेरे क्षेत्र की एक तहसील एत्मादपुर की संपूर्ण जमीन का 70 औ आलू फसल केवल वर्ष में एक बार होती है । इस वर्ष वर्षा न होने से आलू किसान चिंतित है । यमुना में पानी नहीं है । आगरा लोक सभा क्षेत्र में खारा पानी है जिसे पीने से बीमारियां हो रही है । पीने को जो यमुना नदी से आगरा शहर में सप्लाई होता है । वह पूरी तरह बंद है । किंतु यमुना नदी सूखी पड़ी है जिससे पूरे शहर में पीने के पानी का भयंकर संकट है । यमुना में पानी न होने का मुख्य कारण यह भी है कि हरियाणा के हथिनी कुण्ड से पानी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा नहीं दिया जाता । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो यमुना में पानी का है वह पूरा मिले जिससे पनी का पानी मिल सके तथा सूखी यमुना से ताजमहल की नींव में लकड़ी है वह सिकुड़ रही है जिससे ताजमहल को खतरा हो गया है ।

हमारी सरकार से प्रार्थना है कि आगरा शहर और एत्मादपुर, जलेसर के सारी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये ।

आगरा में यमुना पर बैराज तथा आगरा से 60 कि.मी. पर चंबल से पीने का पानी लाया जाये । आलू किसानों की विशेष चिंता हो । देश का का 25 औ आलू आगरा क्षेत्र में होता है ।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

18.10 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, August 1, 2014/Shravana 10, 1936 (Saka).

* Speech was laid on the Table

---

* Eदथ्त्द्रण्‌ य्द्बडदथ्डय्त्द्द द्द ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण्‌ द्द्बश्र्त्दडथ्न्र्‌ ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्बड्ढड्ड त्द ख्ठ्ठदददडड्डड.

* Eदथ्त्द्रण्‌ य्द्बडदथ्डय्त्द्द द्द ण्ड्ढ च्द्रड्ढड्ढहण्‌ द्द्बश्र्त्दडथ्न्र्‌ ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्बड्ढड्ड त्द ड्डत्र्थ्.

* ग़्द्दद्य्‌ द्बड्ढहद्द्बड्डड्ढड्ड.

* च्द्रड्ढड्ढहण्‌ ड्डम्र्‌ थ्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्डडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण्‌ ड्डम्र्‌ थ्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्डडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण्‌ ड्डम्र्‌ थ्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्डडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण्‌ ड्डम्र्‌ थ्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्डडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण्‌ ड्डम्र्‌ थ्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्डडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण्‌ ड्डम्र्‌ थ्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्डडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.
* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्न् थ्ड्डत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.